IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

- *Drug Abuse in India*
- *22ND LAW* COMMISSION AND UNIFORM CIVIL CODE
- *India – US Relations*
- *Financial Inclusion in India*
- *Flash Floods in India*
- *Transgenic Crops in India*

TOPPER'S RECOMMENDED
BEST CHOICE

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

Under The Guidance Of Mohan Sir (Founder, IASbaba)

Under The Guidance Of
Mohan Sir
(Founder, IASbaba)

- 78 Prelims Tests
- 95 Mains Tests
- Weekly Assignments Monitored by Mentor
- Performance Tracker
- Module Wise Classes of Choice
- Current Affairs Classes
- Live solving of Prelims PYQ'S by Prelims Experts
- Enhanced Peer Group Activities

Bangalore Delhi
Bhopal Lucknow Online

ADMISSION OPEN

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

राजव्यवस्था और और शासन

- टेली-लॉ कार्यक्रम
- विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना
- मिशन वात्सल्य
- अनुच्छेद 299
- नेक्रोफिलिया (Necrophilia)
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग 2023
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक
- वैभव फ़ेलोशिप कार्यक्रम
- अनुच्छेद 370
- शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक (GRAI) 2022
- स्मार्ट सिटी मिशन

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- सबांग बंदरगाह
- एशियाई विकास बैंक (एडीबी)
- बैंकॉक विज़न 2030
- ईरान और अफगानिस्तान जल संघर्ष
- OPEC+
- शांगरी-ला वार्तालाप
- कोसोवो-सर्बिया संघर्ष
- SAI20 शिखर सम्मेलन
- यूनेस्को
- क्रेडिट लाइनें (एलओसी)
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)
- नोवा कखोव्का बांध
- महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल (iCET)
- ऑर्डर ऑफ द नाइल

अर्थव्यवस्था

- लघु वित्त बैंक
- क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (CIBIL)
- आरबीआई लाइट वेट पेमेंट सिस्टम
- शुल्क-मुक्त कोटा-मुक्त (डीएफक्यूएफ) योजना
- मूल्य समर्थन योजना
- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT)
- प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) धारक
- भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र
- फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (एफएलडीजी) प्रणाली
- संकल्प कार्यक्रम
- विलफुल डिफॉल्टर्स
- चैंपियंस 2.0 पोर्टल

भूगोल

- बैरेंट्स सागर
- नमक की गुफाएँ
- किलाउआ
- बिपरजॉय
- अनैक क्रैकटाऊ (Anak Krakatau) ज्वालामुखी
- न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट
- जेलिफ़िश आकाशगंगा (JO206)
- एन्सेलाडस
- हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र
- विक्टोरिया झील
- महादायी नदी
- भारतीय मौसम विभाग
- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए)

पर्यावरण

- कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
- हिमालयी भूरा भालू
- पेट कोक
- पर्यावरण संबंधी जानकारी, जागरूकता, क्षमता निर्माण एवं आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी)
- मन्नार की खाड़ी
- अमचांग वन्यजीव अभयारण्य
- जमीनी स्तर पर ओजोन प्रदूषण
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (ANERT)
- उत्तरी बंगाल के जंगली ऑर्किड
- एग्री बाय-प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए नए मानक
- कांगो वर्षावन
- ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व
- ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी)
- हिमालय पर्वत

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- फौकॉल्ट पेंडुलम
- चिट्रिडिओमाइकोसिस
- कवच (KAVACH)
- एबॉसीन
- हिग्स बोसॉन

इतिहास, कला एवं संस्कृति

- तेलंगाना की ऊनी गोंगडी शॉल
- आगरा का किला
- पीटरमैरिट्ज़बर्ग रेलवे स्टेशन की घटना
- गिलगित पांडुलिपियाँ
- मालचा महल
- केदारनाथ मंदिर
- रानी दुर्गावती
- खर्ची पूजा

विविध

- रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस)
- अग्नि प्राइम
- महुआ के लड्डू
- फ्रेंच ओपन
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)
- अभ्यास एकुवेरिन
- स्वालबार्ड मिशन
- वैश्विक दासता सूचकांक 2023
- अंजदीप और संशोधक (Anjadip and Sanshodhak)
- जनजातीय खेल महोत्सव
- गांधी शांति पुरस्कार 2021
- भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI)
- आईएनएस कृपाण
- पद्म पुरस्कार
- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)

MAINS

राजव्यवस्था और और शासन

- भारत में नशीली दवाओं का दुरुपयोग
- 22वां विधि आयोग और समान नागरिक संहिता
- भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग और औषधि सुरक्षा

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- भारत-अमेरिका संबंध
- भारत-मिस्र संबंध

अर्थव्यवस्था

- भारत में वित्तीय समावेशन

भूगोल

- आर्कटिक महासागर का 2030 तक बर्फ मुक्त होना
- भारत में आकस्मिक बाढ़

पर्यावरण

- दुनिया भर में झीलों का सिकुड़ना
- भारत में ट्रांसजेनिक फसलें

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- निश्चित खुराक संयोजन (FDCS) प्रतिबंध मुद्दा

विविध

- हिरोशिमा एआई प्रक्रिया
- बालासोर ट्रेन दुर्घटना और भारतीय रेलवे सुरक्षा का मुद्दा

PRACTICE QUESTIONS

ANSWER KEY

PRELIMS

राजव्यवस्था और और शासन

टेली-लॉ कार्यक्रम	**संदर्भ:** हालिया रिपोर्टों के अनुसार, टेली-लॉ कार्यक्रम ने देश भर में 40 लाख लाभार्थियों के साथ एक नई उपलब्धि हासिल की। **टेली-लॉ कार्यक्रम के बारे में:-** • इसे कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से वर्ष 2017 में नागरिकों के लिये कानूनी सहायता को सुलभ बनाने हेतु लॉन्च किया गया था। **(UPSC CSE: टेली-लॉ)** • **मंत्रालय:** कानून और न्याय मंत्रालय • **उद्देश्य:** यह कार्यक्रम एक ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वंचित वर्ग को अधिवक्ताओं के एक पैनल से जोड़ता है। • इसके तहत, जिन वादियों को कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है, उन्हें अधिवक्ताओं से जोड़ने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और टेलीफोन सेवाओं का उपयोग किया जाता है। • इसके अंतर्गत, 'राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण' (SALSA) और 'जन सेवा केंद्रों' (CSC) में तैनात वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह देने की सुविधा प्रदान की जाती है। (यूपीएससी सीएसई: नालसा) • यह सेवा उन लोगों के लिए निःशुल्क है जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं। अन्य सभी के लिए, मामूली शुल्क लिया जाता है। **अवश्य पढ़ें:** नागरिकों का टेली-लॉ मोबाइल ऐप **स्रोत:** AIR
विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "दुनिया के सबसे बड़े अनाज भंडारण" के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी। **इसके बारे में:-** • इस योजना का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण सुविधाओं का निर्माण करना है। • इसमें प्रत्येक ब्लॉक में 2,000 टन की क्षमता वाला एक समर्पित गोदाम होगा। • **उद्देश्य:** देश भर में खाद्यान्नों के भंडारण और वितरण में क्रांति लाना, उनका संरक्षण और उपलब्धता सुनिश्चित करना। • **योजना का पर्यवेक्षण:** यह एक अंतर-मंत्रालयी समिति कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। **योजना के तहत अभिसरण के लिए पहचानी गई योजनाएं:-** • **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय:-** ○ कृषि अवसंरचना निधि (AIF) ○ कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI) ○ एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) ○ कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (SMAM) • **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय:-** ○ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) का औपचारिकीकरण ○ प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY) • उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय:- ○ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का आवंटन ○ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कार्य

लाभ :

- इस योजना का उद्देश्य देश की कृषि भंडारण अवसंरचना की कमी को दूर करने के लिए PACS स्तर पर गोदामों की स्थापना करना है। **(यूपीएससी मेन्स: भारत में कृषि उपज के भंडारण तंत्र का मूल्यांकन करें।)**
- राज्य एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के लिए खरीद केंद्र के रूप में कार्य करना।
- स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता का निर्माण करके, योजना का उद्देश्य अनाज की बर्बादी को कम करना, बेहतर खाद्य सुरक्षा में योगदान देना है।
- यह योजना किसानों को फसलों की संकटकालीन बिक्री को रोकने के विकल्प प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- **लागत में कमी:** PACS स्तर पर भंडारण सुविधाओं की स्थापना से खरीद केंद्रों और उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न की परिवहन लागत में काफी कमी आएगी।

जरूर पढ़ें: निःशुल्क खाद्यान्न योजना

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

मिशन वात्सल्य

संदर्भ: हाल ही में मिशन वात्सल्य के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बाल देखभाल संस्थानों के पदाधिकारियों की एक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी।

मिशन वात्सल्य के बारे में:-

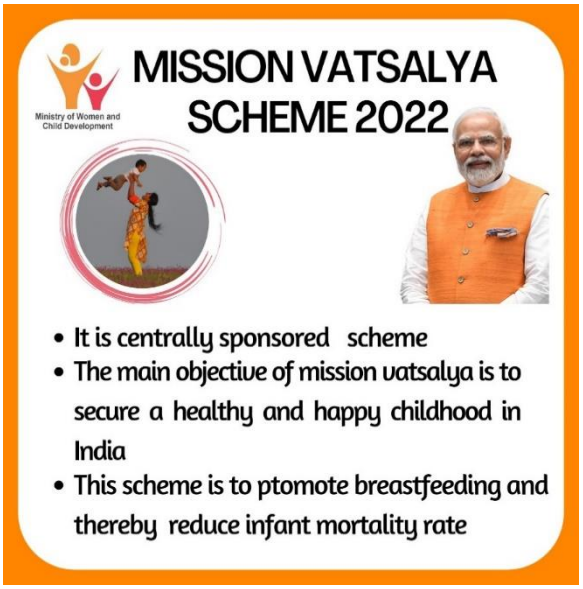

- यह देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक व्यापक योजना है।
- **मंत्रालय:** यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- वर्ष 2009 से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु तीन योजनाओं को लागू किया:
    - देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ बच्चों हेतु किशोर न्याय कार्यक्रम,
    - सड़क पर रहने वाले बच्चों हेतु एकीकृत कार्यक्रम,
    - बाल गृह सहायता योजना।
- वर्ष 2010 में इन्हें एक ही योजना में मिला दिया गया जिसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना के रूप में जाना जाता है।
- वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर "बाल संरक्षण सेवा योजना" कर दिया गया और फिर वर्ष 2021-22 में मिशन

	वात्सल्य के रूप में नामित किया गया। • यह मिशन शक्ति और पोषण 2.0 के साथ योजनाओं की नई तिकड़ी में से एक है। • इसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। **(UPSC MAINS: बालिकाओं के अधिकारों और हितों को बढ़ावा देने के उपाय)** **घटक:-** • सेवा वितरण संरचनाओं को मजबूत करना • संस्थागत देखभाल और सेवाओं को बढ़ाना • गैर-संस्थागत समुदाय-आधारित बाल देखभाल को प्रोत्साहित करना • आपातकालीन पहुँच हेतु सेवाएं • प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण **उद्देश्य:-** • देश के प्रत्येक बच्चे के लिये स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना। • किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अधिदेश को वितरित करने में राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता करने हेतु उन्हें अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने व सभी प्रकार से पालन-पोषण में सहायता करने के अवसर सुनिश्चित करने के लिये सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करना। (यूपीएससी सीएसई: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021) • यह अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के 'संस्थागतकरण के सिद्धांत' के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार-आधारित गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है। **कार्यान्वयन:-** • मिशन के तहत, सरकार निजी क्षेत्र के साथ-साथ स्वयंसेवी समूहों के साथ साझेदारी करने की योजना बना रही है। **अवश्य पढ़ें:** प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) **स्रोत:** पीआईबी
अनुच्छेद 299	**संदर्भ:** हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 299 के तहत राष्ट्रपति के नाम पर एक अनुबंध करते समय प्रतिरक्षा के दावों पर पर निर्णय दिया। **अनुच्छेद 299 के बारे में:-** • अनुच्छेद 298 केंद्र और राज्य सरकारों को व्यापार या व्यवसाय करने, संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और निपटान करने और किसी भी उद्देश्य के लिए अनुबंध करने की शक्ति प्रदान करता है। • अनुच्छेद 299 उस तरीके को चित्रित करता है जिसमें ये अनुबंध संपन्न होते है। • संविधान के अनुच्छेद 299 में प्रावधान है कि "संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए सभी अनुबंध राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा किए गए माने जाएंगे" और ऐसे सभी अनुबंध और "आश्वासन उस शक्ति के प्रयोग में बनाई गई संपत्ति का निष्पादन राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से व्यक्तियों द्वारा उनके द्वारा निर्देशित और अधिकृत तरीके से किया जाएगा।**(यूपीएससी सीएसई: राज्यपाल)** • अनुच्छेद 299 (1) के अनुसार, अनुबंधों को लिखित रूप में व्यक्त किया जाना चाहिये और उनकी ओर से राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिये। • 'चतुर्भुज विट्ठलदास जसानी बनाम मोरेश्वर परशराम एवं अन्य' (1954) के अनुसार, एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके अनुसार सरकार की ओर से कार्य करने वाले एजेंटों द्वारा अनुबंध किया जाना चाहिए; अन्यथा, अनधिकृत या

	अनउपयुक्त अनुबंधों से सार्वजनिक फंड्स ख़त्म हो सकता है। ○ इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 299(1) में दिए गए तरीके का पालन नहीं करने वाले अनुबंधों को किसी भी अनुबंधित पक्ष द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। • अनुच्छेद 299 (2) कहता है कि मुख्य रूप से, न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल को ऐसे अनुबंधों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। **अवश्य पढ़ें:** राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
नेक्रोफिलिया (Necrophilia)	**संदर्भ:** हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पाया कि "नेक्रोफिलिया" लाशों के प्रति एक कामुक आकर्षण है। **नेक्रोफिलिया के बारे में:-** • यह एक मनोवैज्ञानिक विकार है, जिसे डीएसएम-IV के तहत विकारों के एक समूह में वर्गीकृत किया गया है, जिसे "पैराफिलियास" कहा जाता है। • पैराफिलियास: इसमें पीडोफिलिया, प्रदर्शनीवाद और यौन स्वपीड़न (sexual masochism) जैसे विकार शामिल हैं। • नेक्रोफिलिया शारीरिक जरूरत या आदत के बजाय गुस्से, प्रयोग करने की चाहत या वासना का परिणाम हो सकता है। • फिलहाल आईपीसी में नेक्रोफिलिया को एक विशिष्ट अपराध के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। • अदालत ने उल्लेख किया कि अगर कोई अंतिम संस्कार करने के स्थान या मृतकों के अवशेषों के लिये निक्षेप स्थान के रूप में पृथक् रखे गये किसी स्थान में अतिचार करता है तो इसे धारा 297 के तहत "किसी भी मानव शव के अपमान" के रूप में लाया जा सकता है। • **आईपीसी की धारा 297:-** ○ यह जानकारी होना चाहिए कि ऐसे कृत्य से किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत होने की संभावना है या उनके धर्म का अपमान होने की संभावना है, इसे धारा 297 के तहत अपराध माना जाएगा। **रंगाराजू @वाजपेयी बनाम कर्नाटक राज्य" मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला:-** • कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि महिला के शव पर यौन हमला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय बलात्कार का अपराध नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आईपीसी में कोई प्रावधान नहीं है। **(यूपीएससी सीएसई: भारत में रेप और यौन अपराध कानून)** • भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और धारा 377 के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि मृत शरीर को मानव या व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। • इसलिए, यह धारा 376 (बलात्कार के लिए सज़ा) के तहत दंडनीय अपराध नहीं है। • कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृत शरीर पर यौन संबंध बनाना नेक्रोफिलिया के अलावा कुछ नहीं है। • अदालत ने NHRC की 2021 की एडवाइजरी को लागू किया, जिसमें कहा गया है कि शरीर के इलाज में कोई शारीरिक शोषण या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। • इसने केंद्र से कानून में संशोधन करने के लिए भी कहा। **कर्नाटक हाई कोर्ट की केंद्र से सिफारिश:-** • आईपीसी की धारा 377 में संशोधन करना। ○ पुरुष, महिला या जानवर के मृत शरीर को शामिल करना। ○ मृतकों की गरिमा की रक्षा करना। • **नेक्रोफिलिया को अपराध घोषित करना:** इसने एक विकल्प भी पेश किया कि केंद्र नेक्रोफिलिया को अपराध

	घोषित करने के लिए एक अलग दंडात्मक प्रावधान लाए, जिसमें जुर्माने के साथ 10 साल तक की आजीवन कारावास की सजा हो। **परमानंद कटारा, एडवोकेट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1989) मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला:-** • न्यायालय ने इस पर भरोसा किया और माना कि मृत शरीर की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए। • इसने राज्य पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक समान कर्तव्य स्थापित किया कि व्यक्ति को सभ्य दाह संस्कार दिया जाए। • भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी प्राप्त है। **भारत में स्थिति:-** • भारत में नेक्रोफीलिया को दंडित करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। • कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसे आईपीसी की धारा 377 के तहत या नए प्रावधान के रूप में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की। **अवश्य पढ़ें:** वैवाहिक बलात्कार **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	**संदर्भ:** पश्चिम त्रिपुरा में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने हाल ही में डोर-टू-डोर कानूनी सहायता अभियान का आयोजन किया। **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में:-** • कानूनी सेवा प्राधिकरण वैधानिक निकाय हैं जो 1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत भारत के विभिन्न राज्यों में गठित किए गए हैं। • **उद्देश्य:** इस समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता और सेवाएं प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। • इसे कानूनी सहायता कार्यक्रमों और उनकी संरचना की प्रभावी निगरानी प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर आयोजित किया जाता है। • **संबंधित संवैधानिक प्रावधान:** ○ अनुच्छेद 39-A: यह भारत के नागरिकों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान से संबंधित है। ○ यह प्रावधान नागरिकों पर लागू होता है यदि वे कानूनी सेवाओं का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। ○ यह प्रतिवादी को कानूनी पहलुओं में उसके लिए कार्य करने के लिए एक वकील नियुक्त करके भी मदद करता है। **DLSA की संरचना:-** • राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इसका गठन करती है। (यूपीएससी सीएसई: न्यायिक नियुक्तियाँ) • **अध्यक्ष:** जिला न्यायाधीश • अन्य सदस्यों के पास राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुभव और योग्यता होनी चाहिए। • सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इन सदस्यों को नामांकित कर सकती है। ○ नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति राज्य न्यायिक सेवा से संबंधित होगा जो जिला न्यायपालिका के सचिव के रूप में जिला न्यायपालिका की सीट पर तैनात एक अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल जज के रैंक से कम नहीं होगा। ○ संबंधित जिले का सहायक आयुक्त जिला प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। ○ जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वेतन और भत्तों के हकदार हैं और सेवाओं की ऐसी

	अन्य शर्तों के अधीन भी होंगे जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से निर्धारित करती हैं। **विभिन्न स्तरों पर कानूनी सेवा संस्थान:-** 1987 का कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित की स्थापना का आदेश देता है; **राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)** • NALSA की स्थापना 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। • **उद्देश्य:** कानूनी सहायता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा करना तथा अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नियम और सिद्धांत विकसित करना। • **संरक्षक-प्रमुख:** भारत के मुख्य न्यायाधीश • यह राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों और गैर-लाभकारी संगठनों को कानूनी सहायता प्रणालियों तथा पहलों को निष्पादित करने में मदद करने के लिए धन और अनुदान वितरित करता है। **राज्य स्तर: राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण** • **संरक्षक-प्रमुख:** राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश **जिला स्तर पर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण** • **पदेन अध्यक्ष:** जिले के जिला न्यायाधीश **तालुका/उप-विभागीय स्तर पर:** तालुका/उप-विभागीय कानूनी सेवा समिति • एक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश इसका प्रमुख होता है। **न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज)** • न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) की प्राथमिक पहल देश भर में मुफ्त कानूनी सेवाओं को जरुरतमन्द तक पहुंचाने के लिए एक ढांचा स्थापित करना है। • न्याय बंधु के तहत, प्रैक्टिस करने वाले वकील, जो अपना समय और अपनी सेवाओं को स्वेच्छा से देने के इच्छुक हैं, मोबाइल के माध्यम से हाशिये के लाभार्थियों के साथ जुड़े हुए हैं। • न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन (एंड्रॉइड/आईओएस) को तकनीकी भागीदार सीएससी ई-गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उमंग प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। • UMANG (न्यू-एज गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) द्वारा विकसित किया गया है। **अवश्य पढ़ें:** न्यायिक जवाबदेही **स्रोत:** पीआईबी
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग 2023	**संदर्भ:** हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) द्वारा वर्ष 2023 के लिये रैंकिंग की घोषणा की गई। **इसके बारे में:-**

Name	City	State	Rank
Indian Institute of Technology Madras	Chennai	Tamil Nadu	1
Indian Institute of Science	Bengaluru	Karnataka	2
Indian Institute of Technology Delhi	New Delhi	Delhi	3
Indian Institute of Technology Bombay	Mumbai	Maharashtra	4
Indian Institute of Technology Kanpur	Kanpur	Uttar Pradesh	5
All India Institute of Medical Sciences, Delhi	New Delhi	Delhi	6
Indian Institute of Technology Kharagpur	Kharagpur	West Bengal	7
Indian Institute of Technology Roorkee	Roorkee	Uttarakhand	8
Indian Institute of Technology Guwahati	Guwahati	Assam	9
Jawaharlal Nehru University	New Delhi	Delhi	10
Banaras Hindu University	Varanasi	Uttar Pradesh	11
Jamia Millia Islamia-New Delhi	New Delhi	Delhi	12
Jadavpur University	Kolkata	West Bengal	13
Indian Institute of Technology Hyderabad	Hyderabad	Telangana	14
Amrita Vishwa Vidyapeetham	Coimbatore	Tamil Nadu	15
Manipal Academy of Higher Education-Manipal	Manipal	Karnataka	16
Vellore Institute of Technology	Vellore	Tamil Nadu	17
Anna University	Chennai	Tamil Nadu	18
Aligarh Muslim University	Aligarh	Uttar Pradesh	19
University of Hyderabad	Hyderabad	Telangana	20

IMAGE SOURCE: findhow.net

- NIRF विभिन्न मापदंडों के आधार पर देश भर के संस्थानों को रैंक करने की एक पद्धति है।
- **मंत्रालय:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)
- **उद्देश्य:** विश्वविद्यालयों को विभिन्न रैंकिंग मापदंडों पर अपने प्रदर्शन में सुधार करने और अनुसंधान तथा सुधार के क्षेत्रों में अंतराल की पहचान करने में मदद करना।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों, इंजीनियरिंग संस्थानों, प्रबंधन संस्थानों, फार्मेसी संस्थानों और वास्तुकला संस्थानों जैसे उनके संचालन के क्षेत्रों के आधार पर विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए अलग-अलग रैंकिंग हैं।
- NIRF में पहचाने गए मापदंडों की पांच व्यापक श्रेणियां: शिक्षण, सीखना और संसाधन (टीएलआर); अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास; स्नातक परिणाम; आउटरीच; और समावेशिता और धारणा।

एनआईआरएफ 2023 के मुख्य निष्कर्ष:-

- **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास:** समग्र श्रेणी और इंजीनियरिंग में अपना पहला स्थान बरकरार रखा।
- **भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु:** विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष पर और अनुसंधान संस्थान श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा।
- **आईआईएम अहमदाबाद:** भारतीय प्रबंधन संस्थान (Indian Institute of Management- IIM), अहमदाबाद ने भारत में अग्रणी प्रबंधन संस्थान के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली:** मेडिकल में शीर्ष स्थान।
- **नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु:** ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।
- **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर है।
- भारतीय रैंकिंग के वर्ष 2023 संस्करण के तीन विशिष्ट पहलू:-
    - कृषि और संबद्ध क्षेत्र नामक एक नए विषय की शुरुआत। **(यूपीएससी सीएसई: कृषि सुधार)**
    - दो भिन्न-भिन्न अभिकरणों को समान डेटा प्रदान करने के संस्थानों के बोझ को कम करने के लिये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स (ARIIA) द्वारा पूर्व में निष्पादित "इनोवेशन/नवाचार" रैंकिंग का भारतीय रैंकिंग में एकीकरण।

	○ शहरी और नगरीय प्लानिंग में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को शामिल करने के लिये "वास्तु-कला" के दायरे का "वास्तुकला और योजना" तक विस्तार। **(यूपीएससी सीएसई: भारतीय शहरों का रूपांतरण)** • इनके जुड़ने से, इंडिया रैंकिंग का मौजूदा पोर्टफोलियो 13 श्रेणियों और विषय डोमेन तक बढ़ गया है जिन्हें इंडिया रैंकिंग 2023 में स्थान दिया गया है। • वर्ष 2023 की रैंकिंग अभ्यास में विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, डिग्री कॉलेजों के लिये एक सामान्य "समग्र" रैंक प्रदान करना। • यह 8 विषय डोमेन को रैंक करता है: इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला और योजना, चिकित्सा, कानून, दंत चिकित्सा कृषि और संबद्ध क्षेत्र। **अवश्य पढ़ें:** शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक	**संदर्भ:** केरल ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। **इसके बारे में:-** • पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2018-19 में प्रकाशित किया गया था। • इसकी घोषणा 7 जून 2019 को पहले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर की गई थी। • विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) संयुक्त रूप से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। **(यूपीएससी सीएसई: डब्ल्यूएचओ)** • **खाद्य सुरक्षा सूचकांक का उद्देश्य:** देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाना। • **द्वारा विकसित:** FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) **(UPSC CSE: FSSAI)** • मापदंडों में मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण - बुनियादी ढांचा और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण शामिल हैं। **(यूपीएससी सीएसई: खाद्य सुरक्षा)** • राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रवर्तन गतिविधियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ○ इनमें खाद्य सुरक्षा जांच, नमूना संग्रह, नमूना जांच अभियोजन मामले, राज्य में एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं की संख्या आदि शामिल हैं। **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)** • यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS अधिनियम) के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। • **मंत्रालय:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय • **मुख्यालय:** दिल्ली • FSSAI खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और प्रचार के लिए जिम्मेदार है। • **संरचना:** FSSAI में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य शामिल हैं। इसमें एक तिहाई सदस्य महिलाएं होती है। • केंद्र सरकार FSSAI के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है।

	अवश्य पढ़ें: FSSAI ने पैकेज्ड फूड के लिए स्टार रेटिंग पर मसौदा अधिसूचना जारी की। **स्रोत:** द हिंदू
वैभव फ़ेलोशिप कार्यक्रम	**संदर्भ:** हाल ही में, सरकार ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (VAIBHAV) फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। **इस कार्यक्रम के बारे में:-** • यह फेलोशिप कार्यक्रम भारत में भारतीय डायस्पोरा वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देना है। • **आरंभ तिथि:** 15 जून 2023 • **कार्यान्वयन एजेंसी:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। • **उद्देश्य:** सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय STEMM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) डायस्पोरा भारतीयों को भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से जोड़ना, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में ज्ञान, बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा किया जा सके। **कार्यान्वयन:-** • इस कार्यक्रम के तहत, 75 चयनित फ़ेलो को 18 पहचाने गए ज्ञान क्षेत्रों में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। • 18 कार्यक्षेत्रों में क्वांटम प्रौद्योगिकी, हेल्थ, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान और सामग्री विज्ञान शामिल हैं। **पात्रता:-** • आवेदक एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) और भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) होना चाहिए, जो वर्तमान में विदेश में रह रहा हो। • आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Ph.D./M.D/M.S की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। • आवेदक को शीर्ष 500 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में काम करने वाले अनुसंधान और विकास के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक विदेशी शैक्षणिक / अनुसंधान / औद्योगिक संगठन में कार्यरत शोधकर्ता होना चाहिए। • **पात्रता (संस्थानों के लिए):** उच्च शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय NIRF की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 200 में हों और उनके पास NAAC 'ए' ग्रेड (3.0 और ऊपर) और वैज्ञानिक संस्थान हों। **फंडिंग:-** • फ़ेलोशिप में फ़ेलोशिप अनुदान (INR 4,00,000 प्रति माह), अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रा, आवास और आकस्मिक खर्च शामिल होंगे। **SOURCE: PIB**
अनुच्छेद 370	**संदर्भ:** गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के विकास में एक बड़ी बाधा थी। उन्होंने आगे दावा किया कि इसके निरस्त होने से संघ के साथ जम्मू-कश्मीर का पूर्ण एकीकरण और क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हुआ है। **अनुच्छेद 370 के बारे में:-**

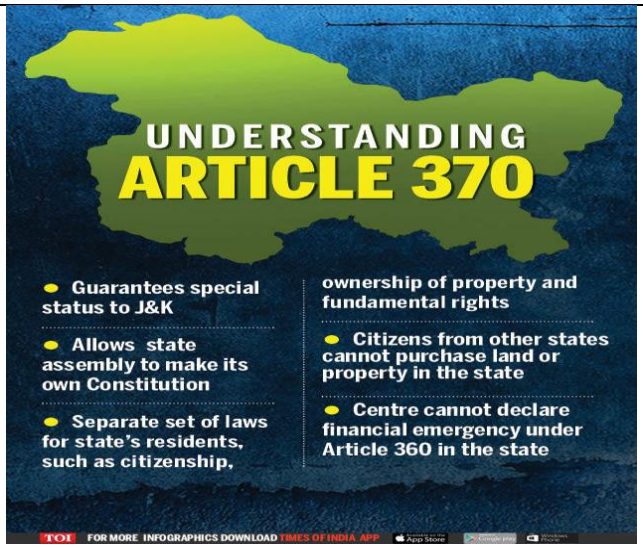

IMAGE SOURCE: blogspot.com

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को कुछ विशेष शक्तियों के प्रावधान से संबंधित है।
- यह जम्मू और कश्मीर (J&K) राज्य को एक 'अस्थायी' स्वायत्त दर्जा प्रदान करता है।
- यह अनुच्छेद आज़ादी के बाद कश्मीर के भारत में विलय का परिणाम था।

इतिहास पृष्ठभूमि:-

- स्वतंत्रता के बाद, जम्मू और कश्मीर (J&K) कुछ विशेष प्रावधानों के साथ 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत के डोमिनियन में शामिल हो गया।
- इसी तर्ज पर 1949 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया।
- इसे जम्मू और कश्मीर राज्य को कुछ छूट देते हुए एक 'अस्थायी प्रावधान' के रूप में जोड़ा गया था। **(यूपीएससी सीएसई: जम्मू और कश्मीर: मीडिया की भूमिका)**

अनुच्छेद 370 के प्रावधान:-

- अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को अपना संविधान बनाने की अनुमति दी।
- इसने राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को और सीमित कर दिया।
- रक्षा, विदेशी मामलों के वित्त और संचार को छोड़कर, भारत सरकार को अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी।
- केंद्र सरकार के पास राज्य में वित्तीय आपातकाल लगाने की कोई शक्ति नहीं थी।
- आपातकाल केवल आंतरिक अशांति और विदेशी शत्रु से आसन्न खतरे के आधार पर ही लगाया जा सकता था।
- अन्य राज्यों से संबंधित भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर राज्य में जमीन या संपत्ति नहीं खरीद सकते थे।
- जो महिला किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी, वह स्वामित्व का अधिकार खो देती थी।
- इन प्रावधानों ने राज्य सरकार को यह नियंत्रण दिया कि उसे केंद्र सरकार की सहमति की चिंता किए बिना राज्य पर शासन कैसे करना है।

धारा 370 हटाना

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने 5 अगस्त, 2019 को संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए कार्यान्वयन) आदेश, 2019 जारी किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर को पहले से सहमत विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया।
- जम्मू-कश्मीर का अब अपना संविधान, झंडा या राष्ट्रगान नहीं है।

	• अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के परिणामस्वरूप इसकी आबादी के पास अब दोहरी नागरिकता नहीं है। • जम्मू और कश्मीर अब सूचना का अधिकार अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम सहित संसद द्वारा किए गए सभी विधायी संशोधनों का पालन करता है। • जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से भारतीय संविधान और सभी 890 केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत आता है। **अवश्य पढ़ें:** जम्मू और कश्मीर नेट प्रतिबंधों के लिए न्यायिक उपाय **स्रोत:** AIR
शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक (GRAI) 2022	**संदर्भ:** शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक (GRAI) 2022 हाल ही में लॉन्च किया गया था। **शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक (GRAI) 2022 के बारे में:-** • **बनाया गया:** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार। **(यूपीएससी सीएसई: वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र)** • **उद्देश्य:** संगठन-वाइज तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत करना और शिकायत निवारण तंत्र की शक्तियों और सुधार के क्षेत्रों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना। • 89 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों का निम्नलिखित आयामों में एक व्यापक सूचकांक के आधार पर मूल्यांकन और रैंकिंग की गई: - ○ दक्षता ○ प्रतिक्रिया ○ डोमेन और ○ संगठनात्मक प्रतिबद्धता और संबंधित 12 संकेतक। • इस उद्देश्य के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) का उपयोग किया गया था। **मुख्य निष्कर्ष:-** • केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए औसत निपटान समय में लगभग 50% की गिरावट आई है, जो 2021 में 32 दिन से घटकर 2023 में 18 दिन हो गई है। • अकेले मई, 2023 की प्रगति में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,16,734 शिकायतों का निवारण किया गया, जिसमें प्रति शिकायत 16 दिनों का औसत निपटान समय था। • निपटाए गए लोक शिकायत मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जो कई बार प्रति माह 1 लाख मामलों को पार कर गई है। • 10-चरणीय CPGRAMS सुधारों को अपनाने से शिकायत निपटान के औसत समय में उल्लेखनीय कमी आई। ○ इन सुधारों ने शिकायत निवारण प्रक्रिया की दक्षता, जवाबदेही और पहुंच को बढ़ाया है। **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)** • CPGRAMS एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित अपनी शिकायतें सार्वजनिक अधिकारियों के पास दर्ज करने की अनुमति देता है। • **द्वारा विकसित:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय [MeitY]), लोक शिकायत निदेशालय (DPG) और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)। • **लॉन्च किया गया:** कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी)। • यह नागरिकों के उपयोग के लिए 24×7 उपलब्ध है। • यह एक एकल पोर्टल के रूप में कार्य करता है जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ राज्य

	सरकारों से भी जुड़ा हुआ है। • यह नागरिकों और सरकार के बीच निर्बाध संचार और शिकायत निवारण को सक्षम बनाता है। • प्रत्येक मंत्रालय और राज्य के पास CPGRAMS तक भूमिका-आधारित पहुंच है, जिससे उन्हें जिम्मेदारी के अपने क्षेत्रों में शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और हल करने की अनुमति मिलती है। • यह मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी नागरिकों के लिए सुलभ है। • CPGRAMS में दर्ज की गई शिकायत की स्थिति को शिकायतकर्ता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई विशिष्ट पंजीकरण आईडी से ट्रैक किया जा सकता है। • CPGRAMS नागरिकों को अपील की सुविधा भी प्रदान करता है यदि वे शिकायत अधिकारी के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं। • **अपील की प्रक्रिया:-** ○ शिकायत बंद होने के बाद यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह फीडबैक दे सकता है। ○ यदि रेटिंग 'खराब' है तो अपील दायर करने का विकल्प सक्षम है। ○ याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत पंजीकरण संख्या से अपील की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। **अवश्य पढ़ें:** शिकायत अपीलीय समितियाँ (GAC) **स्रोत:** PIB
स्मार्ट सिटी मिशन	**संदर्भ:** केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति की सराहना की। **पृष्ठभूमि:-** • स्मार्ट सिटी मिशन ने हाल ही में आठ साल पूरे कर लिए हैं। • केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट सिटी मिशन की उपलब्धियों की सराहना की। **स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में:-** • इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया। (यूपीएससी सीएसई: स्मार्ट सिटी मिशन @ 100) • **मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। • स्मार्ट सिटीज़ मिशन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA), और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) सरकारों का एक संयुक्त प्रयास है। • यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार की एक अभिनव और नई पहल है। **स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य:-** • ऐसे शहरों को बढ़ावा देना जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को जीवन की सभ्य गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण तथा स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। • इसमें शहर के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत स्तंभों पर व्यापक कार्य के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। • इसमें प्रतिकृति मॉडल के निर्माण के माध्यम से टिकाऊ और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। **वित्त पोषित :-** • स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। • केंद्र सरकार मिशन को पांच वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देती है यानी प्रति वर्ष प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रुपये। • एक समान राशि, एक मेल के आधार पर, राज्य / यूएलबी द्वारा योगदान किया जाएगा। **कार्यान्वयन:-**

- शहर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा किया जाएगा।
- **SPV:** यह एक विशेष प्रयोजन वाहन, जिसे विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीई) भी कहा जाता है, वित्तीय जोखिम को अलग करने के लिए मूल कंपनी द्वारा बनाई गई एक सहायक कंपनी है।
    - SPV को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा 50% इक्विटी शेयरधारिता के साथ बढ़ावा दिया जाता है।
    - एक सीमित कंपनी के रूप में गठित SPV कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा शासित होती है।
- **अवधि:-**
    - मिशन को 100 शहरों को कवर करना था और इसकी अवधि पांच वर्ष (FY2015-16 से FY2019-20) होगी।
    - इसे 2019-20 तक पूरा करने का लक्ष्य था लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया है।
- **र्ट सिटी की परिकल्पना चार स्तंभों पर की गई है:-**
- सामाजिक अवसंरचना
- भौतिक मूलढ़ांचा
- संस्थागत बुनियादी ढाँचा (शासन सहित)
- आर्थिक अवसंरचना

अवश्य पढ़ें: स्मार्ट शहर और अकादमी टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च (SAAR)

स्रोत: AIR

अंतरराष्ट्रीय संबंध

सबांग बंदरगाह	**संदर्भ:** भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में इंडोनेशिया के आसेह प्रांत में स्थित सबांग बंदरगाह (Sabang Port) के विकास पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन (joint feasibility study) पूरा किया है। **सबांग बंदरगाह के बारे में:-** • सबांग बंदरगाह इंडोनेशिया के आचे प्रांत में स्थित है। **(यूपीएससी मेन्स: भारत-इंडोनेशिया संबंध)** • यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगभग 700 किमी दूर है। • सबांग मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर है। • **मलक्का जलडमरूमध्य:** इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच समुद्र का एक संकीर्ण विस्तार है । • इसे एक प्रमुख वैश्विक चोक पॉइंट माना जाता है। • इस महत्वपूर्ण बंदरगाह के सफल विकास से भारत को मलक्का जलडमरूमध्य तक पहुंच आसान हो जाएगी। • यह हिंद महासागर में चीन के मुकाबले भारत की सैन्य स्थिति को मजबूत कर सकता है। • वर्ष 2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान: -दोनों देशों ने अंडमान और निकोबार द्वीप तथा इंडोनेशिया के आचे प्रांत के बीच कनेक्टिविटी में सहयोग करने का निर्णय लिया था। • सबांग के आसपास बंदरगाह से संबंधित बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शुरू करने के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। **(यूपीएससी सीएसई: इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन)** **अवश्य पढ़ें:** भारत-प्रशांत संबंध **स्रोत:** THE MINT
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	**संदर्भ :** हाल ही में, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कहा कि वह भारत के शहरी-केंद्रित प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं में योगदान देगा। **एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बारे में:-** 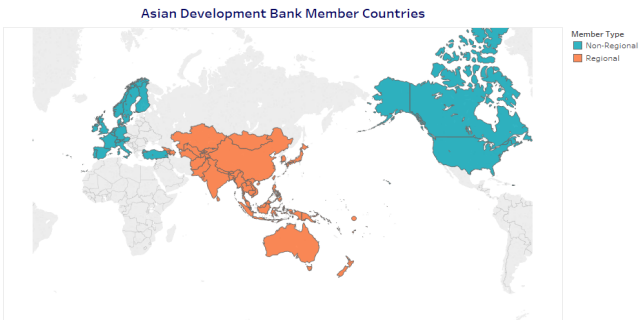 **IMAGE SOURCE: CORPORATEFINANCEINSTITUTE.COM**

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। **(यूपीएससी मेन्स: विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बीच अंतर)**
- इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
- **प्रथम अध्यक्ष:** ताकेशी वतनबे
- **मुख्यालय:** मनीला, फिलीपींस
- **उद्देश्य:** एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। **(यूपीएससी सीएसई: बहु-किश्त वित्तपोषण सुविधा)**
- **सदस्यता:-**
    - बैंक एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) और गैर-क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को स्वीकारता है।
    - वर्ष 1966 में अपनी स्थापना के समय 31 सदस्यों से, ADB बढ़कर 68 सदस्यों तक पहुँच गया है।
    - इनमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हैं।
- **शेयरधारक:** जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रत्येक के पास कुल शेयरों का 15.6%), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%), और ऑस्ट्रेलिया (5.8%)।
- **मतदान अधिकार:** वोट सदस्यों की पूंजी सदस्यता के अनुपात में वितरित किए जाते हैं।
- एडीबी आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है।
- **भूमिकाएँ और कार्य:-**
    - यह समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है।
- **प्रमुख प्रकाशन:-**
    - एडीबी वार्षिक रिपोर्ट 2022
    - एशियाई विकास आउटलुक अप्रैल 2023
    - एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट 2023: एशिया और प्रशांत में व्यापार, निवेश और जलवायु परिवर्तन
    - एशिया और प्रशांत 2022 के लिए प्रमुख संकेतक

भारत और एडीबी

- भारत ADB का संस्थापक सदस्य है।
- भारत बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है।
- एडीबी परिचालन निजी क्षेत्र के विकास, लिंग सशक्तिकरण, क्षेत्रीय एकीकरण, ज्ञान समाधान और क्षमता विकास को बढ़ावा देता है।
- यह एडीबी की रणनीति 2030 और आगामी देश साझेदारी रणनीति, 2023-2027 के अनुरूप मजबूत, जलवायु लचीले और समावेशी विकास के लिए भारत की प्राथमिकताओं का समर्थन करता है।

भारत में एडीबी परियोजनाएं:-

- विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (भाग 2)
- हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना
- न्हावा शेवा कंटेनर टर्मिनल फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट
- दक्षिण एशिया में व्यावसायिक उच्च विद्यालयों को सुदृढ़ बनाना
- ओलम वैश्विक कृषि खाद्य सुरक्षा सहायता परियोजना
- पारगमन-उन्मुख विकास के माध्यम से बेंगलुरु की जीवंतता में सुधार

- **प्रस्तावित परियोजनाएं:-**
    - राज्य सड़क सुरक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम

	○ मणिपुर राज्य सड़क कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम ○ नासिक मेट्रो नियो परियोजना ○ त्रिपुरा में सड़क क्षेत्र का विकास ○ आपदा जोखिम बीमा को बढ़ावा देना **अवश्य पढ़ें:** भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच ऋण समझौता
बैंकॉक विज़न 2030	**संदर्भ:** इस साल के अंत में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) शिखर सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया जाएगा, जैसा कि हाल ही में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने घोषणा की है। **बैंकॉक विज़न 2030 के बारे में:-** ● बैंकॉक विजन 2030 थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ● **उद्देश्य:** स्थायी और संतुलित विकास को बढ़ावा देते हुए बिम्सटेक को एक समृद्ध, लचीले और खुले क्षेत्र की ओर प्रेरित करना। **(यूपीएससी सीएसई: बिम्सटेक)** ● **विज़न:** बिम्सटेक को एक समृद्ध, लचीले और खुले क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ाना। ● यह क्षेत्रीय और वैश्विक आर्किटेक्चर (architecture) में तेजी से हो रहे बदलावों को अपनाते हुए स्थायी और संतुलित विकास पर बल देता है। ● इसका उद्देश्य शांति, स्थिरता और आर्थिक स्थिरता के क्षेत्र के रूप में बिम्सटेक को और बढ़ावा देना है। ● लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों और थाईलैंड के बायो -सर्कुलर -ग्रीन आर्थिक मॉडल के अनुरूप हैं। ● बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) शिखर सम्मेलन ● यह एक क्षेत्रीय संगठन है। ● **उद्देश्य:** उप-क्षेत्र के तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना। ● **स्थापना:** 1997, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर द्वारा। ● **सदस्य देश:** बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ● शुरू में, इसका गठन चार सदस्य राष्ट्रों के साथ 'BIST-EC' (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के संक्षिप्त नाम के साथ किया गया था। 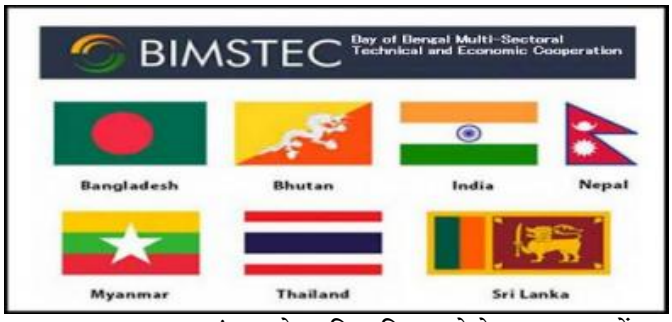 ○ म्यांमार को शामिल किए जाने के बाद 1997 में इसका नाम बदलकर 'BIMST-EC' कर दिया गया। ○ वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के आने के साथ, समूह का नाम बदलकर 'बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल' (बिम्सटेक) कर दिया गया। ● **बिम्सटेक की अध्यक्षता:** सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णमाला क्रम के अनुसार इसकी अध्यक्षता रोटेट होती है। ● वर्तमान अध्यक्ष: थाईलैंड ● सचिवालय: ढाका, बांग्लादेश ○ इसकी स्थापना तीसरे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (2014) के दौरान की गई थी। **अवश्य पढ़ें:** कोलंबो शिखर सम्मेलन के बाद बिम्सटेक **स्रोत:** द हिंदू

ईरान और अफगानिस्तान जल संघर्ष

संदर्भ: ईरान और अफगानिस्तान के जल संघर्ष का लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा हाल ही में सीमा पर झड़पों के कारण फिर से उजागर हुआ।

इसके बारे में:-

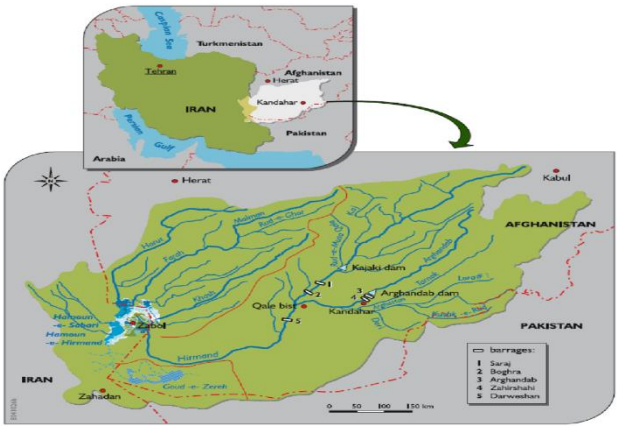

IMAGE SOURCE: ResearchGate

पृष्ठभूमि:-

- अफगानिस्तान और ईरान ने 1973 में हेलमंद नदी संधि पर हस्ताक्षर किये थे।
- **उद्देश्य:** नदी जल के आवंटन को विनियमित करना।
- हालाँकि, समझौते को न तो अनुमोदित किया गया और न ही पूरी तरह से लागू किया गया, जिससे असहमति और तनाव बना रहा।
- **असहमति:-**
    - **ईरान ने अफगानिस्तान पर जल अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया:** ईरान ने लगातार अफगानिस्तान पर अपने जल अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाता रहा है, यह दावा करते हुए कि उसे 1973 की संधि में सहमति से पानी काफी कम मिलता है।
    - **अफगानिस्तान कम जल प्रवाह के लिए जलवायु कारकों को जिम्मेदार मानता है:** अफगानिस्तान ने ईरान के आरोपों का खंडन किया है, उसने कम वर्षा और कम नदी जल मात्रा जैसे जलवायु कारकों को वर्तमान स्थिति का प्राथमिक कारण बताया।
    - **अफगानिस्तान के बांध और सिंचाई परियोजनाओं पर चिंता:** ईरान अफगानिस्तान द्वारा हेलमंद नदी के किनारे बांधों, जलाशयों और सिंचाई प्रणालियों के निर्माण पर चिंता व्यक्त की, उसे डर है कि ये पहल ईरान में जल प्रवाह को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

वर्तमान स्थिति:-

- **पानी की कमी और अन्य समस्याएं:** ईरान का सिस्तान-बलूचिस्तान क्षेत्र पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहा है, जो ईरान के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक में आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों में योगदान दे रहा है।
- **एक जांच आयोग का गठन:** हालिया सीमा संघर्ष को चिन्हित करने के लिए, ईरान और अफगानिस्तान घटना की जांच के लिए एक जांच आयोग स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।
- **आंतरिक समस्याओं पर अल्पकालिक दृष्टिकोण:** ईरान और तालिबान दोनों अल्पकालिक समाधानों को प्राथमिकता दे रहे हैं और जल विवाद को सक्रिय रूप से हल करने के बजाय आंतरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
    - ईरान और तालिबान दोनों ही क्षेत्र में जल संसाधनों के कुप्रबंधन और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में बहुत कम रुचि दिखाते हैं।

हिरमंड/हेलमंद नदी

- हेलमंद अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है।
- **उत्पत्ति:** पश्चिमी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में काबुल (अफगानिस्तान) के पास। **(यूपीएससी सीएसई: भारत-अफगानिस्तान)**

	• **जल निकासी:** यह रेगिस्तानी क्षेत्रों से होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती है।
	• यह हामुन झील में गिरती है, जो अफगानिस्तान-ईरान सीमा तक फैली हुई है।
	  ○ हामुन झील ईरान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। **(यूपीएससी सीएसई: चाबहार बंदरगाह)**
	  ○ सूखे और बांधों के निर्माण जैसे कारकों के कारण इसके जल स्तर में भारी गिरावट देखी गई है।
	  ○ **आर्थिक महत्व:** हामुन झील आसपास के क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों, आजीविका और आर्थिक क्षेत्रों का समर्थन करती है।
	अवश्य पढ़ें: भारत, ईरान और अफगानिस्तान
	स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

OPEC+	**संदर्भ:** ओपेक+ ने हाल ही में एक नए तेल उत्पादन सौदे पर सहमति व्यक्त की है। **इसके बारे में:-** 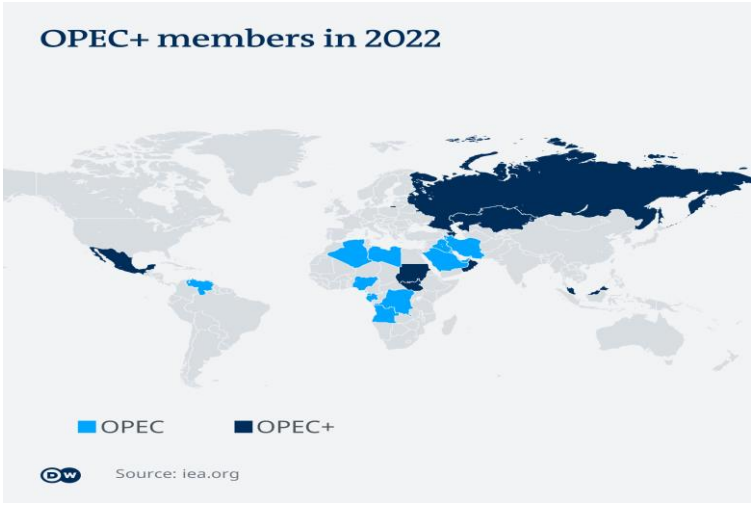 **IMAGE SOURCE:** watchers. ie **पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक)** • यह एक स्थायी, अंतरसरकारी संगठन है। • इसे 1960 में बगदाद सम्मेलन में बनाया गया था। • संस्थापक सदस्य: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला। • **उद्देश्य:** विश्व बाजार में तेल की कीमत निर्धारित करने के प्रयास में तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना, ताकि उतार-चढ़ाव से बचा जा सके जो उत्पादक और क्रय दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। • **मुख्यालय:** वियना, ऑस्ट्रिया • **सदस्यता:** ओपेक की सदस्यता किसी भी ऐसे देश के लिए खुली है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक हो और संगठन के आदर्शों को साझा करता हो। ○ इसमें 14 सदस्य शामिल हैं: सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेज़ुएला (1960), कतर (1961), इंडोनेशिया (1962), लीबिया (1962), अबू धाबी (1967), अल्जीरिया (1969), नाइजीरिया (1971), इक्वाडोर (1973), अंगोला (2007), इक्वेटोरियल गिनी (2017), और कांगो गणराज्य (2018)। • ओपेक के 14 सदस्य वैश्विक तेल आपूर्ति का 35 प्रतिशत और प्रमाणित भंडार का 82 प्रतिशत नियंत्रित करते हैं। • 10 गैर-ओपेक देशों, जिनमें रूस, मैक्सिको और कजाकिस्तान प्रमुख हैं, के जुड़ने से ये हिस्सेदारी क्रमशः 55 प्रतिशत और 90 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। (यूपीएससी सीएसई: ओपेक) **ओपेक+** • ओपेक+ में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) और उसके सहयोगी शामिल हैं। • ओपेक+ दुनिया का लगभग 40% कच्चा तेल पंप करता है। • ओपेक+ देशों में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और

	सूडान शामिल हैं। **अवश्य पढ़ें:** आपातकालीन स्थिति के लिए तेल **स्रोत:** द इकोनॉमिक टाइम्स
शांगरी-ला वार्तालाप	**संदर्भ:** शांगरी-ला डायलॉग का 20वां संस्करण हाल ही में सिंगापुर में संपन्न हुआ। **इसके बारे में:-** • यह एक अंतर-सरकारी सुरक्षा मंच है। • यह मूल रूप से एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जिसे 2002 में एक ऐसे मंच की स्पष्ट आवश्यकता के जवाब में शुरू किया गया था जहां एशिया-प्रशांत रक्षा मंत्री विश्वास पैदा करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वार्तालाप में शामिल हो सकें। • एक " ट्रैक वन " अंतर-सरकारी सुरक्षा सम्मेलन है। • यह वर्ष 2002 से हर साल सिंगापुर में आयोजित किया जाता है। • **द्वारा आयोजित:** इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS)। • IISS लंदन स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। • रक्षा मंत्री, मंत्रालयों के स्थायी प्रमुख और 28 एशिया-प्रशांत राष्ट्रों के सैन्य प्रमुख इसमें भाग लेते हैं। • मंत्री क्षेत्र की सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर बहस करते हैं, महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होते हैं और एक साथ नए दृष्टिकोण लेकर आते हैं। • इस फोरम का नाम सिंगापुर के शांगरी-ला होटल से लिया गया है जहां यह 2002 से आयोजित किया जाता रहा है। • यह एशिया का सबसे बड़ा वार्षिक सुरक्षा मंच है। **(यूपीएससी सीएसई: भारत-प्रशांत संबंध)** • वर्ष 2023 का आयोजन सिंगापुर में हुआ। • ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने शांगरी-ला डायलॉग 2023 में मुख्य भाषण दिया। **(यूपीएससी सीएसई: शांगरी ला डायलॉग में प्रधान मंत्री का मुख्य भाषण)** **कूटनीति के विभिन्न स्तर:** • **ट्रैक वन कूटनीति:** आधिकारिक चर्चाओं में आम तौर पर उच्च-स्तरीय राजनीतिक और सैन्य नेता शामिल होते हैं। • **ट्रैक 2 कूटनीति:** अनौपचारिक वार्तालाप और समस्या-समाधान गतिविधियाँ, जिसमें प्रभावशाली शैक्षणिक, धार्मिक और एनजीओ नेता तथा अन्य नागरिक समाज के अभिनेता शामिल हैं, जो उच्च-रैंकिंग अधिकारियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से वार्तालाप कर सकते हैं। • **ट्रैक 3 कूटनीति:** लोगों से लोगों के बीच कूटनीति व्यक्तियों और निजी समूहों द्वारा की जाती है। **जरूर पढ़ें:** रायसीना डायलॉग **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
कोसोवो-सर्बिया संघर्ष	**संदर्भ:** हाल ही में कोसोवो और सर्बिया के बीच तनाव बढ़ने के बाद, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने अपने 700 और शांति सेना सैनिकों को कोसोवो भेजा। **इसके बारे में** • **कोसोवो:** कोसोवो एक छोटा लैंडलॉक क्षेत्र है जो सर्बिया के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है जो उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया और मोंटेनेग्रो के साथ सीमा साझा करता है। • सर्ब समुदाय के अनेक लोग कोसोवो को अपने राष्ट्र का जन्मस्थान मानते हैं। • **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-** ○ 1990 के दशक में यूगोस्लाविया के टूटने के बाद, कोसोवो जो कि पूर्व देश का एक प्रांत था, ने स्वतंत्रता की मांग की। ○ सर्बिया ने स्वतंत्रता की मांग करने वाले जातीय अल्बानियाई लोगों के खिलाफ क्रूर प्रतिक्रिया के बाद

हस्तक्षेप किया।

- यह 1999 में सर्बिया के विरुद्ध नाटो बमबारी अभियान के साथ समाप्त हुआ।
- सर्बियाई सेनाएँ कोसोवो से हट गईं लेकिन कई कोसोवो अल्बानियाई और सर्बों के लिए, संघर्ष कभी हल नहीं हुआ।
- नाटो के नेतृत्व वाली कोसोवो फोर्स (KFor) अभी भी कोसोवो में स्थित है।
- वर्ष 2008 में, कोसोवो ने एकतरफा स्वतंत्रता की घोषणा की।

- **संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जो कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं:-**
  - संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) के 193 देशों में से कुल 99 अब कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं।
  - इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के 27 में से 22 देश शामिल हैं।
  - रूस, भारत और चीन कोसोवो को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता नहीं देते हैं।
- **वर्तमान स्थिति:-**
  - अल्बानियाई प्रभुत्व वाली सरकार और सर्ब अल्पसंख्यक के बीच संबंध वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं।
  - वर्ष 2022 में तनाव के कारण सविनय अवज्ञा (civil disobedience) हुई।

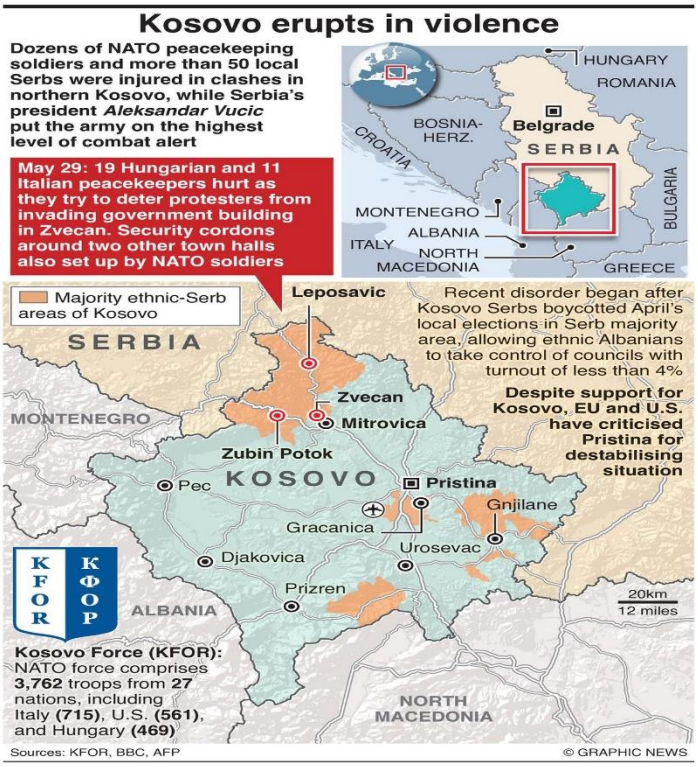

IMAGE SOURCE: THE HINDU

- गर्मियों में, कोसोवो के उत्तरी क्षेत्र में जातीय सर्बों ने एक नए कानून के विरोध में सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी और कुछ लोगों ने कथित तौर पर गोलियां चलाईं।
- विवाद को सुलझाने के लिए यूरोपीय संघ की मध्यस्थता वाली वार्ता विफल रही।

कोसोवो-सर्बिया संघर्ष पर भारत का रुख:-

- वर्ष 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से भारत ने कोसोवो को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है।
- इसके अलावा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे- यूनेस्को, एपोस्टिल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान हेतु प्रशांत कन्वेंशन और एग्मोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स में कोसोवो की सदस्यता का विरोध किया है।
- भारत द्वारा कोसोवो को मान्यता नहीं देने का कारण यह है कि उसका सर्बिया के साथ दीर्घकालिक संबंध है और

	वह उसकी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। **अवश्य पढ़ें:** Turkey's Peace with Sweden and Finland Joining NATO **स्रोत:** द हिंदू
SAI20 शिखर सम्मेलन	**संदर्भ:** भारत के G20 प्रेसीडेंसी के तहत SAI20 शिखर सम्मेलन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के नेतृत्व में गोवा में शुरू हुआ। **इसके बारे में:-** • यह एक ऐसा मंच है जहां G20 देशों के SAI सार्वजनिक नीतियों और शासन प्रथाओं के ऑडिट में अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। • **G20 SAI शिखर सम्मेलन का उद्देश्य:** SAI के बीच सहयोग को बढ़ावा देना वैश्विक चुनौतियाँ और शासन में जवाबदेही को बढ़ावा देना। • सार्वजनिक ऑडिटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और अपने-अपने देशों में सुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त पहल विकसित करने के लिए इस समूह की सालाना बैठक होती है। • **अध्यक्षता:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) श्री गिरीश चंद्र मुर्मू SAI20 की अध्यक्षता करेंगे। **(यूपीएससी सीएसई: CAG and ILO)** **भारत की अध्यक्षता में SAI20 विचार-विमर्श के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र** • **SAI20 विचार-विमर्श के लिए दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन किया गया है:** ○ **नीली अर्थव्यवस्था** ○ इसे विश्व बैंक द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। ○ **रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** ○ **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई):** कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट की उन कार्यों को करने की क्षमता जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। **सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (एसएआई) के महत्वपूर्ण कार्य:-** • **स्वतंत्र ऑडिट:** SAI सरकारी वित्त और संचालन का स्वतंत्र ऑडिट करते हैं। ○ वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक धन का उपयोग कानून के अनुसार किया जा रहा है और सरकारी एजेंसियां प्रभावी और कुशलता से काम कर रही हैं। • **पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना:** SAI ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता हैं। • **शासन में सुधार:** सरकारी संचालन में कमजोरियों और अक्षमताओं की पहचान करके, SAI शासन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता हैं। • **विधायी शाखा का समर्थन करना:** SAI सूचना और विश्लेषण प्रदान करके विधायी शाखा का समर्थन करता है जो कानून निर्माताओं को सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। • **कानून और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना:** SAI सरकारी संचालन और वित्तीय विवरणों की समीक्षा करके कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। • **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना:** SAI विश्व स्तर पर सुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों में अपने समकक्षों के साथ श्रेष्ठ प्रथाओं को सहयोग और साझा करता है। **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** • CAG भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। • यह भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख हैं। • यह सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक है।

	• **नियुक्ति:** भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। • **कार्यकाल:** 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। • **पदस्थ किये जाने की प्रक्रिया:** राष्ट्रपति CAG को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की समान प्रक्रिया द्वारा हटा सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। • अपना पद छोड़ने के बाद वह किसी अन्य कार्यालय के लिये पात्र नहीं होगा, चाहे वह भारत सरकार में हो या किसी राज्य में। • **अनुच्छेद 148:** यह मोटे तौर पर सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। **अवश्य पढ़ें:** शिखर सम्मेलन **स्रोत:** बिजनेस लाइन
यूनेस्को	**संदर्भ:** हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका 4 साल बाद इसमें फिर से शामिल होगा। **इसके बारे में:-** • यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है। • **उद्देश्य:** शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। • **मुख्यालय:** पेरिस, फ्रांस • **सदस्य:-** ○ इसमें 193 सदस्य देश और 11 सहयोगी सदस्य हैं, साथ ही गैर-सरकारी, अंतर-सरकारी और निजी क्षेत्रों में भागीदार हैं। ○ कुक आइलैंड्स, नीयू और फ़िलिस्तीन यूनेस्को के सदस्य है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। ○ अमेरिका, इज़राइल और लिकटेंस्टीन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। **यूनेस्को के कार्य:-** • सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। • सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। • वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को आगे बढ़ाना। • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। • अंतरसांस्कृतिक वार्तालाप को बढ़ावा देना। **यूनेस्को के उल्लेखनीय कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ:-** • **विश्व विरासत कार्यक्रम:** यह उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के स्थलों को नामित और संरक्षित करता है। • **सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम:** सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। • **अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम:** टिकाऊ जल प्रबंधन और सहयोग को बढ़ावा देना। • **मानव और जैवमण्डल कार्यक्रम:** सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना। • **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम:** अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और प्रचार-प्रसार करना। **(यूपीएससी मेन्स: विश्व धरोहर स्थल)** **संयुक्त राज्य अमेरिका का यूनेस्को छोड़ने का कारण** • वर्ष 2011 में, यूनेस्को ने फिलिस्तीन को सदस्य के रूप में शामिल किया। • इसके कारण तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के तहत अमेरिका ने एजेंसी की लाखों डॉलर की फंडिंग रोक दी थी। • **यूनेस्को की फंडिंग रोकने का कारण:-** ○ इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलिस्तीन को शामिल करने और यूनेस्को द्वारा इज़राइल के

	प्राचीन यहूदी स्थलों को फिलिस्तीनी विरासत स्थलों के रूप में नामित करने को इज़राइल विरोधी पूर्वाग्रह का उदाहरण बताया। ○ अमेरिकी कानून, इज़राइल के साथ देश के ऐतिहासिक संबंधों के कारण, किसी भी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को फंडिंग पर रोक लगाते हैं, जिसका तात्पर्य फिलिस्तीनियों की अपने राज्य की मांगों को मान्यता देना है। • परिणामस्वरूप, 2019 में अमेरिका और इज़राइल फिलिस्तीन मुद्दे पर संगठन में पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए यूनेस्को से बाहर हुए। ○ अमेरिका एक बार पहले 1984 में यूनेस्को से बाहर हुआ था और फिर 2003 में फिर से इसमें शामिल हुआ। • **हाल के घटनाक्रम:** हाल ही में एक समझौते के माध्यम से 2022 में इस बात पर बातचीत हुई कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को को फिर से फण्ड देना शुरू करेगा। **भारत और यूनेस्को** • भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य रहा है। • इसने 1946 में औपनिवेशिक शासन के अधीन रहते हुए यूनेस्को के संविधान की पुष्टि की थी। • भारत 1946 से लगातार यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना जाता रहा है। • हाल ही में, भारत ने 2021-25 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुनाव जीता। **भारत में यूनेस्को के मिशन के उद्देश्य:-** • सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना और आजीवन सीखना। **(यूपीएससी सीएसई: भाषाओं के लिए यूनेस्को फंड)** • सतत विकास के लिए साइंस नॉलेज और नीति जुटाना। • उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करना। • सांस्कृतिक विविधता, अंतरसांस्कृतिक संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। • सूचना और संचार के माध्यम से समावेशी ज्ञान समाज का निर्माण। **यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (INCCU)** • यह एक सरकारी संस्था है। • **स्थापना:-** ○ शुरू में वर्ष 1949 में स्थापित, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय में माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत एक सरकारी निकाय है। ○ वर्ष 1951 में एक स्थायी आयोग की स्थापना की गई। • **मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय में माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग। • **उद्देश्य:** यूनेस्को से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देना। • **आयोग के अध्यक्ष:** मानव संसाधन विकास मंत्री। **अवश्य पढ़ें:** Seabed **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
क्रेडिट लाइनें (एलओसी)	**संदर्भ:** हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि अफ्रीका के लिए भारत की भविष्य की क्रेडिट लाइन (एलओसी) महाद्वीप की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रही है। **इसके बारे में:-** • यह किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा दी गई ऋण सुविधा है जो ग्राहक को अधिकतम ऋण राशि निकालने में सक्षम बनाती है।

- **ऋणदाता (Lender):** यह किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा दिया जा सकता है।
- **उधारकर्ता (Borrower):** यह किसी सरकार, व्यवसाय या व्यक्तिगत ग्राहक को दिया जा सकता है।
- **समय सीमा:** निर्धारित उधार सीमा का उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है।
- **लेनदेन सीमा:** उधारकर्ता अधिकतम सीमा तक पहुंचने तक किसी भी समय पैसे निकाल सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपयोग: यह विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर प्रदान किया जाने वाला एक आसान ऋण है।
    - यह कोई अनुदान नहीं है और इसे उधार लेने वाली सरकार द्वारा चुकाया जाना है।
- **क्रेडिट लाइनों के प्रकार:** व्यक्तिगत, व्यावसायिक और घरेलू इक्विटी, अन्य।
- **लाभ:** इसमें अंतर्निहित लचीलापन है, जो इसके मुख्य लाभ है।
    - उधारकर्ता एक निश्चित राशि का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसका पूरा उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
    - वे LOC से अपने खर्च को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकते हैं।
    - उन्हें केवल उस राशि पर ब्याज देना होता है जो वे लेते हैं, संपूर्ण क्रेडिट लाइन पर नहीं।
- **नुकसान:** इसमें होने वाले नुकसान में शामिल हैं उच्च ब्याज दरें, देर से भुगतान के लिए जुर्माना, और अधिक खर्च करने की संभावना।

भारत-अफ्रीका संबंध:-

ऐतिहासिक संबंध

- अफ्रीका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध कई सदियों पुराने हैं। **(यूपीएससी सीएसई: भारत-अफ्रीका: चुनौतियां और आगे का रास्ता)**
- पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों की उपस्थिति 60 ईस्वी में एक प्राचीन यूनानी लेखक द्वारा लिखित 'पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी' या लाल सागर की गाइडबुक में दर्ज की गई है।
- महात्मा गांधी: उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। **(यूपीएससी सीएसई: भारत और महात्मा गांधी)**
- **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM):** भारत अन्य तीसरी दुनिया के देशों के बीच अफ्रीका के विकासशील देशों के हितों के चैंपियन के रूप में अग्रणी था। **(यूपीएससी सीएसई: NAM)**

अफ्रीका का महत्व

- अफ्रीका दुनिया के आधा दर्जन से अधिक सबसे तेजी से विकसित होने वाले देशों का घर है।
- अफ्रीकी महाद्वीप की आबादी एक अरब से अधिक है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 2.5 ट्रिलियन डॉलर है जो इसे एक विशाल संभावित बाजार बनाता है।
- अफ्रीका एक संसाधन-संपन्न देश है, जहां कच्चे तेल, गैस, दालें और फलियाँ, चमड़ा, सोना और अन्य धातुएं मौजूद हैं, जिनकी भारत में पर्याप्त मात्रा में कमी है।
    - भारत मध्य पूर्व से दूर अपनी तेल आपूर्ति में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है और अफ्रीका भारत के ऊर्जा मैट्रिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अफ्रीका में भारत की पहल

- भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीकी-भारतीय संबंधों का आधिकारिक मंच है।
    - इसे वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था।
- भारत भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत कर्मियों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण में $ 1 बिलियन से अधिक प्रदान करके क्षमता निर्माण में निवेश कर रहा है।
    - **ITEC:** विदेश मंत्रालय का अग्रणी क्षमता-निर्माण मंच है।
    - यह वर्ष 1964 में स्थापित किया गया।

	○ नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में 160 से अधिक देशों के 200,000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। • भारत ने पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क में 100 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। ○ **उद्देश्य:** सूचना प्रौद्योगिकी में अपनी शक्ति का लाभ उठाते हुए, अफ्रीका में डिजिटल विभाजन को पाटना। • भारतीय सैन्य अकादमियाँ कई अफ्रीकी राज्यों के सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। • **एशियन अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर:** यह भारतीय और जापानी थिंक टैंक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। ○ गलियारा सहयोग परियोजनाओं, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और संस्थागत कनेक्टिविटी, कौशल वृद्धि और लोगों से लोगों की भागीदारी के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। **अवश्य पढ़ें:** क्रेडिट इन इकॉनमी **स्रोत:** द इकोनॉमिक टाइम्स
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)	**संदर्भ:** अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत और चीन ने रूस का 80% तेल खरीदा। **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के बारे में:-** • यह एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। **(यूपीएससी सीएसई: आईईए)** • **स्थापना:** 1974 में • **मुख्यालय:** पेरिस, फ्रांस • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: इसकी स्थापना 1973-1974 के तेल संकट के मद्देनजर की गई थी, ताकि इसके सदस्यों को तेल आपूर्ति में बड़े व्यवधानों का जवाब देने में मदद मिल सके। • **उद्देश्य:** यह अपने सदस्य देशों और उससे आगे के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करता है। • यह अपनी ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। **IEA की सदस्यता:-** • इसके 30 सदस्य देश हैं। • इसमें आठ एसोसिएशन देश भी शामिल हैं। **पात्रता मापदंड:-** • IEA के लिए एक उम्मीदवार देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) का सदस्य देश होना चाहिए। o OECD: एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसकी स्थापना 1961 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। • IEA के लिए एक उम्मीदवार देश के पास होना चाहिए: • कच्चे तेल और/या उत्पाद का भंडार पिछले वर्ष के 90 दिनों के शुद्ध आयात के बराबर हो। • सरकार के पास वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधानों को दूर करने के लिए उनका उपयोग करने के लिए तत्काल पहुंच होनी चाहिए (भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से उनके पास न हो)। **प्रमुख रिपोर्ट:-** • विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट • विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट • विश्व ऊर्जा सांख्यिकी • विश्व ऊर्जा संतुलन • ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य

	• भारत ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट **भारत और IEA** • वर्ष 2017: भारत IEA का एसोसिएट सदस्य बना। • वर्ष 2021: भारत ने IEA के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता भी किया। o इसका उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और स्थायित्व में सहयोग को मजबूत करना है। • IEA ने भारत को पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। **अवश्य पढ़ें:** निर्णायक एजेंडा रिपोर्ट 2022 **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
नोवा कखोव्का बांध	**संदर्भ:** यूक्रेन में नोवा काखोव्का बांध हाल ही में ढह गया। **इस बांध के बारे में:-** • इसे 1956 में काखोव्का पनबिजली संयंत्र के हिस्से के रूप में बनाया गया था। • यह बांध सोवियत काल में बनाया गया था। • यह निप्रो नदी पर बना है। o डीनिप्रो: यूरोप की प्रमुख सीमा पार नदियों में से एक है। o यह यूक्रेन और बेलारूस की सबसे लंबी नदी है। o वोल्गा, डेन्यूब और यूराल नदियों के बाद यह यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। o यह रूस के स्मोलेंस्क के पास वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है। o यह बेलारूस और यूक्रेन से होते हुए काला सागर में गिरती है। o काला सागर: यह पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित एक अंतर्देशीय समुद्र है। **o** तुर्की जलडमरूमध्य प्रणाली - डार्डानेल्स, बोस्पोरस और मर्मारा सागर भूमध्य सागर और काला सागर के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र बनाते हैं। o काला सागर केर्च की जलडमरूमध्य द्वारा आज़ोव सागर से भी जुड़ा हुआ है। o काला सागर के सीमावर्ती देश रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया हैं। • यह बांध एक विशाल जलाशय को रोके रखता है, जिसे स्थानीय लोग काखोव्का सागर कहते हैं। • आयतन: यह बांध काखोव्का जलाशय में लगभग 18 घन किलोमीटर पानी रोकता है। • यह खेरसॉन क्षेत्र में स्थित है। **(यूपीएससी सीएसई: रूस-यूक्रेन युद्ध पर परिप्रेक्ष्य)** ○ रूस का बाएँ या दक्षिणी किनारे पर कब्ज़ा है जबकि यूक्रेन का दाएँ या उत्तरी किनारे पर नियंत्रण है। • **वितरण:** यह क्रीमिया प्रायद्वीप और ज़ापोरीज़िया परमाणु संयंत्र को पानी की आपूर्ति करता है। • जलाशय ने ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शीतलन प्रणाली के लिए भी पानी उपलब्ध कराया। ○ यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र: यह यूरोप में सबसे बड़ा है। **अवश्य पढ़ें:** काला सागर अनाज पहल **स्रोत:** AIR
महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल (iCET)	**संदर्भ:** हाल ही में महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका-भारत पहल (initiative on Critical and Emerging Technology- iCET) के तहत दोनों देशों ने उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिये एक रोडमैप पेश किया। **परिचय :-** • iCET भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और नई प्रौद्योगिकियों के विकास में एक साथ काम करने के लिए एक साझेदारी है। • **उद्देश्य:** iCET का लक्ष्य अमेरिका और भारत के बीच प्रौद्योगिकी संपर्क को बढ़ाना है, साथ ही संभावित रूप से उनकी बढ़ती साझेदारी में अतिरिक्त रणनीतिक गहराई और व्यापक विस्तार करना है। • **iCET के तहत सहयोग के क्षेत्र:** क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, 5G और 6G वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर, और चंद्र अन्वेषण जैसी नागरिक अंतरिक्ष परियोजनाएं। (यूपीएससी सीएसई: भारत-अमेरिका: व्यापार और जलवायु)

	• **देखरेख:** iCET की देखरेख और निर्देशन दिल्ली में प्रधान मंत्री कार्यालय और वाशिंगटन में व्हाइट हाउस द्वारा किया जायेगा। **भारत के लिए iCET का महत्व:-** • भारतीय और अमेरिकी हितों के बढ़ते अभिसरण से चीन द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा, आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों के प्रबंधन में मदद मिल सकती है। • यह भारत के लिए एक विकल्प सुरक्षित करने और रूसी सैन्य प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। • यह भारत की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा और भारत को महत्वपूर्ण और उभरते हुए क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान करेगा। • यह अमेरिका के साथ अधिक व्यापार करके भारत की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगा। • इससे उन्हें अधिक निवेश और रोजगार के अवसर लाने में मदद मिलेगी। **MUST READ: India's growing defence diplomacy footprint** **SOURCE: THE HINDU**
ऑर्डर ऑफ द नाइल	**संदर्भ:** हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र का 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' पुरस्कार प्रदान किया गया। **पृष्ठभूमि:-** • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने मिस्र (Egypt) का सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' (Order Of The Nile) से सम्मानित किया। • यह मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। • प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। • इससे पहले पीएम मोदी ने मिस्र की ऐतिहासिक 11वीं सदी की अल-हकीम मस्जिद का भी दौरा किया, जिसे भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से बहाल किया गया था। ○ **दाऊदी बोहरा:** दाउदी बोहरा समुदाय इस्लाम की शिया इस्माइली शाखा के भीतर एक धार्मिक संप्रदाय है। ○ इनकी सबसे बड़ी संख्या भारत, पाकिस्तान, यमन, पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्व में रहती है। **ऑर्डर ऑफ द नाइल के बारे में:-** • यह मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। (यूपीएससी मेन्स: भारत और मिस्र के बीच सहयोग) • **स्थापना:** 1915 में • **प्रस्तुतकर्ता:** मिस्र राष्ट्र • यह उन राष्ट्राध्यक्षों, क्राउन प्रिंसेस और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जो मिस्र या मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। • **डेकोरेशन :** यह पुरस्कार अपने आप में पूरी तरह से शुद्ध सोने से बना एक कॉलर है और इसमें तीन वर्ग सोने की इकाइयाँ होती हैं, जिनमें से प्रत्येक फैरोनिक प्रतीकों से सजी होती है। ○ फैरोनिक प्रतीक: ये प्राचीन मिस्रवासियों के जीवन में असंख्य प्रतीक थे और उनके प्रतीकों, रीति-रिवाजों और उपयोग में भिन्नता थी। **अवश्य पढ़ें:** भारत-अफ्रीका: चुनौतियाँ और आगे की राह **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस

अर्थव्यवस्था

लघु वित्त बैंक

संदर्भ: हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि लघु वित्त बैंकों ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में क्रांति ला दी है।

लघु वित्त बैंक के विषय में:

IMAGE SOURCE: tnpscthervupettagam.com

- लघु वित्त बैंक वे वित्तीय संस्थान हैं जो देश के उन क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
- लघु वित्त बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं।
- इसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपये है।
- पूंजी पर्याप्तता का अनुपात - यह जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का 15% है।
- विदेशी शेयरधारिता को भुगतान पूंजी के 74% तक सीमित किया गया।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) 24% से अधिक नहीं हो सकता।
- RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लघु वित्त बैंकों को अपने कुल शुद्ध ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी के लिये आवंटित करना होता है। **(यूपीएससी मेन्स: माइक्रो फाइनेंस में ग्रामीण भारत के उद्यमशीलता उत्साह को उजागर करने की क्षमता)**
- लघु वित्त बैंक का आईडिया वित्तीय समावेशन पर नचिकेतमोर समिति (2013) की सिफारिश पर तैयार किया गया था।
- लघु वित्त बैंकों के मुख्य ग्राहकों में सूक्ष्म उद्योग, लघु और सीमांत किसान, असंगठित क्षेत्र की संस्थाएँ और लघु व्यवसाय इकाइयाँ शामिल हैं।
- उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस प्राप्त है और आरबीआई अधिनियम, 1934 और फेमा के प्रावधानों द्वारा शासित हैं।

मापदंड:-

- निवासी व्यक्ति/पेशेवर (भारतीय नागरिक), अकेले या संयुक्त रूप से प्रत्येक के पास वरिष्ठ स्तर पर बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
- सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (Microfinance Institution), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC), स्थानीय क्षेत्र के बैंक और भुगतान बैंक जैसी संस्थाएँ जो निवासियों द्वारा नियंत्रित होती हैं, वे भी लघु वित्त बैंकों में परिवर्तित हो सकती हैं।

	(यूपीएससी सीएसई: डिजिटल बैंक) • भारतीय निवासी और जिनके पास कम से कम पांच वर्षों की अवधि तक अपना व्यवसाय चलाने की उपलब्धि का सफल रिकॉर्ड हो, उन्हें इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। • छोटे वित्त बैंकों की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम की अनुमति नहीं है। **कार्य:-** • छोटी जमा राशि लेना और ऋण वितरित करना । • म्यूचुअल फंड, बीमा उत्पाद और अन्य सरल तृतीय-पक्ष वित्तीय उत्पाद वितरित करना। • अपने कुल समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधारी के लिये आवंटित करना। (संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश) • एकल या समूहिक देनदार के लिये अधिकतम ऋण आकार और निवेश सीमा उसके पूंजीगत कोष के क्रमशः 10% और 15% तक सीमित होगी। • उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऋण पोर्टफोलियो का 50% भाग 25 लाख रुपए तक का अग्रिम हो। **अवश्य पढ़ें:** समावेशी विकास **स्रोत:** प्रिंट
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (CIBIL)	**संदर्भ:** केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि एक छात्र द्वारा शिक्षा ऋण के लिए आवेदन CIBIL के (क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड) कम स्कोर के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। **इसके बारे में:-** • क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड भारत में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों में से एक है। • यह व्यक्तियों और कंपनियों की प्रत्येक क्रेडिट-संबंधी कार्रवाई का दस्तावेज़ीकरण रखने के साथ-साथ ऋणों और क्रेडिट कार्डों की गिनती भी करती है। • विभिन्न वित्तीय संस्थान और बैंक, अपनी व्यक्तिगत जानकारी CIBIL को जमा करते हैं। • CIBIL CIR (क्रेडिट सूचना रिपोर्ट) और क्रेडिट स्कोर प्रदान करता है। (UPSC CSE: क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) • CIBIL की रिपोर्ट में किसी व्यक्ति द्वारा लिए जा रहे ऋण जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी शामिल होती है। • CIBIL रिपोर्ट दो प्रकार की उपलब्ध होती हैं:- ○ **कंपनी क्रेडिट पर CIBIL रिपोर्ट-** CIBIL CCR आपकी कंपनी के क्रेडिट इतिहास का रिकॉर्ड है। यह देश भर में ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा CIBIL को सौंपे गए डेटा से बनाया गया है। किसी कंपनी के पूर्व भुगतान व्यवहार, उसके भविष्य के व्यवहार का एक मजबूत संकेत है। ○ o क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट- यह व्यक्तियों के लिए बनाई गई है और इसमें अतीत में क्रेडिट व्यवहार और CIBIL के स्कोर के बारे में गहन जानकारी शामिल होती है। **क्रेडिट रेटिंग का महत्व:** **ऋणदाताओं के लिए;** • **बेहतर निवेश निर्णय:** कोई भी बैंक या ऋण देने वाली कंपनियां जोखिम भरे ग्राहक को पैसा नहीं देना चाहेंगी। क्रेडिट रेटिंग से, उन्हें किसी कंपनी (जो पैसा उधार ले रही है) की साख और उससे जुड़े जोखिम कारक के बारे में पता चलता है। इसका मूल्यांकन करके वे बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं। • **सेफ्टी का आश्वासन:** उच्च क्रेडिट रेटिंग का मतलब पैसे की सुरक्षा के बारे में एक आश्वासन है और इसका समय पर ब्याज सहित भुगतान होगा। **उधारकर्ताओं के लिए (For Borrowers);** • **सरल ऋण स्वीकृति:** उच्च क्रेडिट रेटिंग के साथ, आपको कम/कोई जोखिम नहीं वाले ग्राहक के रूप में देखा जाता है। इसलिए, बैंक आपके ऋण आवेदन को आसानी से मंजूरी देते है। • **प्रतिस्पर्धी ब्याज दर:** आपको इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि प्रत्येक बैंक ब्याज दरों की एक विशेष सीमा में

	ऋण प्रदान करता है। आपके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज दर निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक आपका क्रेडिट इतिहास है। क्रेडिट रेटिंग जितनी अधिक होगी, ब्याज दर उतनी ही कम होगी। **क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियाँ (सीआईसी):-** • वर्तमान में, चार सीआईसी हैं। • उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। • इनमें इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। • भारत में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है और क्रेडिट सूचना कंपनी विनियमन अधिनियम, 2005 द्वारा शासित किया जाता है। **अवश्य पढ़ें:** वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) **स्रोत**: टाइम्स ऑफ इंडिया
आरबीआई लाइट वेट पेमेंट सिस्टम	**संदर्भ:** हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 'लाइट वेट पेमेंट सिस्टम' शुरू करने की घोषणा की। **परिचय:** • लाइटवेट सिस्टम का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध जैसी आपात स्थितियों के दौरान निर्बाध डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करना है। • **पृष्ठभूमि:** RBI उत्कर्ष 2.0 पहल के एक भाग के रूप में केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों के लिए निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रहा है। **मुख्य विशेषताएं:-** • यह प्रणाली मौजूदा भुगतान प्रौद्योगिकियों जैसे UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस), NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर), और आरटीजीएस (रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS)) से स्वतंत्र रूप से संचालित होगी। • इसे कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। • आपात्कालीन स्थिति के दौरान इसमें न्यूनतम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। • यह अत्यधिक और अस्थिर स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण लेनदेन, जैसे कि थोक भुगतान (bulk payments) और इंटरबैंक भुगतान को संसाधित करेगा। • यह सिस्टम कम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर कार्य करता है। • इसे जरूरत पड़ने पर ही सक्रिय किया जाता है। **लाइटवेट भुगतान प्रणाली बनाम यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस)** • यूपीआई और अन्य पारंपरिक प्रणालियाँ बड़ी मात्रा में लेनदेन संभालने को प्राथमिकता देती हैं और इसके लिए एक स्थिर और मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। (यूपीएससी सीएसई: यूपीआई) • दूसरी ओर, लाइटवेट सिस्टम को अस्थिर और अत्यधिक स्थितियों में भी संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब नियमित भुगतान प्रणाली पहुंच योग्य नहीं हो सकती है। **उत्कर्ष 2.0:** • जनवरी 2023 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी मध्यम अवधि की रणनीति का दूसरा चरण उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है। • उत्कर्ष 2.0, उत्कर्ष 0.1 द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है, जिसे जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और 2019 से 2022 तक की अवधि को कवर किया गया था। • उत्कर्ष 2.0 2023 से 2025 की अवधि में आरबीआई का मार्गदर्शन करेगा और इसमें छह विज़न स्टेटमेंट शामिल हैं जो आरबीआई के वैधानिक और अन्य कार्यों के प्रदर्शन में सुधार करने, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इसकी प्रासंगिकता और महत्व को बढ़ाने और इसके आंतरिक प्रशासन, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

अवश्य पढ़ें: भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS)
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

शुल्क-मुक्त कोटा-मुक्त (डीएफक्यूएफ) योजना

संदर्भ: हाल की रिपोर्टों के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन (WTO) की शुल्क-मुक्त कोटा-मुक्त (DFQF) योजना के तहत भारत द्वारा अल्प विकसित देशों (LDC) को शून्य टैरिफ पर पेश किए गए 11,000 उत्पादों में से लगभग 85 प्रतिशत अप्रयुक्त हैं।

इसके बारे में:-

STATUS CHECK

Utilisation of India's preferential scheme by LDCs with covered imports higher than $60 mn

Country	Utilisation rate (in %)	Preference margin (percentage points)
Bangladesh	0	17
Afghanistan	0	24
Guinea	8	15
Burkina Faso	8	15
Myanmar	18	21
Sudan	32	17
Togo	60	16
Zambia	63	9
Madagascar	70	21
Tanzania	78	14
Guinea-Bissau	81	18
Mozambique	87	12
Senegal	87	13
Benin	98	25

Source: WTO

IMAGE SOURCE: BUSINESS STANDARD

- **पृष्ठभूमि:** अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के लिए शुल्क-मुक्त कोटा-मुक्त (डीएफक्यूएफ) पहुंच प्रदान करने का निर्णय पहली बार 2005 में डब्ल्यूटीओ हांगकांग मंत्रिस्तरीय बैठक में लिया गया था।
  - **सबसे कम विकसित देश (एलडीसी):** विश्व व्यापार संगठन (WTO) उन देशों को सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) के रूप में मान्यता देता है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस रूप में नामित किया गया है।
    - वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सूची में 48 एलडीसी हैं।
    - इनमें से 31 विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं।
- इस योजना के लिए सभी विकसित और विकासशील देश के सदस्यों को सभी एलडीसी से उत्पन्न होने वाले सभी उत्पादों के लिए तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है।
- वर्ष 2008 में, भारत इस पहल को लागू करने वाला पहला विकासशील देश बन गया, जिसने एलडीसी को अपनी कुल टैरिफ लाइनों के 85% तक पहुंच प्रदान की।
  - इसका उद्देश्य एलडीसी को वैश्विक व्यापार प्रणाली में एकीकृत करना और उनके व्यापारिक अवसरों में सुधार करना है।
- इसके बाद, 2014 में, एलडीसी को भारत की टैरिफ लाइनों के लगभग 98.2% पर तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया था।
- भारत एलडीसी को 11,506 तरजीही टैरिफ लाइनें प्रदान करता है, जिनमें से 10,991 शुल्क-मुक्त हैं।
  - शुल्क-मुक्त टैरिफ लाइनों में से 1,129 कृषि वस्तुएं हैं और शेष 9,862 गैर-कृषि वस्तुएं हैं।

2020 के लिए डब्ल्यूटीओ डेटा के मुख्य निष्कर्ष:-

- भारत की 85% टैरिफ लाइनें चीन की 64% की तुलना में शून्य उपयोग दर दर्शाती हैं।
- बाकि में, केवल 8% चीन की 17% की तुलना में 95% से अधिक की उपयोगिता दर प्रदर्शित करती हैं।
- उल्लेखनीय मात्रा में एलडीसी निर्यात गैर-तरजीही (सबसे पसंदीदा देश) टैरिफ रुट्स के अंतर्गत भारत में प्रवेश कर रहे हैं, भले ही वे भारतीय प्राथमिकता योजना के अंतर्गत आते हों।
- लाभार्थी एलडीसी के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता है।
- **गिनी और बांग्लादेश (Guinea and Bangladesh):** एक साथ उपयुक्त आयात की उच्चतम मात्रा दर्शाते हैं।
- **बेनिन:** यह 98% की उपयोग दर की रिपोर्ट करता है, जो सभी लाभार्थी देशों में सबसे अधिक है।

	• **अफगानिस्तान:** निर्यात किए गए 325 मिलियन डॉलर मूल्य के फलों और मेवों को भारतीय प्राथमिकता योजना के तहत 28 प्रतिशत अंकों के वरीयता मार्जिन की पेशकश के बावजूद सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के तहत दर्ज किया गया था। ○ **सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN):** इसका उद्देश्य अन्य लोगों के साथ समान व्यवहार करना। ▪ डब्ल्यूटीओ समझौतों के तहत, देश आम तौर पर अपने व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ▪ यदि कोई देश किसी को विशेष लाभ देता है (जैसे कि उनके किसी उत्पाद के लिए कम सीमा शुल्क दर), तो उन्हें अन्य सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों के लिए भी ऐसा ही करना होगा। ▪ इस सिद्धांत को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) उपचार के रूप में जाना जाता है। • **चाड:** एमएफएन के तहत 48 मिलियन डॉलर मूल्य के खनिज ईंधन, तेल और उत्पाद आदि का निर्यात भारत में प्रवेश कर रहा है। **अवश्य पढ़ें:** विश्व व्यापार संगठन को पुनर्जीवित करना **स्रोत:** बिजनेस स्टैंडर्ड
मूल्य समर्थन योजना	**संदर्भ:** सरकार ने हाल ही में मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर दाल की खरीद सीमा को हटाने की घोषणा की। **मूल्य समर्थन योजना के बारे में:-** • यह योजना NAFED के माध्यम से खरीद के लिए है। (UPSC CSE: NAFED और APMC) • इसके तहत, NAFED तिलहन, दालों और कपास की खरीद करता है जब कीमतें MSP से नीचे गिर जाती हैं। • PSS के तहत खरीद तब तक जारी रहती है जब तक कीमतें एमएसपी पर या उससे ऊपर स्थिर नहीं हो जाती। • किसान कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समिति (एपीएमसी) केंद्रों में समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। • केंद्र सरकार ऐसे कार्यों को करने में NAFED को होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति करती है। **नेफेड:-** • इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। • यह बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है। • यह भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का शीर्ष संगठन है। • जब भी कीमतें एमएसपी से नीचे आती हैं तो यह खरीद करता है। • यह वर्तमान में भारत में कृषि उत्पादों की सबसे बड़ी खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक है। **उद्देश्य:-** • कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण को व्यवस्थित, बढ़ावा देना और विकसित करना। • कृषि मशीनरी, उपकरण और अन्य इनपुट वितरित करना। • कृषि उत्पादन में तकनीकी सलाह हेतु कार्य करना एवं सहायता करना। **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)** • कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी की घोषणा फसलों की बुवाई के मौसम की शुरुआत में की जाती है। CACP: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। • यह किसानों की उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना है। • **उद्देश्य:** संकटग्रस्त बिक्री से किसानों का समर्थन करना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद करना। • आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एमएसपी की घोषणा की। • **एमएसपी के अंतर्गत फसलें:-**

	○ केंद्र वर्तमान में CACP की सिफारिशों के आधार पर 23 कृषि वस्तुओं के लिए MSP तय करता है। ○ **अनाज (7):** धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी ○ **दाल (5):** चना, अरहर, मूँग, उड़द और मसूर की दाल ○ **तिलहन (8):** मूँगफली, सरसों, तोरिया (लाही), सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम का बीज, रामतिल का बीज ○ **4 व्यावसायिक फसलें:** कच्ची कपास, कच्चा जूट, नारियल, सूखा नारियल ○ गन्ना (उचित और लाभकारी मूल्य) **अवश्य पढ़ें:** कोपरा सीजन 2023 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) **स्रोत:** TIMES NOW
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT)	**संदर्भ:** हाल ही में, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने सेबी के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग्स का लाइसेंस रद्द कर दिया था। **इसके बारे में:-** ● यह सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। ● इसकी केवल एक बेंच है, जो मुंबई में बैठती है। ● क्षेत्राधिकार: देशभर में ● SAT की संरचना: इसमें एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य होते हैं। ○ पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति: भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा। ● **शक्तियाँ:** इसमें सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ होती हैं। ○ इसके आदेशों की अपील को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ● **महत्वपूर्ण कार्य:-** ○ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या अधिनियम के तहत एक निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई और निपटान करना। **(यूपीएससी सीएसई: सेबी)** ○ इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत एसएटी को प्रदत्त क्षेत्राधिकार, अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करना। ○ पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई और निपटान करना। **(यूपीएससी सीएसई: एनपीएस)** **पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए):-** ● यह एक पेंशन नियामक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। ● यह पीएफआरडीए अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ● **मंत्रालय:** वित्त मंत्रालय ● **मुख्यालय:** नई दिल्ली ● **कार्य:** यह पेंशन निधि की स्थापना, विकास और विनियमन द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ● यह पेंशन निधि की योजनाओं और संबंधित मामलों के ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है। ● यह भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई और निपटान करता है। **भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI):-** ● यह आईआरडीए अधिनियम 1999 के तहत स्थापित एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। ● इसके शीर्ष निकाय भारत में बीमा क्षेत्र की देखरेख और विनियमन करता है। ● **उद्देश्य:** पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना, भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करना, बढ़ावा देना और

	व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना। • **नोडल मंत्रालय:** वित्त मंत्रालय • **मुख्य कार्यालय:** हैदराबाद • **संरचना:** IRDAI एक 10 सदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और भारत सरकार चार अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति करती है। **कार्य:-** • लागू कानूनों और विनियमों की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हुए बीमा उद्योग का उचित विनियमन करना। • बीमा कंपनियों का पंजीकरण और विनियमन। • पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना। • बीमा मध्यस्थों के लिए लाइसेंस देना और मानदंड स्थापित करना। • गैर-जीवन बीमा कवर की प्रीमियम दरों और शर्तों को विनियमित करना तथा उनकी देखरेख करना। **अवश्य पढ़ें:** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कृषि वस्तुओं पर व्यापार प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई **स्रोत:** बिजनेस स्टैंडर्ड
प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) धारक	**संदर्भ:** RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) विनियमित संस्थाओं के लिये ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने वाली एक समिति ने धोखाधड़ी और अनधिकृत लेन-देन से सुरक्षा प्रदान करने के लिये जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation- DICGC) को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) तक विस्तारित करने की सिफारिश की है। **इसके बारे में:-** • ये वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करने वाले साधन हैं, ये वित्तीय सेवाओं का संचालन करते हैं और उनमें संग्रहीत धन पर प्रेषण सुविधाएँ सक्षम करते हैं। • प्रीपेड उपकरणों को स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, इंटरनेट खाते, इंटरनेट वॉलेट, मोबाइल खाते, मोबाइल वॉलेट, पेपर वाउचर और प्रीपेड वाउचर तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी साधन के रूप में जारी किया जा सकता है। (यूपीएससी सीएसई: गैर-बैंक पीएसपी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होंगे) • पीपीआई के तीन प्रकार होते है:- **1. क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई:** ये पीपीआई किसी इकाई द्वारा केवल उस इकाई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए जारी किए जाते हैं। • ये नकद निकासी की अनुमति नहीं देते हैं। • ऐसे उपकरणों के संचालन के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। • क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई का सबसे आम उदाहरण एक ब्रांड-स्पेसिफिक कार्ड है। **2. सेमी-क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई:** बैंक (आरबीआई द्वारा अनुमोदित) और गैर-बैंक (आरबीआई द्वारा अधिकृत) ये पीपीआई जारी करते हैं। • वे व्यापारिक स्थानों पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए होते हैं, इनके पास पीपीआई को भुगतान उपकरण के रूप में स्वीकार करने के लिए जारीकर्ता के साथ एक विशिष्ट अनुबंध रहता है। **3. ओपन सिस्टम पीपीआई:** ये पीपीआई केवल बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं (आरबीआई द्वारा अनुमोदित)। • इनका उपयोग किसी भी व्यापारी के यहां सामान और सेवाओं की खरीद के लिए किया जाता है। • ऐसे पीपीआई के माध्यम से एटीएम/प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों/बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (बीसी) पर नकद निकासी की अनुमति है। **जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)** • वर्ष 1978 में डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (DIC) और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CGCI) के विलय के परिणामस्वरूप DICGC का गठन हुआ।

	• यह जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के तहत एक वैधानिक निकाय है। • यह भारत में बैंकों के लिए जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी के रूप में कार्य करता है। यह प्रति बैंक खाताधारक 5 लाख रुपये तक के जमा खातों की सुरक्षा करता है। यदि किसी एक बैंक में खाताधारक की जमा राशि 5 लाख रुपये से अधिक है, तो बैंक दिवालिया होने पर DICGC ब्याज और मूलधन सहित 5 लाख रुपये तक का भुगतान करेगा। • यह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। • RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। • DICGC का कवरेज:-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भारत में शाखाओं वाले विदेशी बैंकों और सहकारी बैंकों सहित बैंकों को DICGC के साथ जमा बीमा कवर लेना अनिवार्य है। • कवर की गई जमाओं के प्रकार:-DICGC सभी बैंक जमाओं का बीमा करता है, जैसे बचत, सावधि, चालू, आवर्ती, आदि। निम्नलिखित प्रकार की जमाएं DICGC के अंतर्गत शामिल नहीं हैं:- o विदेशी सरकारों की जमाराशियाँ। o केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियाँ। o अंतर-बैंक जमा। o राज्य भूमि विकास बैंकों की राज्य सहकारी बैंकों में जमा राशि। o भारत के बाहर प्राप्त किसी भी जमा के कारण देय कोई भी राशि। o कोई भी राशि जिसे आरबीआई की पिछली मंजूरी के साथ निगम द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई हो। **अवश्य पढ़ें:** UPI और NPCI विनियमन **स्रोत:** इंडियन एक्सप्रेस
भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने कृषि विपणन के समान एक प्रणाली विकसित करके, मत्स्य पालन क्षेत्र में विपणन को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। **भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में:-** • भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। • भारतीय नीली क्रांति से मछली पकड़ने और जलीय कृषि उद्योगों में बड़ा सुधार हुआ है। o **नीली क्रांति:** यह 1960 के दशक के मध्य से लेकर आज तक विश्वव्यापी जलीय कृषि उद्योग के तीव्र विकास के समय को संदर्भित करता है। o इसे भारत में 1985 से 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना (FYP) के दौरान लॉन्च किया गया था। • इन उद्योगों को उभरता हुआ क्षेत्र माना जाता है और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ने का अनुमान है। o **सनराइज उद्योग:** सनराइज उद्योग एक तेजी से उछाल का वादा दिखाते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक बढ़ते क्षेत्र या व्यवसाय के लिए बोलचाल का शब्द है। **मत्स्य पालन क्षेत्र में हालिया रुझान:-** • हाल के दिनों में, भारतीय मात्स्यिकी में समुद्री वर्चस्व वाली मात्स्यिकी से अंतर्देशीय मात्स्यिकी की ओर एक प्रतिमान बदलाव देखा गया है, जिसमें 1980 के मध्य में मत्स्य उत्पादन में 36% से पिछले कुछ समय में 70% के योगदान के साथ अन्तर्देशीय मात्स्यिकी ने प्रमुख रूप से योगदान दिया है। • वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मछली उत्पादन 16.25 MMT के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। • समुद्री निर्यात 57,586 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। **(यूपीएससी सीएसई: मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौता)** • **शीर्ष मछली उत्पादक राज्य:-** o भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है। **मत्स्य पालन क्षेत्र की चुनौतियाँ:-** • अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ना: यह अत्यधिक मछली पकड़ने को बढ़ावा देता है और क्षेत्र की स्थिरता को कमजोर करता है।

	○ IUU मछली पकड़ने में उचित लाइसेंस के बिना मछली पकड़ना, प्रतिबंधित गियर का उपयोग करना और पकड़ने की सीमा की अवहेलना करना जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। • **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी:** पुरानी मछली पकड़ने वाली नौकाएं, गियर और प्रसंस्करण सुविधाएं क्षेत्र की दक्षता और उत्पादकता में बाधा पहुँचाती हैं। अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और परिवहन बुनियादी ढांचे के परिणामस्वरूप फसल के बाद नुकसान होता है। • **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट:** बढ़ते समुद्री तापमान, समुद्र के अम्लीकरण और बदलती धाराओं का समुद्री पारिस्थितिक तंत्र तथा मछली की आबादी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। • **सामाजिक-आर्थिक मुद्दे:** बड़ी संख्या में छोटे पैमाने के और कारीगर मछुआरे जो कई सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं, भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की विशेषता है। ○ इन चुनौतियों में कम आय, ऋण और बीमा तक पहुंच की कमी, अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा उपाय आदि शामिल हैं। • लैंगिक असमानताएं और मत्स्य पालन में महिलाओं का हाशिए पर होना भी चुनौतियां उत्पन्न करता है। • **बाज़ार पहुंच और मूल्य श्रृंखला अक्षमताएँ:** भारत में महत्वपूर्ण मछली उत्पादन के बावजूद, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचने में चुनौतियाँ हैं। **अवश्य पढ़ें:** कृषि सुधार **स्रोत:** AIR
फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (एफएलडीजी) प्रणाली	**संदर्भ:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में डिजिटल ऋण क्षेत्र में फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (FLDG) प्रणाली की अनुमति दी है। **इसके बारे में:-** • फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (FLDG) को डिफ़ॉल्ट हानि गारंटी (DLG) के रूप में भी जाना जाता है। • यह बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और डिजिटल ऋण क्षेत्र में फिनटेक अभिकर्ताओं के बीच एक सुरक्षा-नेट व्यवस्था है। • FLDG एक फिनटेक और बैंकों या NBFC जैसी विनियमित इकाई के बीच एक ऋण देने वाला मॉडल है। ○ **वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक):** यह एक नई तकनीक है जो वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी और उपयोग को बेहतर तथा स्वचालित करने का प्रयास करती है। (यूपीएससी सीएसई: भारत में फिनटेक विनियमन) • इसके तहत, यदि कोई उधारकर्ता बैंकों या एनबीएफसी को ऋण चुकाने में विफल रहता है तो फिनटेक कंपनी डिफॉल्ट के एक निश्चित राशि तक मुआवजा देने की गारंटी देती है। • क्रेडिट जोखिम फिनटेक कंपनियों द्वारा वहन किया जाता है जिन्हें कभी-कभी ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) के रूप में भी जाना जाता है। **ऋण सेवा प्रदाता (LSP)** • ये नए युग के खिलाड़ी हैं जो ऋण देने के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं। • ये किसी बैंक या NBFC के एजेंट हैं। (यूपीएससी सीएसई: आरबीआई ने NBFC के लिए सख्त नियामक ढांचे का सुझाव दिया है) • वे आरबीआई के आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहक अधिग्रहण, अंडरराइटिंग समर्थन, मूल्य निर्धारण समर्थन, संवितरण, सर्विसिंग, निगरानी और विशिष्ट ऋण या ऋण पोर्टफोलियो की रिकवरी में ऋणदाता के एक या अधिक कार्य (आंशिक या पूर्ण) करते हैं। **अवश्य पढ़ें:** ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना फिनटेक **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
संकल्प कार्यक्रम	**संदर्भ:** हाल ही में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने आजीविका संवर्धन (संकल्प) कार्यक्रम के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता के तहत प्रशिक्षकों के क्लस्टर-आधारित प्रशिक्षण परियोजना में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को प्रमाणित किया। **संकल्प कार्यक्रम के बारे में:-**

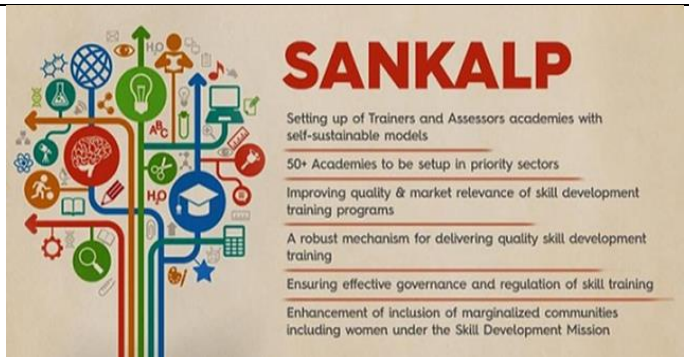

IMAGE SOURCE: IASBABA

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **कार्यकाल:** वर्ष 2018-2023 **(यूपीएससी सीएसई: संकल्प योजना)**
- **मंत्रालय:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)
- **उद्देश्य:** संस्थानों को मजबूत करने, बेहतर बाजार कनेक्टिविटी लाने और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को शामिल करके अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना।
- **योग्य आयु:** उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) के अधिदेश को लागू करना है।
- इसे विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त होती है। **(यूपीएससी सीएसई: विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम)**
    - **विश्व बैंक:** एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो विकासशील देशों को उनकी आर्थिक उन्नति में सहायता के लिए वित्तपोषण, सलाह और अनुसंधान प्रदान करने के लिए समर्पित है।

संकल्प के 3 प्रमुख क्षेत्र:-

- केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण।
- कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता आश्वासन।
- कौशल विकास कार्यक्रमों में हाशिये पर पड़ी आबादी को शामिल करना।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम)

- इसका लक्ष्य कौशल प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में अभिसरण बनाना है।
- **लॉन्च:** वर्ष 2015। **(यूपीएससी सीएसई: एनएसडीएम)**
- **मंत्रालय:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)।

NSDM के उद्देश्य:-

- सभी क्षेत्रों और राज्यों में कौशल प्रशिक्षण और विकास के प्रयासों को समेकित करना।
- त्वरित गति से बड़े पैमाने पर विभिन्न कौशल प्रयासों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने में मदद करना।
- एक संपूर्ण ढांचा तैयार करना जो नागरिकों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देता है।

संस्थागत तंत्र:-

एमएसडीई ने तीन स्तरों पर संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं:-

- गवर्निंग काउंसिल: नीति मार्गदर्शन के लिए शीर्ष स्तर पर
- संचालन समिति
- मिशन निदेशालय

मिशन निदेशालय क्षैतिज रूप से कार्य करने वाले तीन अतिरिक्त संस्थानों द्वारा समर्थित है। इसमे शामिल है:-

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए):-

- एनएसडीए की स्थापना सरकार और निजी क्षेत्र के कौशल विकास प्रयासों के समन्वय और सामंजस्य के लिए की गई

	थी। • यह नीति अनुसंधान, गुणवत्ता आश्वासन और सभी कौशल एजेंसियों में गुणवत्ता मानकों के कार्यान्वयन आदि पर केंद्रित है। **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC):-** • NSDC देश में प्रशिक्षण क्षमता बनाने, व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों को निधि देने और कौशल विकास के लिए एक बाजार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) है। • यह सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण पहलुओं की अनदेखी करता है, उद्योगों के साथ जुड़ाव का नेतृत्व करता है, और क्षेत्र की कौशल परिषदों को संचालित करता है। **प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT):-** • DGT व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकास और समन्वय के लिए शीर्ष संगठन है। • यह प्रशिक्षण संस्थानों की कौशल प्रशिक्षण संरचनाओं को बनाए रखता है, प्रशिक्षण नीतियों पर सलाह देता है, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करता है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है, महिला-केंद्रित प्रशिक्षण संस्थान चलाता है, आदि। **अवश्य पढ़ें:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा **स्रोत:** PIB
विलफुल डिफॉल्टर्स	**संदर्भ:** हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने धोखाधड़ी में शामिल जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को अपने बकाया का निपटान करने के लिए संबंधित बैंकों के साथ समझौता करने की अनुमति दी है। **विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में:-** • आसान शब्दों में एक विल्फुल डिफ़ॉल्टर वह व्यक्ति है जो जान-बुझकर लिया गया ऋण वापस लौटाने नहीं चाहता है। एक विल्फुल डिफ़ॉल्टर एक इकाई या एक व्यक्ति हो सकता है जो है जो ऋण भरने के योग्य होने के बावजूद भी अपने ऋण का भुगतान नहीं करता। जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जाती है। • **आरबीआई के अनुसार जानबूझकर चूक तब होती है जब:-** ○ जब इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की हो, जबकि उसके पास इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता रहती है। ○ धन का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। जिसके लिए वित्त का लाभ उठाया गया था, बल्कि इसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ○ जिन्होंने सावधि ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से दी गई चल अचल संपत्ति या अचल संपत्ति का निपटान या हटा दिया है। **सरकार द्वारा कदम:-** • SARFAESI अधिनियम (वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूतियों के हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002):- ○ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, सुरक्षित संपत्तियों से जुड़े कई मामले शुरू किए गए हैं। ○ SARFAESI अधिनियम, 2002: जब कोई उधारकर्ता ऋण राशि चुकाने में विफल रहता है तो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण की रिकवरी के लिए वाणिज्यिक या आवासीय संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है। • **आरबीआई निर्देश:-** ○ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, जानबूझकर चूक करने वालों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधाएं स्वीकृत नहीं की जाती हैं, इनकी इकाई को 5 साल के लिए नए उद्यम शुरू करने से रोक दिया जाता है। ○ आवश्यकतानुसार आपराधिक कार्यवाही भी की जाती है।

	सेबी विनियम:- ○ जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले और ऐसी कंपनियां जिनके पास प्रमोटर या निदेशक के रूप में जानबूझकर चूक करने वाले लोग हैं, उन्हें धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। • **दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016:** इसने जानबूझकर चूक करने वालों को दिवाला समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया है। ○ **IBC 2016:** यह भारत का दिवालियापन कानून है, जो दिवालियापन और दिवालियापन के लिए एक एकल कानून बनाकर मौजूदा ढांचे को मजबूत करना चाहता है। • **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018:** यह अधिनियम भारतीय क्षेत्राधिकार से भागकर जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए बनाया गया था। ○ यह भगोड़े अपराधियों की संपत्ति की कुर्की और सीज़ तथा उन्हें किसी भी नागरिक दावे का बचाव करने से वंचित करने का प्रावधान करता है। ○ **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018:** इसका उद्देश्य उन आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करना है जो आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ चुके हैं या अभियोजन का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार कर रहे हैं। **अवश्य पढ़ें:** गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
चैंपियंस 2.0 पोर्टल	**संदर्भ:** हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री श्री नारायण राणे ने 'चैंपियंस 2.0 पोर्टल' लॉन्च किया। **पृष्ठभूमि:-** • अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME ने 'चैंपियंस 2.0 पोर्टल' लॉन्च किया। ○ **MSME दिवस:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 जून को "सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस" के रूप में नामित किया। ○ **उद्देश्य:** संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि में MSME के अद्भुत योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। **चैंपियंस 2.0 पोर्टल के बारे में:-** • चैंपियंस पोर्टल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक सिंगल विंडो शिकायत निवारण पोर्टल है। • **लॉन्च:** यह 1 जून, 2020 से। • **मंत्रालय:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। **नामपद्धति:** चैंपियंस यहां उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं के निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग के लिए स्टैंड है। • इसे हब और स्पोक मॉडल में बनाया गया है। ○ हब-एंड-स्पोक मॉडल: एक परिवहन या वितरण प्रणाली जो विभिन्न स्पोक या परिधीय स्थानों से वस्तु, व्यक्तिओं या सूचनाओं के प्रदान के लिए मुख्य बिंदु के रूप में एक केंद्रीय हब या नोड का उपयोग करती है। ○ हब: सचिव MSME के कार्यालय में नई दिल्ली में स्थित है। ○ स्पोक: राज्यों में मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में होंगे। • **उद्देश्य:-** • अपने क्लस्टर परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में MSME के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। • MSME की शिकायतों का त्वरित, सुविधाजनक और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना। • विभिन्न सरकारी योजनाओं/नीतियों के संचालन में MSME को सहायता प्रदान करना। • वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, कच्चा माल, श्रम, बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में मार्गदर्शन और

सलाहकार सेवाएं प्रदान करना। **(यूपीएससी सीएसई: एमएसएमई क्षेत्र के मुद्दे और चिंताएं)**

- MSME को मंत्रालय, राज्य सरकारों, ऋण देने वाली संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के प्रमुख अधिकारियों के साथ जोड़ना।
- MSME मंत्रालय की सभी योजनाओं की जानकारी और विवरण का प्रसार करना।

नई सुविधाएं:-

- संशोधित पोर्टल में अब एआई-संचालित चैटबॉट शामिल होंगे।
- यह हिंदी, गुजराती, बंगाली और कन्नड़ सहित 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा।
- पोर्टल में इसके विश्लेषण के लिए एक वास्तविक समय प्रतिक्रिया तंत्र भी होगा।
    - मोबाइल एप्लिकेशन के द्वारा जियो टैगिंग से परियोजनाओं की वास्तविक समय पर निगरानी, ट्रैकिंग और मूल्यांकन हो सकेगा, जिससे पारदर्शिता और प्रभावी संसाधन उपयोग सुनिश्चित होगा।
    - **जियोटैगिंग:** यह मेटाडेटा जोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल मैप में किसी स्थान के बारे में भौगोलिक जानकारी शामिल है।
    - डेटा में आमतौर पर अक्षांश और देशांतर निर्देशांक होते हैं।

अवश्य पढ़ें: MSME को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना

स्रोत: PIB

भूगोल

बैरेंट्स सागर

संदर्भ: भूवैज्ञानिकों ने नॉर्वे के तट से दूर बैरेंट्स सागर के तल पर एक पहले कभी न देखे गए ज्वालामुखी की खोज की है, जो ग्रह के आंतरिक भाग से कीचड़, तरल पदार्थ और गैस के साथ फूट रहा है।

बैरेंट्स सागर के बारे में:-

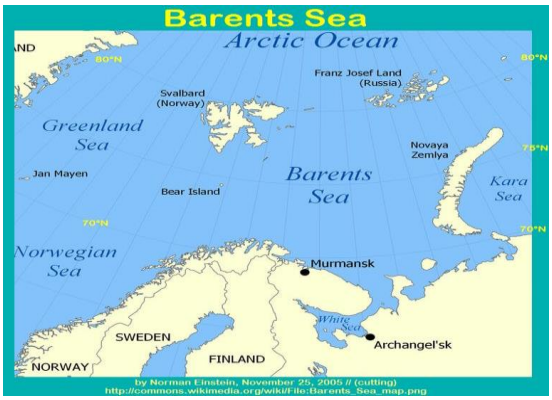

- बैरेंट्स सागर आर्कटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है।
- यह नॉर्वे और रूस के उत्तरी तट पर स्थित है।
- यह पश्चिम में नॉर्वेजियन और ग्रीनलैंड सागर, उत्तर में आर्कटिक सागर और पूर्व में कारा सागर से घिरा है।
- समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) द्वारा बैरेंट्स सागर को रूस और नॉर्वे के बीच विभाजित किया गया है।
- यह समुद्र वाइकिंग्स और मध्ययुगीन रूसियों के लिए मरमीन सागर के नाम से जाना जाता था।
- समुद्र का वर्तमान नाम ऐतिहासिक डच नाविक विलेम बैरेंटज़ के नाम पर है।
- **द्वीपीय भू-आकृतियों वाली सीमा:-**
    - यह उत्तर पश्चिम में स्वालबार्ड द्वीपसमूह, उत्तर पूर्व में फ्रांज जोसेफ लैंड द्वीप समूह, पूर्व में नोवाया ज़ेमल्या द्वीपसमूह, पश्चिम में नॉर्वेजियन सागर और ग्रीनलैंड सागर तथा दक्षिण में कोला प्रायद्वीप से घिरा है।

(यूपीएससी मेन्स: ज्वालामुखी विस्फोट से बनी भू-आकृतियाँ)

- यह कारा सागर से कारा जलडमरूमध्य और नोवाया ज़ेमल्या द्वीपसमूह द्वारा अलग किया गया है।
- समुद्र का सबसे गहरा बिंदु बियर आइलैंड ट्रेंच पर 600 m है। **(UPSC MAINS: ज्वालामुखी क्या है)**

अवश्य पढ़ें: भारत-रूस संबंध

स्रोत: इंडिया टुडे

नमक की गुफाएँ

संदर्भ: सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) राजस्थान में नमक गुफा आधारित सामरिक तेल भंडार विकसित करने की संभावनाओं और व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है।

नमक गुफाओं के बारे में:-

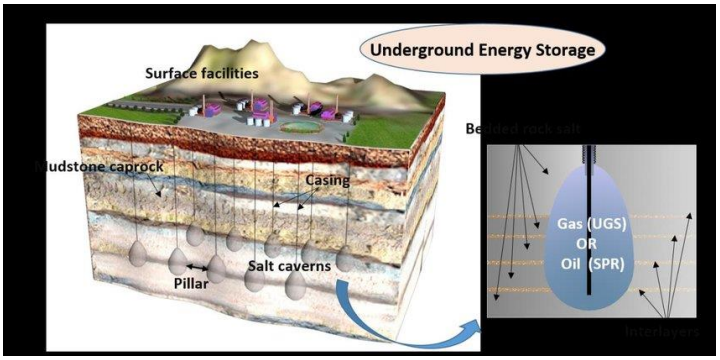

IMAGE SOURCE: ResearchGate

- नमक की गुफाएँ भूमिगत स्थान हैं जो नमक को जल में घोलकर (प्रक्रिया के माध्यम से) बनाई जाती है जिसे विलियन खनन (Solution Mining) कहा जाता है।
- इस पद्धति में नमक को घोलने एवं गुफाओं के निर्माण हेतु नमक भंडारित बड़े क्षेत्रों में जल को पंप किया जाता है। एक बार ब्राइन (जल में घुला हुआ नमक) निकाल देने के बाद इन गुफाओं का उपयोग कच्चे तेल को भंडारित करने के लिये किया जा सकता है।
- यह प्रक्रिया चट्टानी गुफाओं की खुदाई की तुलना में बहुत तेज और सस्ती है और इसे समतल या निचले इलाकों में किया जा सकता है जहां नमक का भंडार पाया जाता है।
    - **चट्टानी गुफाएँ:** वांछित भंडारण स्थान बनाने हेतु ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और चट्टान की परतों को हटाकर उत्खनित चट्टानी गुफाओं का निर्माण किया जाता है।

लाभ:

- नमक की गुफाएँ प्राकृतिक रूप से अच्छी तरह से सील्ड होती हैं।
- नमक की परत तरल और गैस प्रवास के विपरीत एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करती है, जो तेल को बाहर निकलने या भूजल को दूषित होने से बचाती है। **(यूपीएससी सीएसई: भूजल मानचित्रण)**
- इनमें तेल सोखने की क्षमता कम होती है, जो संग्रहीत तेल के रिसाव और संदूषण को रोकता है।
- इन्हें बनाना और संचालित करना अपेक्षाकृत आसान और सस्ता है।
- चट्टानी गुफाओं की खुदाई की तुलना में समाधान खनन की प्रक्रिया तेज़ और सरल है, जिसके लिए अधिक समय, श्रम और उपकरण की आवश्यकता होती है।
- वे प्राकृतिक गैस, संपीड़ित वायु (compressed air) और हाइड्रोजन के भंडारण के लिए उपयुक्त हैं। **(यूपीएससी सीएसई: LNG और इसका जलवायु प्रभाव)**
- नमक की गुफाएं चट्टानी गुफाओं की तुलना में सतह के करीब भी स्थित हो सकती हैं, जिससे ड्रिलिंग लागत और रिसाव का खतरा कम हो जाता है।
- नमक की गुफाएं उच्च दबाव और तापमान भिन्नता का सामना कर सकती हैं, जिससे तेल के तेजी से इंजेक्शन और निष्कर्षण को सक्षम किया जा सकता है।
- यह उन्हें आपात स्थिति या बाजार के उतार-चढ़ाव के लिए आदर्श बनाता है जब तेल को जल्दी से जारी करने या

	संग्रहीत करने की आवश्यकता होती है। **नुकसान:-** • नमक की गुफाओं को बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। • समाधान खनन के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को संक्षारण और बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए उपचारित किया जाना चाहिए, जिससे परिचालन लागत बढ़ जाती है। • नमकीन पानी (घुले हुए नमक वाला पानी) निकालने के बाद पानी को सुरक्षित निपटान भी करना पड़ता है, जो पर्यावरणीय चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। • नमकीन पानी में भारी धातु या रेडियोधर्मी तत्व जैसे हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं, जिन्हें सतही पानी में छोड़ने या गहरे कुओं में डालने से पहले निकालना पड़ता है। • नमक गुफाएँ नमक भंडार की उपलब्धता और गुणवत्ता के कारण सीमित हैं। **अवश्य पढ़ें:** सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) **स्रोत:** द इंडिन एक्सप्रेस
किलाउआ	**संदर्भ:** दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक, किलाउआ, हाल ही में फटना शुरू हो गया है। **इसके बारे में:-** • अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी को ग्रह पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। किलाउआ का शिखर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। • 1952 से अब तक यह 34 बार फट चुका है। 1983 से 2018 तक यह लगभग लगातार फट है। • यह एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है। • शील्ड ज्वालामुखी: यह ज्वालामुखी कम श्यानता, बहता हुआ लावा पैदा करता है जो स्रोत से बहुत दूर फैलता है और हल्का ढलान वाले ज्वालामुखी का निर्माण करता है। **किलाउआ ज्वालामुखी की विशेषताएँ:-** • इसका आकार गुंबद के समान है। • इसमें एक काल्डेराहै। • **काल्डेरा:** काल्डेरा, क्रेटर (यह ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः कीपाकार गर्तनुमा आकृति है) का ही विस्तृत रूप है। यह क्रेटर में धँसाव अथवा विस्फोटक उदगार से निर्मित स्थलरूप माना जाता है। क्रेटर के धँसाव से उसका आकार बड़ा हो जाता है व काल्डेरा का निर्माण होता है। • इसमें एक लावा झील है। • **लावा झील:** काल्डेरा के ऊपर पानी के निर्माण से निर्मित एक झील है। • किलाऊआ के पश्चिमी और उत्तरी ढलान इसके पास के ज्वालामुखी मौनालोआ के साथ विलय होते हैं। **(यूपीएससी सीएसई: माउंट मौना लोआ)**

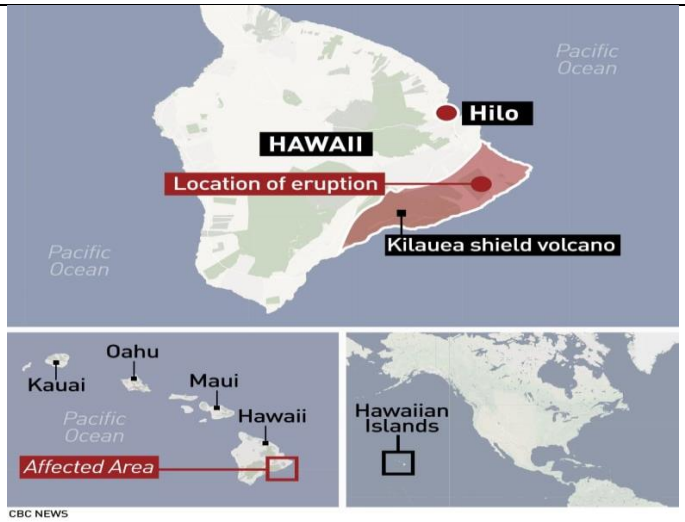

भारत में ज्वालामुखी:

- बैरन द्वीप, अंडमान द्वीप समूह (भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी)
- नारकोंडम, अंडमान द्वीप समूह
- बारातांग, अंडमान द्वीप समूह
- डेक्कन ट्रैप्स, महाराष्ट्र
- धिनोधर हिल्स, गुजरात
- धोसी हिल, हरियाणा

अवश्य पढ़ें: माउंट सेमरू ज्वालामुखी विस्फोट

स्रोत: द हिंदू

बिपरजॉय

संदर्भ: हाल ही में, पूर्व-मध्य अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय बना।

बिपरजॉय के बारे में:-

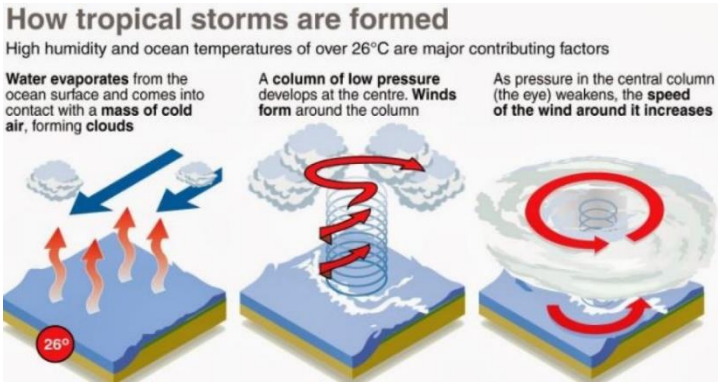

IMAGE SOURCE: Swarajya

- बिपरजॉय दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर बना एक गहरा दबाव था, जो तीव्र होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया।
- 'बिपरजॉय' नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। इसका अर्थ है 'त्रासदी' या 'आपदा'।

चक्रवातों का नामकरण:

- वर्ष 2000 में, WMO/ESCAP (विश्व मौसम विज्ञान संगठन/एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग) नामक राष्ट्रों का एक समूह, जिसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे, ने क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण शुरू करने का निर्णय लिया।
- WMO/ESCAP का विस्तार 2018 में पांच और देश ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को शामिल करके किया गया।

- प्रत्येक देश द्वारा अपने सुझाव भेजने के बाद, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO/ESCAP पैनल (PTC) चक्रवातों के नामों की सूची को अंतिम रूप देता है।
- अप्रैल 2020 में IMD द्वारा जारी 169 चक्रवात नामों की सूची में इन देशों द्वारा 13 देशों में से प्रत्येक से 13 सुझाव प्रदान किए गए थे।

चक्रवातों के नाम अपनाने हेतु दिशानिर्देश:

- प्रस्तावित नाम (A) राजनीति और राजनीतिक हस्तियों (B) धार्मिक विश्वास, (C) संस्कृतियों आदि के प्रति तटस्थ होना चाहिए।
- नाम इस तरह से चुनना होगा जिससे दुनिया भर में आबादी के किसी भी समूह की भावनाएं को आहत न पहुचें।
- यह स्वभाव से बहुत अभद्र और क्रूर नहीं होना चाहिए।
- यह संक्षिप्त और उच्चारण में आसान होना चाहिए।
- इसके नाम में अधिकतर आठ शब्द होने चाहिए।
- प्रस्तावित नाम उसके उच्चारण और वॉयसओवर सहित प्रदान किया जाना चाहिए।
- उत्तरी हिंद महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम दोहराए नहीं जाते है। एक बार उपयोग करने के बाद इसका दोबारा उपयोग बंद हो जाता है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- यह मौसम विज्ञान (मौसम), जलवायु विज्ञान (जलवायु), ऑपरेशनल जल विज्ञान (जल) और अन्य संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान जैसे समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय रसायन विज्ञान के लिए समर्पित है।
- वर्ष 1873 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (आईएमओ) इसका पूर्ववर्ती संगठन था।
- **सदस्यता:** इसके 192 सदस्य राज्य और क्षेत्र हैं। भारत WMO का सदस्य है।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- **रिपोर्ट:-**
  - ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन
  - विश्व जलवायु की स्थिति

अवश्य पढ़ें: अरब सागर में और चक्रवात

स्रोत: डाउन टू अर्थ

अनैक क्रैकटाऊ (Anak Krakatau) ज्वालामुखी

संदर्भ: हाल ही में इंडोनेशिया का अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी फट गया।

इसके बारे में:-

IMAGE SOURCE: ABC News

- यह जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीपों के बीच सुंडा जलडमरूमध्य में स्थित काल्डेरा में एक द्वीप है।
- **काल्डेरा:** यह एक बड़ा अवसाद है जो ज्वालामुखी के फटने और ढहने से बनता है।

	• **उत्पत्ति:** अनैक क्रैकटाऊ, जिसका अर्थ है क्रैकटाऊ का बच्चा, प्रसिद्ध क्रैकटाऊ ज्वालामुखी की संतान है, जिसके 1883 में हुए विशाल विस्फोट ने वैश्विक शीतलन का दौर शुरू हुआ। • वर्ष 1927 में, अनैक क्रैकटाऊ 1883 में विस्फोटक ज्वालामुखी से बने काल्डेरा से उभरा, जिसने क्राकाटोआ द्वीप को नष्ट कर दिया था। **(यूपीएससी सीएसई: माउंट सेमेरू में ज्वालामुखी विस्फोट)** • यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध उजंग कुलोन राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। **(यूपीएससी सीएसई: धोलावीरा: भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल)** **उजंग कुलोन राष्ट्रीय उद्यान** • यह इंडोनेशिया के बैंटन प्रांत में जावा द्वीप पर एक राष्ट्रीय उद्यान है। • इसे एक सींग वाले जावन गैंडे की अंतिम शरणस्थली के रूप में जाना जाता है। • छोटी पहाड़ियों और पठारों का एक सुदूर क्षेत्र, छोटे लैगून और तटीय टीलों के साथ, यह एक प्रायद्वीप पर 475 वर्ग मील (1,229 वर्ग किमी) और जावा के अधिकतम पश्चिमी सिरे पर कुछ द्वीपों पर फैला है। • यह पार्क सुंडा जलडमरूमध्य का सामना करता है, जो जावा को सुमात्रा से अलग करता है, और इसमें प्रायद्वीप के उत्तर-पश्चिम में लगभग 6 मील (10 किमी) दूर पनैतन द्वीप भी शामिल है। • इसे 1921 में एक प्रकृति आरक्षित के रूप में अलग रखा गया था; राष्ट्रीय उद्यान 1980 में प्रस्तावित किया गया था और 1992 में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। • इस क्षेत्र को 1991 में विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। • उजुंग कुलोन नेशनल पार्क जावा पर लास्ट रमैनिंग लो-रिलीफ फारेस्ट (last remaining low-relief forest) की मेजबानी करता है, जिसमें फ़िकस और बैरिंगटनिया सहित प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ हैं। • यह पार्क 60 से भी कम जावन गैंडों का घर है, यह एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो अवैध शिकार और बीमारी के कारण खतरे में है। • पार्क में अन्य उल्लेखनीय प्रजातियों में बैंटेंग (एक प्रकार का जंगली मवेशी), जावन गिब्बन, लंगूर (लीफ बंदर), मंटजैक (भौंकने वाला हिरण), शेवरोटेन (माउस हिरण), मगरमच्छ, ग्रीन टर्टल्स, ग्रीन मोर और जंगल फाउल शामिल हैं। दुर्भाग्य से, माना जाता है कि जावन बाघ जो कभी इस क्षेत्र में निवास करते थे, हाल के दिनों में विलुप्त हो गए हैं। **अवश्य पढ़ें:** गैंडे **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट	**संदर्भ:** लक्षद्वीप का न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट बड़ी सफलता साबित हुआ है। **न्यूट्री गार्डन परियोजना के बारे में:-** • न्यूट्री गार्डन का एक प्रमुख उद्देश्य ताजा सब्जियां कीटनाशी रहित सब्जियां उगाना है। • इसे इस प्रकार लगाया जाता है कि परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ सब्जियां प्राप्त होती रहे। साथ ही घर के समूचे परिसर को एक सुंदर, स्वच्छ एवं शांत वातावरण प्रदान करता है। • यह अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत या सामुदायिक उपभोग के लिए पोषक तत्व से भरपूर फसलें उगाने का एक लागत प्रभावी मॉडल है। • **मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय • **शहरी क्षेत्रों में:** न्यूट्री किचन गार्डनिंग को रूफटॉप गार्डनिंग, टैरेस गार्डनिंग, वर्टिकल गार्डनिंग और कंटेनर गार्डनिंग के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। (यूपीएससी सीएसई: शहरी कृषि) • **ग्रामीण क्षेत्रों में:** घरों के पीछे भाग में न्यूट्री किचन गार्डन को बढ़ावा दिया जा सकता है। **न्यूट्री गार्डन के फायदे:-** • यह भोजन और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। • यह पूरक आय के स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है।

	• काटी गई फसलें ताजा और सुरक्षित (रसायन मुक्त) होती हैं। (यूपीएससी सीएसई: प्राकृतिक खेती) • यह एक स्थायी जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर अल्प-पोषण और अति-पोषण दोनों से निपटने में मदद करता है। **चुनौतियाँ:-** • न्यूट्री-गार्डन बनाने के लिए खाली जमीन, पानी और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का अभाव। • प्रशासन से अपर्याप्त धनराशि। **अवश्य पढ़ें:** पोषण स्मार्ट विलेज **स्रोत**: टाइम्स ऑफ इंडिया
जेलिफ़िश आकाशगंगा (JO206)	**संदर्भ:** हाल ही में, नासा ने जेलिफ़िश आकाशगंगा JO206 को प्रदर्शित करने वाली एक छवि जारी की जिसे हबल टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था। **जेलीफ़िश आकाशगंगा JO206:-** • यह हमारे ग्रह से लगभग 700 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड में फैला हुआ है। • यह कुंभ राशि में है। • जेलिफ़िश आकाशगंगाएँ उनके समुद्री नामों से मिलती-जुलती हैं और यह छवि में स्पष्ट है। • छवि में नीचे दाईं ओर चमकीले तारे के गठन के "स्पर्शक" दिखाई दे रहे हैं जो आकाशगंगा की मुख्य डिस्क का पता लगाते हैं। **एक्वेरियस कोंस्टेलेशन** • यह 12 कोंस्टेलेशन में से एक है। • नक्षत्र के नाम का अर्थ लैटिन में "जल-वाहक" (या "कप-वाहक") है। • यह आकाश के क्षेत्र में स्थित है जिसे कभी-कभी समुद्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी से जुड़े नामों के साथ कई अन्य नक्षत्र शामिल हैं। • यह 980 वर्ग डिग्री के क्षेत्र में व्याप्त आकाश का 10वां सबसे बड़ा तारामंडल है। • यह 15 विषुवतीय नक्षत्रों में से एक है। • यह दक्षिणी गोलार्ध (SQ4) के चौथे चतुर्भुज में स्थित है और अक्षांशों पर +65° और -90° के बीच देखा जा सकता है। **अवश्य पढ़ें:** भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
एन्सेलाडस	**संदर्भ:** हाल ही में, नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने 'शनि के चंद्रमा एन्सेलेडस' पर फॉस्फोरस की खोज की। **एन्सेलाडस के बारे में:-** 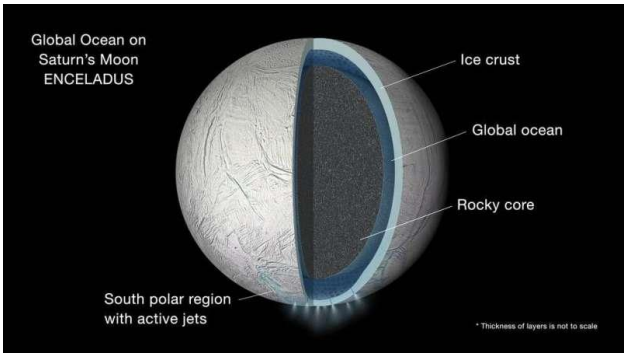 • एन्सेलाडस शनि का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है। • **खोज:** इसकी खोज 1789 में अंग्रेजी खगोलशास्त्री विलियम हर्शेल ने की थी। • **नाम की उत्पत्ति:** इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के दिग्गजों (गिगेंट्स) में से एक के नाम पर रखा गया था। • **सतह की विशेषताएं:** पुराने, भारी गड्ढों वाले क्षेत्रों से लेकर नये, विवर्तनिक रूप से विकृत इलाकों तक।

- यह ज्यादातर ताजी, साफ बर्फ से ढका हुआ है, जो इसे सौर मंडल के सबसे परावर्तक पिंडों में से एक बनाता है।
- यह शनि के प्रमुख नियमित चंद्रमाओं में से दूसरा निकटतम और इसके सभी चंद्रमाओं में सबसे चमकीला है।
- यह एक सक्रिय चंद्रमा है जो अपनी पपड़ी के नीचे तरल नमकीन पानी के वैश्विक महासागर को छुपाता है। (यूपीएससी सीएसई: यूएई का होप मिशन)

प्रमुख खुलासे:-

- **वर्ष 2005 में :** कैसिनी अंतरिक्ष यान ने दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र से निकलने वाले जल-समृद्ध प्लम्स की खोज की।
  - नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार, प्लम की संरचना धूमकेतुओं के समान होती है।
- **वर्ष 2014 में:** नासा ने बताया कि कैसिनी को तरल पानी के एक बड़े दक्षिण-ध्रुवीय उपसतह महासागर के प्रमाण मिले हैं।
  - इसकी मोटाई लगभग 10 किमी थी।
- **वर्ष 2021 में :** खगोलविदों ने मीथेन की पर्याप्त मात्रा का पता लगने की जानकारी दी।
  - यह एन्सेलाडस पर सूक्ष्मजीवी जीवन का संभावित संकेत हो सकता है।

कैसिनी अंतरिक्ष यान

- यह वर्ष 1997 में लॉन्च किया गया।
- **द्वारा लॉन्च किया गया:** नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA)
  - यह अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैमानिकी अनुसंधान और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है।
- **मिशन की समय अवधि:** इसने 2004 से 2017 तक शनि की कक्षा में 294 बार ग्रह की परिक्रमा की।
- इसने शनि के वायुमंडल और छल्लों की संरचना की माप की, साथ ही वे ग्रह के चंद्रमाओं के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं।
- इसने छह नामित चंद्रमाओं की भी खोज की और एन्सेलेडस तथा टाइटन को अलौकिक जीवन की खोज के लिए आशाजनक स्थानों के रूप में प्रदर्शित किया।
  - **टाइटन:** शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा।
  - यह पर्याप्त वातावरण वाला सौर मंडल का एकमात्र चंद्रमा है।

अवश्य पढ़ें: गगनयान

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र

संदर्भ: इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) की एक हालिया रिपोर्ट में हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र में ग्लेशियर का तेजी से नुकसान हो रहा है।

हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के बारे में:-

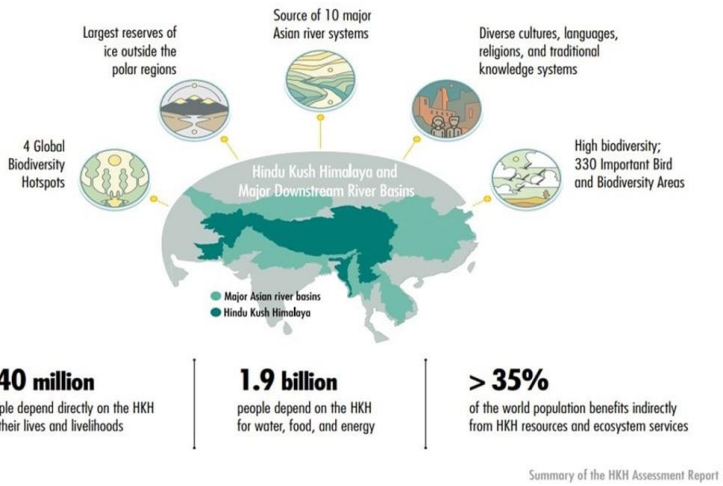

IMAGE SOURCE: THE THIRD POLE

- हिंदू कुश मध्य एशिया की एक विशाल पर्वतीय प्रणाली है।
- यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान तक फैला हुआ है।
- यह मध्य एशिया के महान जलक्षेत्रों में से एक है।
- यह विशाल अल्पाइन क्षेत्र का एक हिस्सा है जो पूर्व से पश्चिम तक यूरेशिया में फैला हुआ है।
- यह उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम तक चलती है और उत्तर में अमु दरिया (प्राचीन ऑक्सस नदी) की घाटी को सिंधु नदी घाटी से दक्षिण तक विभाजित करती है।
- **पूर्व में हिंदू कुश:** उस बिंदु के पास पामीर रेंज स्थित है जहां चीन, पाकिस्तानी-नियंत्रित कश्मीर और अफगानिस्तान की सीमाएं मिलती हैं।
- **दक्षिण-पश्चिम में:** यह पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान तक जाती है, अंत में पश्चिमी अफगानिस्तान में छोटी श्रेणियों में विलीन हो जाती है।
- सबसे ऊंची चोटी माउंट तिरिच मीर है।
    - यह पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के पास 25,230 फीट (7,690 मीटर) तक ऊँचा है।
- **तीसरा ध्रुव (Third Pole):** हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र को कभी-कभी दुनिया का "तीसरा ध्रुव" कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक हिम बर्फ होती है।
- इसमें दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ शामिल हैं।
- यह 10 प्रमुख नदियों का स्रोत है और एक भयावह वैश्विक पारिस्थितिक बफर बनाता है।
- इस क्षेत्र में 1,106 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आईबीए) हैं, जो इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% कवर करते हैं।
    - IBA: मानक वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग करके पहचाने गए पक्षियों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल है।

महत्व:-

- सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता: यह 600 से अधिक भाषाएँ और कई बोलियाँ बोलने वाले कई अलग-अलग जातीय समुदायों का घर है।
- **पारिस्थितिकी:** यह समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और इसमें चार वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के सभी या कुछ हिस्से शामिल हैं। (यूपीएससी सीएसई: जलवायु परिवर्तन को कम करना)
    - इनमें हिमालय हॉटस्पॉट, इंडो-बर्मा हॉटस्पॉट, दक्षिण-पश्चिम चीन के पर्वत और मध्य एशिया के पर्वत शामिल हैं।
- **स्थानीय अर्थव्यवस्था:** ये पर्वतीय संसाधन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला और क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आजीविका का आधार प्रदान करते हैं।
- **उद्गम नदियाँ:** कई लोग इन नदी घाटियों में उत्पादित भोजन और ऊर्जा से लाभान्वित होते हैं जिनका उद्गम पहाड़ों में होता है।

हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- पेड़ की पत्तियों का गिरना और फल लगने के समय में बदलाव हुआ है।
    - इससे पौधों के अस्तित्व में कमी आई है और प्रजातियों की भेद्यता को खतरा उत्पन्न हुआ है।

  नेपाल और आसपास के HKH क्षेत्र में हिमालयी रोडोडेंड्रोन के उन्नत और फूलों का देरी से खिलना आदि देखे गए हैं।
- तापमान में वृद्धि के कारण बर्फबारी के पैटर्न में बदलाव के परिणामस्वरूप पेड़-पौधों की वृद्धि भी स्थानांतरित हुई है।
- भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कई पौधों की प्रजातियाँ प्रति दशक 11 से 54 मीटर की दर से ऊपर की ओर स्थानांतरित हुई हैं।
- सिक्किम हिमालय में लगभग 90 प्रतिशत स्थानिक प्रजातियाँ 27.53 से 22.04 मीटर प्रति दशक की दर से

	विस्थापित हुई हैं। • पूर्वी लद्दाख के उत्तर-पश्चिमी हिमालय में पाई जाने वाली कई प्रजातियाँ, पौधों की वितरण सीमा से लगभग 150 मीटर ऊपर की ओर बढ़ गई हैं। • 26 आक्रामक पौधों की प्रजातियों में से 5 प्रतिशत का विस्तार हुआ है जबकि 25 प्रतिशत कम हो गए है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा को खतरा है। ○ आक्रामक या विदेशी प्रजाति एक ऐसे वातावरण में लाई गई प्रजाति है जो अधिक घनी वाली हो जाती है और अपने नए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। • इससे जीव-जंतुओं की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। • स्तनधारी, कीड़े, सूक्ष्म जीव, पक्षी, उभयचर और मछलियाँ विलुप्त हो रहे हैं या आनुवंशिक और व्यवहारिक परिवर्तनों का अनुभव कर रहे हैं। • हिमालयी कस्तूरी मृग, सुनहरे नाक वाले बंदर और हिमालयी ग्रे लंगूर पहले ही घटती आबादी के साथ सीमा परिवर्तन का अनुभव कर चुके हैं। • सिक्किम हिमालय में मोनोकल्ड और किंग कोबरा 1,000 मीटर से 1,700 मीटर तक ऊंचे चले गए हैं। • पाकिस्तान में, मुरी पहाड़ियों और पड़ोसी क्षेत्रों में रहने वाली तितलियों की 14 प्रजातियों के गायब होने की जानकारी मिली है। **एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICIMOD)** • ICIMOD एक अंतरसरकारी ज्ञान और शिक्षण केंद्र है। • **स्थापना:** वर्ष 1983 में • **मुख्यालय:** ललितपुर, नेपाल • **उद्देश्य:** यह हिंदू कुश-हिमालयी क्षेत्र के आठ क्षेत्रीय सदस्य देशों में लोगों को सशक्त बनाने के लिए शोध, सूचना और नवाचारों को विकसित और साझा करता है। • **सदस्य:** अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। **ICIMOD के कार्य:-** • यह सूचना और ज्ञान सृजन के माध्यम से क्षेत्र की सेवा करता है। (यूपीएससी सीएसई: जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) • यह महत्वपूर्ण पर्वतीय समस्याओं के नवीन समाधान खोजने के लिए साझाकरण में शामिल है। • यह नीतियों और जमीनी प्रथाओं के बीच एक गठबंधन के रूप में कार्य करता है। • यह एक क्षेत्रीय मंच प्रदान करता है जहां विशेषज्ञ, योजनाकार, नीति निर्माता और व्यवसायी सतत पर्वतीय विकास की उपलब्धि के लिए विचारों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। • यह पूरे क्षेत्र में ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। • यह अंतरराष्ट्रीय ज्ञान को अनुकूलित करने और इसे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में मदद करता है। • यह क्षेत्रीय मुद्दों को वैश्विक मंच पर लाने में मदद करता है। **MUST READ:Water bomb in the Himalayas** **SOURCE: DOWN TO EARTH**
विक्टोरिया झील	**संदर्भ:** पूर्वी अफ्रीका में लेक विक्टोरिया बेसिन (LVB) भारी बारिश, तूफान और बाढ़ से महत्वपूर्ण खतरों का सामना कर रहा है, जिससे क्षेत्र के समुदायों और स्थानिक जैव विविधता पर प्रतिकूल परिणाम हो रहे हैं। **विक्टोरिया झील बेसिन (एलवीबी) के बारे में:-**

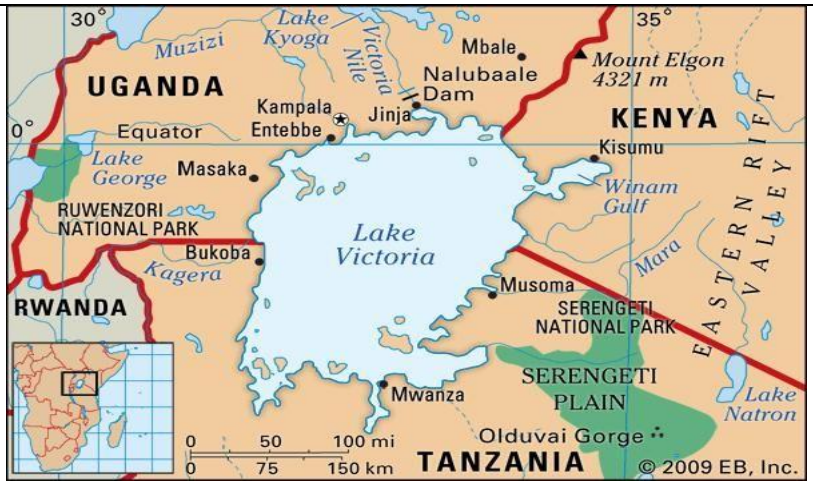

IMAGE SOURCE: Britannica

- लेक विक्टोरिया बेसिन (एलवीबी) नील नदी बेसिन की ऊपरी पहुंच में स्थित है। **(यूपीएससी सीएसई:चिलिका झील)**
- इसमें झीलों, आर्द्रभूमियों और नदियों का दुनिया का सबसे बड़ा परिसर शामिल है।
- **जलग्रहण क्षेत्र:** लगभग 194,200 वर्ग किमी।
- यह तंजानिया (44%) सहित पांच पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या (22%); युगांडा (16%); रवांडा (11%) और बुरुंडी (7%) से होकर गुजरती है।

महत्व:-

- यह बेसिन एक प्रमुख पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक भूमिका निभाता है और पूर्वी अफ्रीका समुदाय (ईएसी) के विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के लिए केंद्रीय है।
- यह मत्स्य पालन, जैव विविधता, नदियों और आर्द्रभूमि के व्यापक नेटवर्क, जंगलों, उपजाऊ मिट्टी, वन्य जीवन, खनिज, पर्यटन, मल्टीमॉडल परिवहन और संचार जैसे संसाधनों से समृद्ध है।
- बेसिन स्थानीय लोगों को आजीविका प्रदान करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेसिन के आसपास प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं।
- इस बेसिन में निवेश की अपार संभावनाएं हैं।

विक्टोरिया झील

- यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
- यह अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
- यह सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। (यूपीएससी सीएसई: विक्टोरिया झील की जल गुणवत्ता का प्रबंधन)
- यह नील नदी का प्रमुख जलाशय है।
  - नील: यह विश्व की सबसे लंबी नदी है।
- **सीमावर्ती देश:** केन्या (6%), तंजानिया (51%) और युगांडा (43%)।
  - इसका प्रसार क्षेत्र बुरुंडी और रवांडा के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है।
- यह अपनी उच्च स्तरीय अद्वितीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है।

अवश्य पढ़ें: सावा झील

स्रोत: डाउन टू अर्थ

महादायी नदी

संदर्भ: हाल ही में, महादयी नदी पर कलसा बंडूरी परियोजना के लिए जारी की गई निविदाओं को सफलता नहीं मिली है।

पृष्ठभूमि:-

- विवादास्पद कलासा बंडूरी योजना के कार्यान्वयन के लिए निविदाएं कर्नाटक विधानसभा चुनावों की घोषणा से कुछ मिनट पहले पिछली भाजपा सरकार द्वारा जारी की गई थीं।

- उन्हें वन और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना बाहर रखा गया था।
- निविदाएं 21 अगस्त 2023 तक बोली लगाने के लिए खुली हैं, लेकिन खरीदार मिलने की संभावना नहीं है।

महादायी नदी के बारे में:-

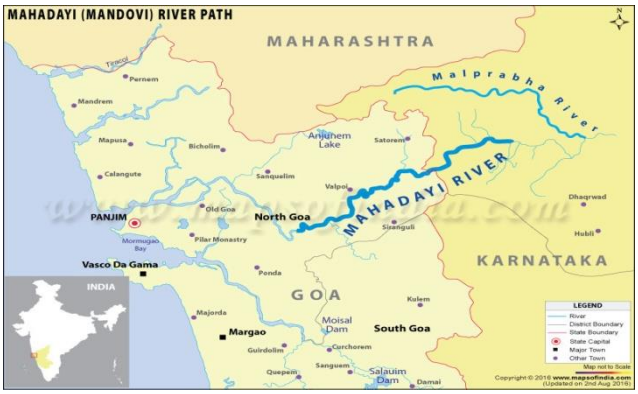

IMAGE SOURCE: MapsofIndia

- महादायी नदी को मांडोवी नदी के नाम से भी जाना जाता है।
- **उत्पत्ति:** इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बेलगाम जिले में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से पश्चिमी घाट में होती है।
- **अंतिम छोर:** अरब सागर में गिरने से पहले यह लगभग 81 किमी तक बहती है।
- यह नदी दो नदियों दद्दी और मार्कंडेय के संगम से बनी है।
- **बाएं तट की सहायक नदियाँ:** दद्दी नदी, मालाप्रभा नदी और मार्कंडेय नदी।
- **दाएं तट की सहायक नदियाँ:** ताम्बरापरानी नदी, बैनगंगा नदी, वर्धा नदी।
- **महादयी नदी पर बांध:-**
  - **हिडकल बांध:** कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित है।
  - **सेलौलीम बांध:** दक्षिण गोवा में स्थित है।
- **विरदी बांध:** कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित है
- सलीम अली पक्षी अभयारण्य चोराओ द्वीप (island of Chorao) पर स्थित है, जो मांडोवी नदी में स्थित है।
- **महत्व:** महादायी नदी गोवा और कर्नाटक राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पीने, सिंचाई और पर्यटन के लिए जल के स्रोत के रूप में काम करती है।

कलसा-बंडूरी नाला परियोजना

- यह कर्नाटक सरकार की एक परियोजना है।
- वर्ष 1989 में यह योजना बनाई गई।
- **उद्देश्य:** कर्नाटक के बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट और गडग जिलों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए महादयी से पानी को मोड़ना।
- इसमें पानी को मालप्रभा नदी की ओर मोड़ने के लिए महादयी नदी की दो सहायक नदियों कलसा और बंदुरी पर बांध बनाना शामिल है।

कलसा-बंडूरी नाला परियोजना विवाद पृष्ठभूमि

- **वर्ष 1989 में :** इस परियोजना की योजना कर्नाटक सरकार द्वारा बनाई गई थी।
- **वर्ष 2002 में :** प्रस्ताव के ढाई दशक बाद, केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया।
- **गोवा का रुख:** इसने केंद्र से मिलकर और नदी में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करके, तीन बेसिन राज्यों: गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक को पानी आवंटित करने का आग्रह किया।
- गोवा में विरोध प्रदर्शन के कारण तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस परियोजना को रोक दिया था।

	• **वर्ष 2006:** वर्ष 2006 में विवाद तब तूल पकड़ लिया जब कर्नाटक में गठबंधन सरकार ने इस परियोजना पर काम शुरू करने का फैसला किया। • इसके बाद गोवा ने जल-बंटवारे विवाद को निपटाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। • महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। • गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र ट्रिब्यूनल के पक्षकार हैं। • **वर्ष 2018:** ट्रिब्यूनल ने महादयी नदी बेसिन से कर्नाटक को 13.42 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी), महाराष्ट्र को 1.33 टीएमसी और गोवा को 24 टीएमसी पानी दिया। • **वर्ष 2019:** ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद, गोवा ने आवंटन की मात्रा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। • **वर्ष 2020:** गोवा ने SC के समक्ष अवमानना याचिका दायर की, जिसमें कर्नाटक पर महादयी बेसिन से अवैध रूप से पानी निकालने का आरोप लगाया गया। (यूपीएससी सीएसई: महादायी नदी विवाद पर गोवा विपक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही बाधित की) • **वर्ष 2023:** गोवा और महाराष्ट्र सरकार ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे जल मोड़ परियोजना के संबंध में कर्नाटक के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। **MUST READ:** Mahadayi Water Row **SOURCE:** THE HINDU
भारतीय मौसम विभाग	**संदर्भ:** हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। **पृष्ठभूमि:-** • भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, विदर्भ और कोंकण में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। • नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है। • प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों के किनारे न जाने की अपील की है। **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में:-** • **स्थापना:** वर्ष 1875 में • **मंत्रालय:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय • **आईएमडी मुख्यालय:** नई दिल्ली • यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है। • यह मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। **उद्देश्य:-** • कृषि, सिंचाई, शिपिंग आदि जैसी मौसम-संवेदनशील गतिविधियों के इष्टतम संचालन के लिए मौसम संबंधी अवलोकन करना और वर्तमान और पूर्वानुमानित मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना। • गंभीर मौसमी घटनाओं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, धूल भरी आंधी, भारी बारिश और बर्फ, ठंड और गर्मी की लहरों आदि के खिलाफ चेतावनी देने के लिए, जो जीवन और संपत्ति के विनाश का कारण बनते हैं। • मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों में अनुसंधान का संचालन और प्रचार करना। • कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योग, तेल की खोज और अन्य राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक मौसम संबंधी आँकड़े प्रदान करना। **IMD चार रंग कोड का उपयोग करता है:-** • **हरा (सब ठीक है):** कोई सलाह जारी नहीं की गई है। (यूपीएससी सीएसई: रंग कोडित मौसम चेतावनी)

	• **पीला रंग-** इस रंग का मतलब होता है तैयार रहें स्थिति खराब हो सकती है। पीला रंग कई दिनों से खराब मौसम का संकेत देता है। • **नारंगी रंग-** ऑरेंज अलर्ट तब जारी किया जाता है जब सड़क और रेल यात्रा जैसे आवागमन में बाधा उत्तपन्न हो, साथ ही बिजली की आपूर्ति में रुकावट के साथ बेहद खराब मौसम की चेतावनी के रूप में इसे जारी किया जाता है। नारंगी चेतावनी (ऑरेंज अलर्ट) का मतलब होता है कि आप अपनी जगह को खाली करने के लिए तैयार रहें और अपने साथ भोजन के पैकेट तैयार रखें। • **लाल रंग (कार्रवाई करें):** जब बेहद खराब मौसम की स्थिति निश्चित रूप से यात्रा को बाधित करती है और बिजली की सप्लाई को भी प्रभावित करती है और ऐसी स्थिति में जीवन को भी महत्वपूर्ण खतरा होता है तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है। **अवश्य पढ़ें:** भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) नए मानसून मॉडल प्रस्तुत करना **स्रोत:** AIR
भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए)	**संदर्भ:** भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के हालिया अध्ययनों ने इस बात की स्पष्ट तस्वीर दी है कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अंतरग्रहीय चुंबकीय स्थान को कैसे प्रभावित करता है। **अध्ययन और उसके निष्कर्षों के बारे में:-** • इस अध्ययन की मदद से वैज्ञानिक अब सौर माध्य चुंबकीय क्षेत्र (source of solar mean magnetic field-SMMF) के स्रोत की पहचान करने के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। ○ SMMF: दृश्य गोलार्ध पर औसत सौर वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के लाइन-ऑफ़-विज़न (एलओएस) घटक का औसत मूल्य और साथ ही इंटरप्लेनेटरी चुंबकीय क्षेत्र (आईएमएफ) के साथ इसका संबंध है। ○ IMF: यह सौर पवन द्वारा अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष तक खींचे गए कोरोनल चुंबकीय क्षेत्र का विस्तार है। ○ LOS: यह दो बिंदुओं के बीच का सीधा पथ है। • वैज्ञानिकों ने क्रोमोस्फेरिक ऊंचाइयों पर SMMF और फोटोस्फेरिक ऊंचाइयों पर SMMF के बीच बहुत अच्छी समानता पाई है। • क्रोमोस्फेरिक SMMF का मान फोटोस्फेरिक SMMF से कम है। • इससे पता चलता है कि सूर्य के अंदर मौलिक चुंबकीय क्षेत्र SMMF का स्रोत हो सकता है। **डेटा तकनीक:-** • इसने फोटोस्फेरिक माप के साथ क्रोमोस्फीयर में चुंबकीय क्षेत्र माप का उपयोग करके SMMF की गणना और विश्लेषण किया। ○ **क्रोमोस्फीयर:** क्रोमोस्फीयर एक तारे (या सूर्य) के प्रकाशमंडल के ऊपर गैस की एक लाल और चमकदार परत है। ○ **प्रकाशमंडल:** प्रकाशमंडल सूर्य की दृश्यमान सतह है और वह परत है जिससे सूर्य का अधिकांश प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। • ये विद्युत धाराएँ सूर्य के संवहन क्षेत्र में गर्म, आयनित गैसों के प्रवाह से उत्पन्न होती हैं। ○ सूर्य का संवहन क्षेत्र: यह सूर्य के आंतरिक भाग की सबसे बाहरी परत है। ○ यह परत प्रकाशमंडल तक लगभग 200,000 किमी तक फैली हुई है। **भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के बारे में:-** • भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और संबंधित भौतिकी में अनुसंधान के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:- ○ इसकी उत्पत्ति 1786 में मद्रास में स्थापित एक वेधशाला से मानी जाती है। ○ वर्ष 1792 से इसके नुंगमबक्कम परिसर में मद्रास वेधशाला के रूप में औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू हुआ।

- **वर्ष 1899 में :** यह वेधशाला कोडाइकनाल में स्थानांतरित कर दी गई।
- **वर्ष 1971 में :** कोडाइकनाल वेधशाला एक स्वायत्त सोसाइटी बन गई, और इसे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के रूप में जाना जाने लगा।

- **मुख्यालय:** बेंगलुरु
- **मंत्रालय:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- **वित्त पोषण:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित।
- **मुख्य अवलोकन सुविधाएं:** कोडाइकनाल, कवलूर, गौरीबिदानूर और हानले।
- कवलुर में वेनु बप्पू वेधशाला 1960 के दशक के उत्तरार्ध से रात्रिकालीन खगोल विज्ञान (nighttime astronomy) के लिए संस्थान की मुख्य ऑप्टिकल वेधशाला रही है।
  - यहां कई दूरबीनें कार्यरत हैं, इनमें से सबसे प्रमुख 2.34-मीटर वेनु बप्पू टेलीस्कोप है।
- कोडाइकनाल वेधशाला एक शताब्दी से अधिक समय से अवलोकन संबंधी सौर और वायुमंडलीय भौतिकी में गतिविधि का प्रमुख केंद्र रही है। (यूपीएससी सीएसई: गगनयान)

अवश्य पढ़ें: भारतीय अंतरिक्ष संघ

स्रोत: द हिंदू

पर्यावरण

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

संदर्भ: हाल ही में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बस्तर स्थित विख्यात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में अब दुर्लभ प्रजाति 'माउस डियर'की तस्वीर कैमरा ट्रेप में कैद हुई है।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:-

- कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित है।
- इसे वर्ष 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। **(यूपीएससी सीएसई: पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड))**
- इसका नाम यहां से बहने वाली कांगेर नदी के नाम पर पड़ा है।
- कुडप्पा समूह की चट्टानें, साथ ही विंध्यन चट्टानें समूह, पार्क में सबसे प्रचलित चट्टानें हैं।
- छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी, बस्तर हिल मैना, इस क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है। यह मानव आवाज़ की नकल कर सकती है।
- कुटुंबसर, कैलाश और दंडक पार्क में तीन गुफाएं हैं, जो स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स की भूवैज्ञानिक विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं।
- **जीव-जंतु:** इसमें बाघ, तेंदुआ, माउस डियर, रीसस मकाक, सुस्त भालू, उड़ने वाली गिलहरी, चीतल, सांभर, बार्किंग

	हिरण, अजगर, कोबरा, सांप आदि पाए जाते हैं। (यूपीएससी सीएसई: छत्तीसगढ़ का राज्य पशु, जंगली भैंसा, विलुप्त होने के करीब) • **वनस्पतियां:** सागौन, हल्दू, साल, तेंदू, महुआ, साजा, बीजा, धावरा, तिन्सा, महुलबेल, अमरबेल, बंधा आदि। **इंडियन माउस डियर:** • इसे इंडियन स्पॉटेड शेवरोटेन के नाम से भी जाना जाता है। • यह भारत, श्रीलंका और नेपाल में पाया जाता है। • यह भारत का सबसे छोटा हिरण है और अत्यधिक रात्रिचर होता है। • **संरक्षण की स्थिति** ○ **IUCN रेड लिस्ट:** कम चिंताजनक (Least Concern)। **अवश्य पढ़ें: इंद्रावती टाइगर रिजर्व** **स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया**
हिमालयी भूरा भालू	**संदर्भ:** हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि अतिक्रमण हिमालयी भूरे भालूओं को कश्मीर के गांवों में धकेलता (pushing) है। **इनके बारे में:-** • **वितरण:** यह मख्य रूप से उत्तर-पश्चिमी और मध्य हिमालय, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन का तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र और भूटान शामिल हैं। • **पर्यावास:** उच्च ऊंचाई वाली खुली घाटियाँ और घास के मैदान। • **संरक्षण की स्थिति:-** ○ IUCN लाल सूची- गंभीर रूप से संकटग्रस्त ○ CITES - परिशिष्ट I ○ रतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 - अनुसूची 1 **(यूपीएससी सीएसई: भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई)** • **भोजन :** सर्वाहारी • **खतरा:** मानव-पशु संघर्ष, तेजी से निवास स्थान का नुकसान, फर, पंजे और अंगों के लिए अवैध शिकार और, कुछ दुर्लभ मामलों में, भालू को खाना। **अवश्य पढ़ें:** एशियाई काला भालू **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
पेट कोक	**संदर्भ:** सरकार ने हाल ही में लिथियम-आयन बैटरी के लिए कच्चे माल के रूप में पेट कोक के आयात की अनुमति दी है। **पेट कोक के बारे में:-** • पेट कोक तेल शोधन प्रक्रिया से प्राप्त एक कार्बनयुक्त उत्पाद है।

	• ईंधन के साथ-साथ इसका उपयोग लिथियम-आयन बैटरियों के निर्माण के लिये भी किया जाता है।
	• यह तेल के आसवन विधि से निर्मित एक स्पंजी, ठोस उपोत्पाद है जिसे कोयले के समान ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
	• यह गहरे रंग का ठोस कार्बन पदार्थ है।
	• इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए ऊर्जा और कार्बन के स्रोत के रूप में किया जाता है।
	  ○ भारत में सीमेंट, स्टील और कपड़ा जैसे कई विनिर्माण उद्योगों में इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है।
	• यह कोयले की तुलना में काफी सस्ता है, इसमें उच्च कैलोरी मान है और परिवहन और भंडारण करना आसान है।
	• तेल शोधन के दौरान दो प्रकार के पेट कोक का उत्पादन किया जाता है।
	  ○ ईंधन-ग्रेड पेट कोक (80%) और
	  ○ कैलक्लाइंड पेट कोक (20%)
	• भारत दुनिया में पेट कोक का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। (यूपीएससी सीएसई: रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर))
	• **स्थानीय उत्पादक:** इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन।
	• भारत में सीमेंट कंपनियाँ देश के पेट कोक उपयोग का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा बनाती हैं।
	पेट कोक के पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे:-
	• पेट कोक कोयले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली प्रदूषक है।
	• इसमें 74,000 PPM की भारी मात्रा में सल्फर सामग्री होती है, जो उत्सर्जन के रूप में वायुमंडल में छोड़ी जाती है, यह वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से कहीं अधिक है।
	• यह महीन धूल का भी एक स्रोत है, जो मानव श्वसन मार्ग के माध्यम से प्रवेश कर सकता है और फेफड़ों में जमा हो सकता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
	• यह सल्फर, नाइट्रस ऑक्साइड, पारा, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल और हाइड्रोजन क्लोराइड निकलता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में इसकी अधिकता बढ़ जाती है। (यूपीएससी सीएसई: COP 27)।
	लिथियम
	• यह एक नरम, चांदी-सफेद धातु है।
	• यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है।
	• इसमें किसी भी ठोस तत्व की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता सबसे अधिक होती है।
	• यह विद्युत का सुचालक है।
	• यह ज्वलनशील है और हवा तथा पानी के संपर्क में आने पर विस्फोट भी सकता है।
	• लिथियम, लिथियम-आयन रिचार्जेबल बैटरियों का एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक है।
	• वर्तमान में, भारत इन सेलों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है और लिथियम के लिए इंक सोर्सिंग समझौते के कदम को चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के कदम के रूप में देखा जाता है, जो कच्चे माल और सेल दोनों का एक प्रमुख स्रोत है।
	अवश्य पढ़ें: पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) देश
	स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

पर्यावरण संबंधी जानकारी, जागरूकता, क्षमता निर्माण एवं आजीविका कार्यक्रम	**संदर्भ:** भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने मिशन लाइफ पर जोर देते हुए विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाए जाने की परिकल्पना की है। **इसके बारे में:-** • यह एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना है जिसे मिशन LiFE के साथ संरेखण में कार्यान्वित किया जा रहा है। **(यूपीएससी सीएसई: ईआईएसीपी)**

(ईआईएसीपी)

- **मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)
- वर्ष 2023 में, पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) का नाम बदलकर EIACP (पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम) कर दिया गया।
    - पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS): वर्ष 1983 में अस्तित्व में आया।
        - पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) का ध्यान पूरे देश में निर्णय निर्माताओं, नीति नियोजकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं आदि को पर्यावरणीय जानकारी प्रदान करना था।
- EIACP को मिशन LiFE के साथ संरेखण में लागू किया जा रहा है। **(UPSC CSE: LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली)**
- **उद्देश्य:** यह पर्यावरणीय जानकारी के प्रसार, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर सूचित नीति निर्माण और हरित कौशल के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका की सुविधा के लिए वन-स्टॉप मंच के रूप में कार्य करता है।
- वर्तमान जन सहभागिता अभियान के एक भाग के रूप में करीब 60 ईआईएसीपी केंद्र सक्रिय रूप से स्थायी जीवनशैली के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, जिसे नागरिक अपना सकते हैं।

पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (EEP)

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना है।
- **उद्देश्य:** स्कूलों और कॉलेजों में इको-क्लब गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अन्य पहलों के माध्यम से अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा प्रदान करना।
- एक स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने के सामान्य लक्ष्य को साझा करना।
- **कार्यान्वयन:** इसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से मिशन लाइफ के साथ पूर्ण संरेखण में कार्यान्वित किया जाता है।
- ईईपी की कार्यान्वयन एजेंसियों ने प्राकृतिक शिविर, इको-कला कार्यशाला, चिकनी मिट्टी और साधारण मिट्टी के बर्तनों की कार्यशाला, इको-फ्रेंडली ग्रीन वेडिंग आइडियाज को बढ़ावा देना, औषधीय पौधों के लिए जागरूकता अभियान, इको क्लब के छात्रों की मदद से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ समाज में अभियान चलना, पेंटिंग प्रतियोगिता, हस्ताक्षर लेना, मिशन लाइफ के संदेशों के साथ नाम व स्टिकर का वितरण आदि जैसी कुछ बहुत ही अनूठी तथा पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों का आयोजन किया है।
- इको-क्लब का उपयोग LiFE पर संदेश फैलाने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में किया जाता है।

पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल (LiFE):-

- **पृष्ठभूमि:** 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC COP26) में, भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिशन LiFE की घोषणा की।
- **उद्देश्य:** व्यक्तिगत व्यवहार को वैश्विक जलवायु कार्रवाई आख्यान में सबसे आगे लाना।
- LiFE की परिकल्पना प्रचलित 'उपयोग और निपटान' अर्थव्यवस्था को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था से बदलने की है, जिसे सावधानीपूर्वक और जानबूझकर उपयोग द्वारा परिभाषित किया जाएगा।
- **दृष्टिकोण:-**
    - **व्यक्तिगत व्यवहार पर ध्यान देना:** व्यक्तियों और समुदायों के व्यवहार और दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करके जीवन को एक जन आंदोलन (जन आंदोलन) बनाना।
    - **विश्व स्तर पर सह-निर्माण करना:** शीर्ष विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिमागों (best minds of the world) से अनुभवजन्य (empirical) और स्केलेबल विचारों को क्राउडसोर्स करना।
    - **स्थानीय संस्कृतियों का लाभ उठाना:** अभियान को चलाने के लिए दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों के जलवायु-अनुकूल सामाजिक मानदंडों, विश्वासों और दैनिक घरेलू प्रथाओं का लाभ उठाना।
- **उद्देश्य:-**

	○ इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली को बढ़ावा देना है जो 'नासमझ और बेकार उपभोग' के बजाय 'सावधान और जानबूझकर उपयोग' पर केंद्रित है। ○ इसका उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का उपयोग करना है। ○ इसका उद्देश्य दुनिया भर के व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल जलवायु-अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। ○ मिशन की योजना व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और उसका पोषण करने की है, जिसका नाम 'प्रो-प्लैनेट पीपल' (P3) है। ▪ यह पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। ○ यह जलवायु के आसपास के सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए सामाजिक नेटवर्क की शक्ति का लाभ उठाने का प्रयास करता है। **अवश्य पढ़ें:** राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम **स्रोत:** पीआईबी
मन्नार की खाड़ी	**संदर्भ:** मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। **मन्नार की खाड़ी के बारे में:-** 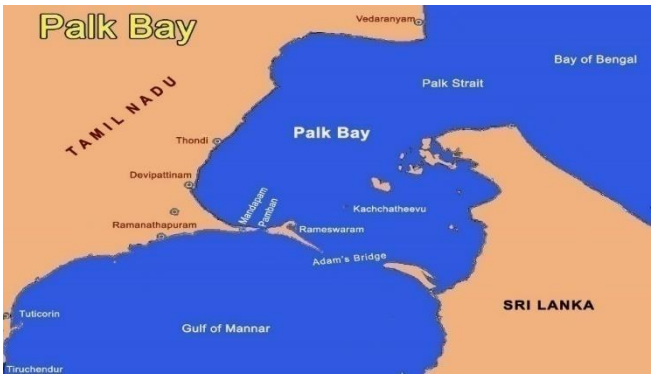 **IMAGE SOURCE:** casmbenvis. nic. in • मन्नार की खाड़ी दक्षिणपूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार है। • यह उत्तर-पूर्व में रामेश्वरम (द्वीप), एडम्स ब्रिज (आदम का पुल), और मन्नार द्वीप से घिरा है। • इस खाड़ी में कई नदियाँ मिलती हैं, जिनमें ताम्ब्रापर्णी (भारत) और अरुवी (श्रीलंका) शामिल हैं। • तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। • यह अपने अत्यधिक उत्पादक मोती बैंकों (pearl banks) और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। • भारत सरकार ने 1989 में इसे देश के पहले समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया। • मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान को इसके समृद्ध पक्षी जीवों के कारण BNHS-बर्डलाइफ़ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी पहचाना गया है। • मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी को इसकी डुगोंग आबादी और अन्य समुद्री स्तनधारियों की उपस्थिति के कारण IUCN द्वारा विश्व के एक महत्वपूर्ण समुद्री स्तनधारी क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। **मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाले प्रमुख जीवन रूप:-** • **डुगोंग (समुद्री गाय):** जिसे 'समुद्री गाय' भी कहा जाता है, यह ऑर्डर सिरेनिया में चार जीवित प्रजातियों में से एक है और यह शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है जो विशेष रूप से समुद्र में रहती है। (यूपीएससी प्रीलिम्स: भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व) ○ **संरक्षण स्थिति:-** ▪ **IUCN लाल सूची स्थिति:** असुरक्षित (Vulnerable) ▪ **वन्य (जीवन) संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची I

	▪ **CITES:** परिशिष्ट I • **समुद्री कछुए:** दुनिया भर में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की सात प्रजातियों में से चार मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में पाए जाते है। • **ये हैं:-** ▪ ओलिव रिडले (लेपिडोचिल्स ओलिवेसिया): IUCN स्थिति (असुरक्षित) ▪ ये अपने अनूठे सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं जिन्हें अरिबाडा कहा जाता है, जहां हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं। ▪ गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य: यह ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है। ○ ग्रीन (चेलोनिअमाइडस) ○ हॉक्सबिल (एरेटमोचेलीस इम्ब्रिकाटा) ○ लेदरबैक (डर्मोचेलिस कोरियासिया) • इन तटीय जल में पाई जाने वाली समुद्री कछुओं की सभी चार प्रजातियाँ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) की अनुसूची I के तहत संरक्षित हैं, साथ ही वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन (CITES) के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है। • **झींगा मछली:** इस क्षेत्र में पैनुलिरस होमरस और पी पॉलीफेगस झींगा मछलियों का स्टॉक बढ़ाना और उन्हें मोटा करना तटीय मछुआरों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। • **केकड़े (Crabs):** भारत के 11 महत्वपूर्ण व्यावसायिक केकड़ों में से छह केकड़े की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। • **समुद्री साँप:** मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री साँपों की कुल 12 प्रजातियाँ बताई गई हैं। • **तटीय पक्षी:** मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी से पक्षियों की 187 प्रजातियाँ दर्ज की गई। • **मूंगा चट्टान पारिस्थितिकी तंत्र:-** ○ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी के मूंगे और मूंगे की चट्टानें एक आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं, जो विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री जीवन का समर्थन करती हैं। (यूपीएससी सीएसई: कोरल रीफ्स) ○ मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी में द्वीपों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है, मंडपम समूह (सात द्वीप), कीलाकराई समूह (7 द्वीप) और तूतीकोरिन समूह (7 द्वीप)। **अवश्य पढ़ें:** ग्रेट निकोबार का विकास **स्रोत:** AIR
अमचांग वन्यजीव अभयारण्य	**संदर्भ:** हाल ही में, भारतीय सेना ने असम के अमचांग वन्यजीव अभयारण्य में जंगली हाथियों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए एक अद्वितीय इकोसिस्टम तंत्र तैयार किया। **अमचांग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:-** • अमचांग वन्यजीव अभयारण्य असम के गुवाहाटी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। • इसमें तीन आरक्षित वन शामिल हैं:- ○ खानापारा ○ अमचांग, और ○ दक्षिण अमचांग • यह उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर दक्षिण में मेघालय के पहाड़ी जंगलों तक फैला है, जो मेघालय के मराडकडोला रिजर्व वनों के माध्यम से एक सतत वन बेल्ट बनाता है। (यूपीएससी मुख्य परीक्षा: ब्रह्मपुत्र पर चीन के चाल की निगरानी) • असम सरकार द्वारा 2004 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। (यूपीएससी मेन्स: मानव-वन्यजीव संघर्ष)

- **वनस्पतियां:** खासी पहाड़ी में साल वन, पूर्वी हिमालयी मिश्रित पर्णपाती वन, पूर्वी जलोढ़ माध्यमिक अर्ध-सदाबहार वन और पूर्वी हिमालयी साल वन।
- **जीव-जंतु:** यह स्तनधारियों (फ्लाइंग फॉक्स, असमिया मकाक, स्लो लोरिस, आदि), पक्षियों (छोटे और बड़े एडजुटेंट, सफेद पीठ वाले गिद्ध, स्लेंडर-बिल्ड गिद्ध), सरीसृप (पायथन, मॉनिटर छिपकली, भारतीय कोबरा आदि) का घर है।
- **ट्री येलो बटरफ्लाई (बनाना हरिना):** ये अमचांग वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती हैं, जो थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और पूर्वोत्तर भारत की मूल निवासी हैं।

अवश्य पढ़ें: तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य

स्रोत: THE PRINT

जमीनी स्तर पर ओजोन प्रदूषण

संदर्भ: सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्से इस गर्मी में जमीनी स्तर के ओजोन प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।

ओजोन प्रदूषण

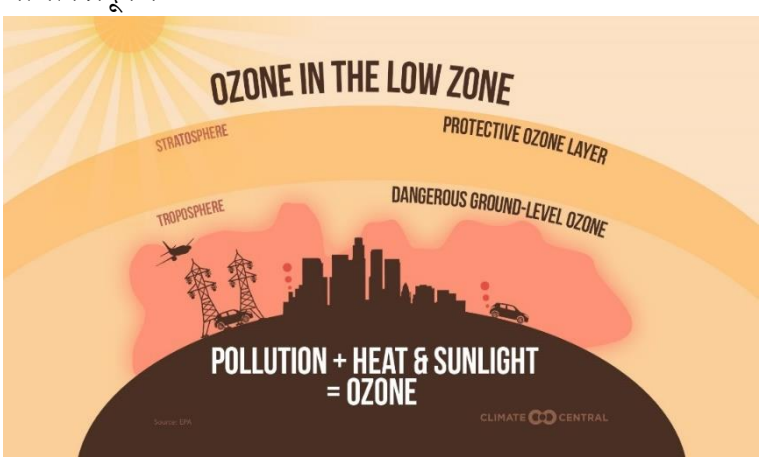

IMAGE SOURCE: Climate Central

- ओजोन पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल (समतापमंडल) और जमीनी स्तर (क्षोभमंडल) दोनों में होता है।
- यह अच्छा या खराब हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कहाँ पाया जाता है।
- **अच्छा ओजोन:** ओजोन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल (स्ट्रैटोस्फियर) में होता है।
- यह एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है।
- क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी), एचसीएफसी और हेलोन (halons) जैसी ओजोन-क्षयकारी गैसें इस सुरक्षा कवच को नष्ट कर देती हैं और ओजोन में होल का कारण बनती हैं।
- **खराब ओजोन:** पृथ्वी के निचले वायुमंडल (क्षोभमंडल) में जमीनी स्तर के पास पाया जाता है।
- यह तब बनता है जब कार, बिजली संयंत्र, औद्योगिक बॉयलर, रिफाइनरियों, रासायनिक संयंत्रों और अन्य स्रोतों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं।
- यह एक हानिकारक वायु प्रदूषक है। (यूपीएससी सीएसई: वायु प्रदूषण)
- इससे फसलों और जंगलों को नुकसान होता है।
- यह क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) जैसी फेफड़ों के सूजन के जोखिम और संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है।
- इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता कम हो सकती है और सांस लेना मुश्किल हो सकता है।

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई) के बारे में:-

- इसकी स्थापना 1980 में हुई थी
- यह एक सार्वजनिक-हित अनुसंधान और वकालत संगठन है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली

	• यह भारत में पर्यावरण-विकास के मुद्दों पर एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। • यह ऐसे विकास की तात्कालिकता पर शोध, सिफारिश और संचार करता है जो टिकाऊ और न्यायसंगत दोनों हो। • यह समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करता है और स्थायी समाधान प्रस्तावित करता है। • वर्ष 2018 में, सीएसई को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। **अवश्य पढ़ें:** वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भारत की कठिन लड़ाई **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (ANERT)	**संदर्भ:** केरल राज्य सरकार ने हाल ही में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (एएनईआरटी) को ग्रीन हाइड्रोजन पहल के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। **इसके बारे में:-** • ANERT केरल राज्य के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति का मसौदा तैयार करने और प्रकाशित करने वाली एकल नोडल एजेंसी है। (यूपीएससी सीएसई: ग्रीन हाइड्रोजन) • सरकार द्वारा नियुक्त एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ANERT का प्रमुख होता है। • **अध्यक्ष:** बिजली मंत्री • **पर्यवेक्षण:** ANERT निम्नलिखित द्वारा निर्देशित होता है:- ○ शासी निकाय- इसकी अध्यक्षता केरल के बिजली मंत्री करते हैं। ○ कार्यकारी समिति- इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव, सरकार/प्रमुख सचिव द्वारा की जाती है। • बिजली विभाग, केरल सरकार विभिन्न ऊर्जा-संबंधित क्षेत्रों में ANERT की गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है। **ANERT के उद्देश्य:-** • केरल राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से परियोजनाओं की पहचान करना, तैयार करना, कार्यान्वयन करना। • सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ऊर्जा वृक्षारोपण, सूक्ष्म और लघु जलविद्युत परियोजनाएं, बेहतर चूल्हे आदि के दोहन पर आधारित दीर्घकालिक योजनाएं विकसित करना। • उत्पादन के स्रोत, वितरण की स्थिति और/या इसके उपयोग पर ऊर्जा के संरक्षण सहित एक व्यापक-आधारित ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम की पहचान करना, तैयार करना, कार्यान्वित करना और कार्यान्वयन का समर्थन करना। • ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, ऊर्जा संरक्षण और ग्रामीण प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने और जागरूकता पैदा करने के लिए तकनीकी, वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करना। • ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों, ऊर्जा संरक्षण और ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार कार्यशालाएं आदि शुरू करना या प्रायोजित करना। • ऊर्जा और ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के वैकल्पिक और नए स्रोतों के क्षेत्र में प्रोटोटाइप, पायलट प्लांट जांच आदि के विकास से जुड़े विकास प्रकृति के अनुसंधान कार्यक्रमों या परियोजनाओं को प्रायोजित, समन्वयित या बढ़ावा देना, और **ANERT के अंतर्गत कार्यक्रम:-** • सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम • पवन ऊर्जा • सौर तापीय कार्यक्रम • बेहतर चूल्हे (Improved chulhas) • प्रशिक्षण और विस्तार • अन्य कार्यक्रम • बायोएनेर्जी **ग्रीन हाइड्रोजन**

	• ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। • बिजली की मदद से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। • इसे 'हरित हाइड्रोजन' कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई कार्बन पदचिह्न नहीं होता है। • **हाइड्रोजन के अन्य प्रकार:-** ○ **ब्राउन हाइड्रोजन:** ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है जहाँ उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। (यूपीएससी सीएसई: कोयला आधारित हाइड्रोजन) ○ **ब्लू हाइड्रोजन:** ब्लू हाइड्रोजन (Blue Hydrogen) की उत्पत्ति प्राकृतिक गैस से होती है, जहाँ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। **भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व:-** • ग्रीन हाइड्रोजन भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। • भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा महत्वपूर्ण है। ○ पेरिस जलवायु समझौते के तहत, भारत ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33-35% तक कम करने का वादा किया है। • यह जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करता है। • इलेक्ट्रोलाइज़र उत्पादन का स्थानीयकरण और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं का विकास भारत में 18-20 बिलियन डॉलर का एक नया हरित प्रौद्योगिकी बाजार और हजारों नौकरियां उत्पन्न कर सकता है। (यूपीएससी सीएसई: राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन) **अवश्य पढ़ें:** भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया **स्रोत:** द हिंदू
उत्तरी बंगाल के जंगली ऑर्किड	**संदर्भ:** हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि उत्तरी बंगाल के जंगली ऑर्किड चिंताजनक दर से नष्ट हो रहे हैं। **इसके बारे में:-** • ऑर्किड आकर्षक फूल वाले और रंगीन पौधे हैं। • वे अपने जीवंत और दुर्लभ फूलों के लिए जाने जाते हैं। (यूपीएससी सीएसई: अरुणाचल ऑर्किड की रेड-लिस्टिंग शुरू करेगा) • **स्थान:** वे दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, जिनमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पहाड़ और यहां तक कि रेगिस्तान भी शामिल हैं। • भारत में ऑर्किड की 1200 से अधिक प्रजातियां हैं (388 भारत के लिए स्थानिक हैं, जिनमें से 128 पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक हैं)। ○ **स्थानिक:** इसका मतलब कोई पौधा या जानवर जो मूल निवासी है और एक निश्चित स्थान तक ही सीमित है। **उत्तरी बंगाल के जंगली ऑर्किड की सुरक्षा स्थिति:-** **CITES: परिशिष्ट II** **ऑर्किड के प्रकार** **एपिफाइटिक ऑर्किड (Epiphytic Orchids):-** • ये किसी अन्य पौधे पर उगने वाले पौधे हैं जिनमें चट्टानी जगहों पर उगने वाले पौधे भी शामिल हैं और इन्हें अक्सर लिथोफाइट्स कहा जाता है। • भारत में पाए जाने वाले सभी ऑर्किड में से लगभग 60% एपिफाइटिक हैं। **स्थलीय ऑर्किड (Terrestrial Orchids):-** • ये भूमि पर उगने तथा चढ़ने वाले पौधे हैं।

	• भारत में 447 प्रजातियाँ स्थलीय हैं। • ये सीधे मिट्टी पर उगते हैं और समशीतोष्ण और अल्पाइन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। **माइकोहेटरोट्रॉफ़िक ऑर्किड (Mycoheterotrophic Orchids):-** • ये ऐसे पौधे हैं जो संवहनी पौधे की जड़ों से जुड़े माइकोरिज़ल कवक से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। **वितरण:-** • **हिमालय क्षेत्र:** ऑर्किड प्रजातियों में सबसे समृद्ध। • **पूर्वोत्तर भारत:** उच्चतम प्रजाति सघनता। • **पश्चिमी घाट:** ऑर्किड की उच्च स्थानिकता। • **आर्किड प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या:** अरुणाचल प्रदेश> सिक्किम> पश्चिम बंगाल। **उपयोग:-** • सौंदर्य प्रयोजनों के लिए • हर्बल चिकित्सा में • वेनिला का उत्पादन वेनिला प्लैनिफ़ोलिया ऑर्किड से होता है। **अवश्य पढ़ें:** परजीवी फूल वाले पौधे की नई प्रजाति **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
एग्री बाय-प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए नए मानक	**संदर्भ:** हाल ही में, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एग्री बाय-प्रोडक्ट से बने भोजन परोसने वाले बर्तनों के लिए नए मानक जारी किए हैं। **इनके बारे में:** • इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और स्थिरता को बढ़ावा देना है। **लाभ:-** • इस मानक के लागू होने के व्यापक फायदे हैं क्योंकि बायोडिग्रेडेबल एग्री बाय-प्रोडक्ट बर्तनों के उपयोग से पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। • इन बर्तनों में किसी नुकसानदेह पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं का कल्याण सुनिश्चित होता है। • यह मानक किसानों के लिए आर्थिक अवसर सृजित करता है और सस्टेनेबल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण विकास में योगदान करता है। • भारत में, कई बड़े पैमाने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्तर के निर्माता बायोडिग्रेडेबल कटलरी के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं, उन्हें इस मानक से काफी लाभ होगा। **भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में:-** • बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। **(यूपीएससी सीएसई: बीआईएस)** • इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। • यह मूल रूप से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत अधिनियमित किया गया था। • एक नया अधिनियम (1986 के बीआईएस अधिनियम को बदलने के लिए) लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे बाद में 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। • **मुख्यालय:** नई दिल्ली • **मंत्रालय:** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। • **क्षेत्रीय कार्यालय:** कोलकाता (पूर्वी), चेन्नई (दक्षिणी), मुंबई (पश्चिमी), चंडीगढ़ (उत्तरी) और दिल्ली (मध्य)। **अवश्य पढ़ें:** भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)
कांगो वर्षावन	**संदर्भ:** हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि कांगो वर्षावन लगातार लुप्त हो रहे हैं और वर्ष 2022 में पांच लाख हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाने की संभावना है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:-

- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने 2022 में पांच लाख हेक्टेयर से अधिक प्राथमिक वन क्षेत्र को खो दिया।
- वनों के नुकसान की यह दर हाल के वर्षों में लगातार बढ़ रही है।
- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) को 2022 में 500,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का नुकसान हुआ।
- इसमें कहा गया है कि पिछले साल दुनिया भर में 4.1 mha प्राथमिक उष्णकटिबंधीय वन नष्ट हो गए।
    - इसमें से, ब्राजील में कुल उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वन हानि का 43 प्रतिशत हिस्सा है, इसके बाद डीआरसी (12.1 प्रतिशत) और बोलीविया का स्थान है।
- प्राकृतिक वनों के इस विनाश से 2.7 बिलियन टन CO2 उत्पन्न हुई।
- इस अवधि के दौरान DRC में आर्द्र प्राथमिक वनों का कुल क्षेत्रफल 6.1 प्रतिशत कम हो गया।
    - **प्राथमिक वन:** देशी वृक्ष प्रजातियों के वन, जहाँ मानवीय गतिविधियों के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलते।
- रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश प्राथमिक वन हानि में चक्रीय कृषि क्षेत्रों के निकट छोटी-छोटी कटाई शामिल है।
    - **चक्रीय कृषि क्षेत्र:** वह भूमि जो फसलों की अल्पकालिक खेती के लिए साफ की जाती है (काटकर जलाओ तकनीकों का उपयोग करके) और जंगलों तथा मिट्टी के पोषक तत्वों को पुनर्जीवित करने के लिए परती (fallow) छोड़ दी जाती है।
- आर्थिक कारक वनों की कटाई को प्रेरित कर सकते हैं।
- अधिकांश कांगोवासी अपने भोजन और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों पर निर्भर हैं और इस प्रकार क्षेत्र में प्राथमिक वन हानि को कम करना एक चुनौती बनी हुई है।
- डीआरसी में वन हानि के कारणों में काटने और जलाने वाली कृषि, अनियंत्रित झाड़ियों की आग, स्थानीय और क्षेत्रीय बाजारों के लिए लकड़ी का कोयला उत्पादन, पशुपालन और अवैध (कारीगर) कटाई शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में चारकोल ऊर्जा का प्रमुख रूप है, जो लकड़ी काटने और जलाने से उत्पन्न होता है।

कांगो वर्षावन के बारे में:-

IMAGE SOURCE: adlance22.blogspot.com

- कांगो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। (UPSC MAINS: अफ्रीका में भारत की हिस्सेदारी)
    - विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन अमेज़न है।
- **सीमावर्ती देश:** कांगो वर्षावन में छह अफ्रीकी देश शामिल हैं:-कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC), इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन।
- **जलवायु:** यहां साल भर उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है, जिसमें भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता एवं तापमान होता है।
- **पौधे:** इसमें लगभग 10,000 उष्णकटिबंधीय पौधे हैं, जो इस क्षेत्र के लिए 30% अद्वितीय हैं।
- **वन्यजीव:** यहां स्तनधारियों की 400 प्रजातियाँ, 600 से अधिक पेड़ों की प्रजातियाँ, 10,000 जानवरों की प्रजातियाँ, 1,000 पक्षियों की प्रजातियाँ और 700 मछली की प्रजातियाँ भी हैं।
    - इसमें जंगली हाथी, चिंपैंजी और बोनोबोस जैसे लुप्तप्राय वन्यजीव शामिल हैं।
- **आर्थिक महत्व:** कांगो बेसिन 75 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन, औषधि , जल, सामग्री और आश्रय प्रदान

	करता है। • **मानव निवासी:** 150 से अधिक जातीय समूह 50,000 से अधिक वर्षों से कांगो वर्षावन क्षेत्र में रह रहे हैं। • इन जातीय समूहों में, बा'अका (Ba'Aka), बाका, बाम्बुटी, एफे और अन्य संबंधित समूहों को अक्सर पिग्मीज़ के रूप में जाना जाता है। ○ **पिग्मी:** किसी भी मानव समूह का सदस्य जिसके वयस्क पुरुषों की औसत ऊंचाई 59 इंच (150 सेमी) से कम होती है। ○ ये वर्षावन में जीवित रहने के लिए शिकार और संग्रहण पर निर्भर रहते हैं। **अवश्य पढ़ें:** भारत-अफ्रीका: चुनौतियाँ और आगे की राह **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व	**संदर्भ:** हाल ही में ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व के लिए नए ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। **पृष्ठभूमि:-** • वैश्विक एंड-टू-एंड आपूर्ति श्रृंखला समाधान प्रदाता डीपी वर्ल्ड ने हाल ही में महाराष्ट्र में ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व के लिए थर्मल ड्रोन प्रदान किए हैं। • ये ड्रोन जंगल की आग का पता लगाने और निगरानी तेज करने में मदद करने के लिए हैं। • वन क्षेत्र के कर्मचारियों को एक वर्ष के लिए ड्रोन के संचालन के लिए साइट पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।r **ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में:-** 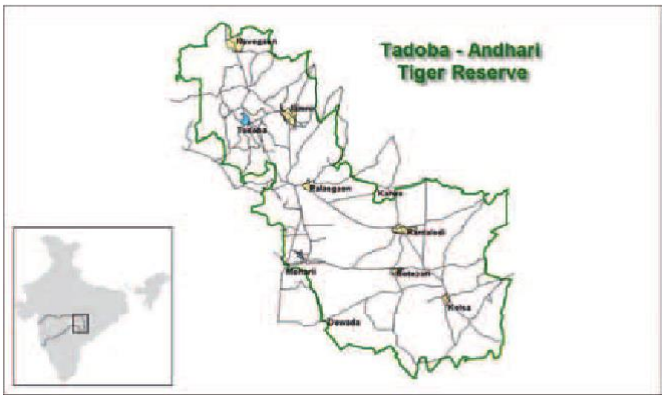 **IMAGE SOURCE:** ResearchGate • **स्थान:** महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिला। (यूपीएससी सीएसई: ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व) • **स्थापना:** 1993-94 में • यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। • यह भारत के 50 "प्रोजेक्ट टाइगर" में से एक है। • यह रिज़र्व महाराष्ट्र का दूसरा टाइगर रिज़र्व है। ○ राज्य में स्थापित पहला टाइगर रिजर्व मेलघाट टाइगर रिजर्व (1973-74) है। **जीव-जंतु:-** • **स्तनधारी:** भेड़िया, सियार, जंगली कुत्ते, लोमड़ी, लकड़बग्घा, चित्तीदार हिरण, जंगली सूअर, भौंकने वाला हिरण। • **पक्षी:** हनी बज़र्ड, शर्मीले जंगल फाउल (Shy Jungle Fowl), ग्रे-हेडेड फिशिंग ईगल। **वनस्पतियां :-** • **वनस्पति:** घने जंगलों के साथ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ○ इसमें संरक्षित क्षेत्र का लगभग 27 प्रतिशत शामिल है। • इनमें सागौन प्रमुख वृक्ष प्रजाति है। • **अन्य:** बांस, ऐन, बीजा, धौदाब, हल्दू, सलाई, सेमल, शीशम, सिसू, सूर्या, सिरस। **अवश्य पढ़ें:** वैश्विक संरक्षण आश्वासन|बाघ मानक (CA|TS)

	स्रोत: बिजनेस लाइन
ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी)	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'ग्रीन क्रेडिट' के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है। **पृष्ठभूमि:-** ● मंत्रालय ने 26 जून, 2023 को जारी एक अधिसूचना में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियम 2023 का मसौदा प्रस्तावित किया। ● इसमें 60 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के बारे में:-** ● **लॉन्च किया गया :** वर्ष 2023 ○ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में "ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम" (जीसीपी) लॉन्च किया था। ● **उद्देश्य:** ग्रीन क्रेडिट के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करके वनीकरण कार्यक्रम और जल संरक्षण जैसी पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक बाजार-आधारित तंत्र बनाना। ○ **ग्रीन क्रेडिट:** 'ग्रीन क्रेडिट' का अर्थ है किसी निर्दिष्ट गतिविधि के लिये प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एकल इकाई, इसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक ऐसे तंत्र के रूप में है जो घरेलू कार्बन बाज़ार के पूरक के रूप में कार्य करता है। ● **मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ● विभिन्न हितधारकों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। ● यह कार्रवाई करके निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा, जो ग्रीन क्रेडिट जनरेट करने या खरीदने से संबंधित गतिविधियों के साथ जुड़ने में सक्षम हैं। **GCP की शासन संरचना:-** **GCP प्रशासक** ● भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) GCP का प्रशासक होगा। ○ **ICFRE:** यह MoEFCC के तहत एक स्वायत्त संगठन या सरकारी एजेंसी है। ○ इसका उद्देश्य वानिकी अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से पारिस्थितिक सुरक्षा, बेहतर उत्पादकता, आजीविका वृद्धि और वन संसाधनों के सतत उपयोग के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकियों को उत्पन्न करना, आगे बढ़ाना और प्रसारित करना है। ● यह पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन, निगरानी और संचालन करेगा। **संचालन समिति** ● इसे जीसीपी को संस्थागत बनाने की प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों को मंजूरी देने के लिए स्थापित किया जाएगा। ● यह ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश करेगा। ● यह जीसीपी के कार्यान्वयन की लागत और व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से शुल्क और इसके प्रकार तथा राशि का भी निर्धारण करेगा। **जीसीपी का कार्य:-** ● जीसीपी प्रशासक पर्यावरण मुआवजा एकत्र करेगा और इसे एक अलग समर्पित खाते में जमा करेगा। ● इस निधि का उपयोग जीसीपी के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा। ● उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में वृक्षारोपण करता है, वह ग्रीन क्रेडिट अर्जित कर सकता है, जिसे वह संचालन समिति द्वारा सत्यापन के बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बेच सकता है। **जीसीपी के लाभ:-** ● यह वनों को एक वस्तु के रूप में व्यापार करने की अनुमति देता है।

	• यह वन विभाग को पुनर्वनीकरण की अपनी जिम्मेदारियों में से एक को गैर-सरकारी एजेंसियों को आउटसोर्स करने की अनुमति देता है। • यह पारंपरिक वन क्षेत्र के बाहर व्यक्तियों द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करेगा। • यह सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगा। **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
हिमालय पर्वत	**संदर्भ:** एक हालिया अध्ययन के अनुसार, हिमालय व उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ों में हर एक डिग्री तापमान बढ़ने से 15 फीसदी अधिक बारिश होने की संभावना है। **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:-** • नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तरी गोलार्ध के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी से लेकर बारिश तक में बदलाव हो सकता है, जिससे बारिश की चरम सीमा कुछ घंटों से लेकर एक दिन तक बढ़ सकती है। • दुनिया भर में तापमान दो डिग्री होने से 30 प्रतिशत और तीन डिग्री की वृद्धि होने से 45 प्रतिशत तक बारिश में वृद्धि देखी जा सकती है। • बर्फबारी के बजाय बारिश होने के इस बदलाव के कारण बाढ़, भूस्खलन और मिट्टी के कटाव जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। • हालांकि सभी पर्वतीय क्षेत्र खतरे में नहीं हैं। ○ निष्कर्षों से पता चला है कि हिमालय और उत्तरी अमेरिकी प्रशांत पर्वत श्रृंखलाएं, जिनमें कैस्केड, सिएरा नेवादा और कनाडा से दक्षिणी कैलिफोर्निया तक की तटीय श्रृंखलाएं शामिल हैं, रॉकी या आल्प्स की तुलना में अधिक खतरे में हैं। ○ **कैस्केड:** यह पर्वत श्रृंखला पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की प्रशांत पर्वत प्रणाली का एक खंड है। ○ **सिएरा नेवादा:** यह पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जो अमेरिकी राज्य कैलिफ़ोर्निया के पूर्वी किनारे पर फैली हुई है। ○ **रॉकी पर्वत:** वे कनाडा में उत्तरी अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको तक फैले हुए हैं। ○ **आल्प्स:** एक असंतुलित पर्वत श्रृंखला का एक छोटा खंड जो उत्तरी अफ्रीका के एटलस पर्वत से लेकर दक्षिणी यूरोप और एशिया तक हिमालय से बाहर तक फैला हुआ है। • हिमालय उन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है जहां हम अत्यधिक वर्षा का खतरा बढ़ा हुआ देखते हैं। **हिमालय पर्वत के बारे में:-** **IMAGE SOURCE:** jfb-levage.com • ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। • ये पश्चिम में पामीर नॉट से शुरू होती है। • और अंत: पूर्व में पूर्वांचल तक चलती है।

- **प्रमुख चोटियाँ:** माउंट एवरेस्ट, काराकोरा (K2), कैलाश, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और मानसक्लू।

हिमालय का निर्माण:-

- हिमालय भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने का परिणाम है।
- क्रेटेशियस काल के दौरान भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना से अलग हुआ और उत्तर की ओर बढ़ने लगा।
    - **गोंडवाना:** प्राचीन महाद्वीप जिसमें वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है।
- दो प्लेटों के बीच, टेथिस सागर सिकुड़ गया, जिससे एक जियोसिंक्लाइन बन गया।
    - **जियोसिंक्लाइन:** पृथ्वी की पपड़ी में एक बड़े पैमाने पर अवसाद जिसमें बहुत मोटी जमा राशि होती है।
    - **टेथिस सागर:** मेसोज़ोइक युग और प्रारंभिक सेनोज़ोइक युग के दौरान एक प्रागैतिहासिक महासागर, जो गोंडवाना और लौरेशिया के प्राचीन महाद्वीपों के बीच स्थित था।
- जैसे ही प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी, भारतीय प्लेट की समुद्री सीमा कम हो गई।
- टेथिस सागर के संपीड़न के साथ-साथ उत्तर की ओर बहाव के कारण हिमालय का उत्थान हुआ।
- पर्वत लगातार जुड़ते रहे, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, जिन्हें वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है।

हिमालय के डिवीज़न:-

- **ट्रांस हिमालय**
    - ट्रांस हिमालय 1,600 किलोमीटर लंबी (990 मील) पर्वत श्रृंखला है, जो मुख्य हिमालय श्रृंखला के समानांतर पश्चिम-पूर्व दिशा में फैली हुई है।
- **ग्रेट हिमालय (Great Himalayas)**
    - इसकी औसत लम्बाई 5000 किमी है।
    - इसमें ग्लेशियरों के व्यापक हिमक्षेत्रों के साथ-साथ ऊँची चोटियाँ भी हैं।
- **मध्य हिमालय**
    - इसकी औसत लम्बाई 1300 से 5000 किमी है।
- **शिवालिक**
    - यह कोई सतत श्रेणी नहीं है, इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है।

हिमालय को निम्नलिखित उप-भागों में विभाजित किया जा सकता है:-

- कश्मीर या उत्तर-पश्चिमी हिमालय
    - इसमें काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कर और पीर पंजाल जैसी पर्वतमालाओं की एक श्रृंखला शामिल है।
- हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय
    - यह भाग लगभग पश्चिम में रावी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है।
    - रावी: सिंधु नदी की एक सहायक नदी।
    - काली: घाघरा नदी की एक सहायक नदी।
- दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय
    - वे पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय से घिरे हुए हैं।
- अरुणाचल हिमालय
    - ये भूटान हिमालय के पूर्व से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक फैले हुए हैं।

भारत के लिए हिमालय का महत्व:-

- **नदी स्रोत:** बड़ी नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि यहीं से निकलती हैं।
- **उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान:** नदियाँ हिमालय से गिरते समय भारी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी ले आती हैं।
    - यह उपजाऊ मिट्टी के रूप में बड़ा मैदान में जमा होता है, जिससे यह मैदान दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि

में से एक बन जाता है।

- **भारत की ऊर्जा सुरक्षा:** देश की लगभग 33% तापीय बिजली और 52% जलविद्युत हिमालय से निकलने वाली नदी के पानी पर निर्भर है।
- **मानसून:** हिमालय मानसून में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - यह अपनी अधिक ऊंचाई, लंबाई और दिशा के कारण, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाले ग्रीष्मकालीन मानसून को प्रभावी ढंग से रोकता हैं और बारिश या बर्फ के रूप में वर्षा कराता हैं।
- **वन संसाधन:** हिमालय पर्वतमाला वन संसाधनों में बहुत समृद्ध है।
  - हिमालय के वन वन-आधारित उद्योगों के लिए ईंधन की लकड़ी और बड़ी संख्या में कच्चे माल प्रदान करते हैं।
- **पर्यटन:** अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्वस्थ वातावरण के कारण, हिमालय पर्वतमाला ने बड़ी संख्या में पर्यटन स्थल विकसित किए हैं।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

फौकॉल्ट पेंडुलम

संदर्भ: हाल ही में उद्घाटन किए गए नए संसद भवन में फौकॉल्ट पेंडुलम (Foucault Pendulum) स्थापित किया गया है।

फौकॉल्ट के पेंडुलम के बारे में:-

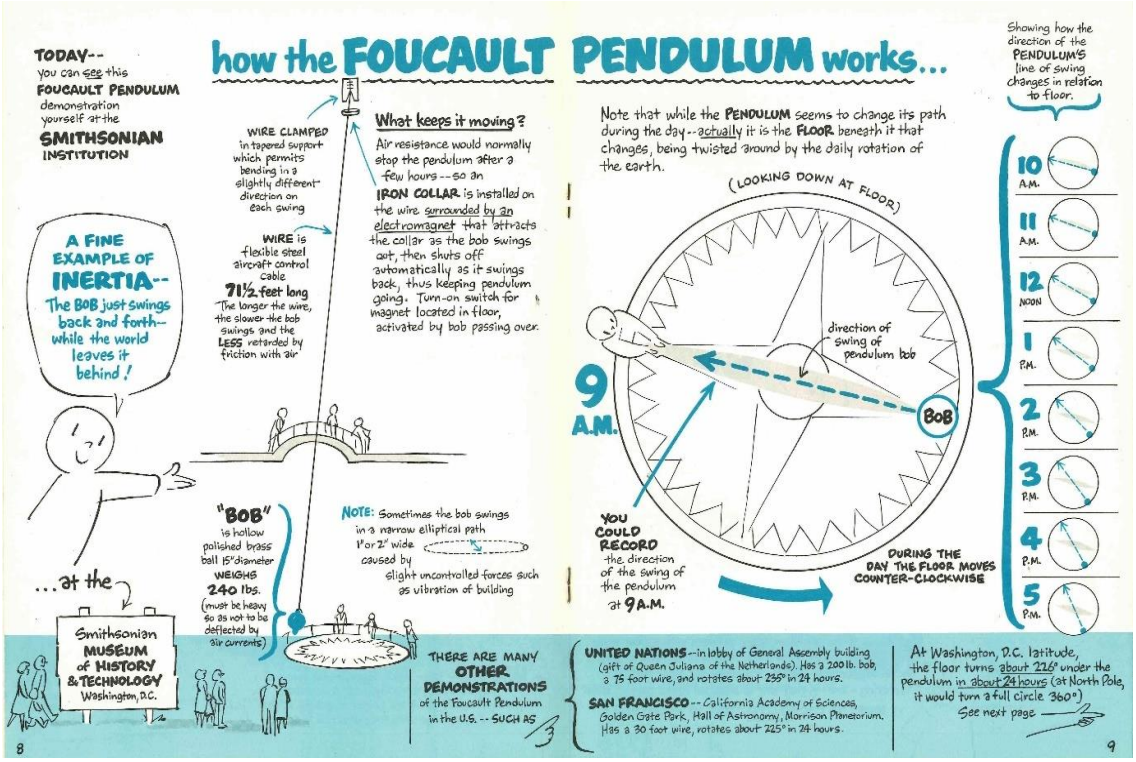

IMAGE SOURCE: si.edu

- फौकॉल्ट पेंडुलम एक उपकरण है इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है।
- फौकॉल्ट पेंडुलम का नाम 19वीं शताब्दी के फ्राँसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फौकॉल्ट के नाम पर रखा गया है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** 1851 में, फौकॉल्ट पेंडुलम प्रयोग ने निर्णायक रूप से पृथ्वी के घूर्णन का प्रदर्शन किया, जिससे ग्रह की गति के बारे में बहस सुलझ गई। (यूपीएससी मेन्स: जियोमैग्नेटिज्म क्या है?)
- **कार्य करना:** पेंडुलम में स्टील के तार से लटकी हुई एक भारी लोहे की गेंद होती है और यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूमने की नकल करते हुए एक समतल पर घूमती है।

	• फौकॉल्ट पेंडुलम हमेशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमता है। • दक्षिणी गोलार्ध में घूर्णन वामावर्त होता है। • पेंडुलम के आभासी घूर्णन की दर और दिशा उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। (यूपीएससी सीएसई: जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी की धुरी में बदलाव होना) • जैसे-जैसे पेंडुलम का स्थान भूमध्य रेखा के पास आता है, गति धीमी हो जाती है। • भूमध्य रेखा पर यह बिल्कुल नहीं घूमेगा। **अवश्य पढ़ें:** NavIC **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस

चिट्रिडिओमाइकोसिस	**संदर्भ:** हाल ही में, वैज्ञानिकों ने चिट्रिडिओमाइकोसिस के लिए एक नैदानिक परीक्षण विकसित किया है।
	चिट्रिडिओमाइकोसिस के बारे में:-
	• चिट्रिडिओमाइकोसिस मेंढक आबादी में एक कवक रोग है। (यूपीएससी सीएसई: सफेद कवक)
	• इसके कारण 500 से अधिक मेंढक प्रजातियों में गंभीर गिरावट आई है और 90 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, जिससे यह ज्ञात सबसे घातक पशु रोग बन गया है। (यूपीएससी सीएसई: म्यूकोर्मिकोसिस)
	• यह संक्रमित कैसे करता है?
	  ○ यह मेंढकों की त्वचा को संक्रमित करता है।
	  ○ इससे पानी और नमक के स्तर को संतुलित करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है।
	• चिट्रिड की उत्पत्ति एशिया में हुई है और यह उभयचरों के व्यापार और वैश्विक यात्रा के माध्यम से अन्य महाद्वीपों में फैल गया है।
	• अंतत: संक्रमण का स्तर बहुत अधिक होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है।
	• **कुछ उभयचरों के लिये प्रतिरक्षा:**
	  ○ कुछ उभयचर प्रजातियाँ फंगस ले जाने पर अस्वस्थ/रोगग्रस्त नहीं होती हैं, जो हैरान करने वाला है।
	  ○ अब तक प्रतिरोध और प्रतिरक्षा कार्य के बीच कोई स्पष्ट रुझान नहीं पाया गया है। यह भी सबूत है कि चिट्रिड एक मेज़बान की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को दबा सकता है।
	अवश्य पढ़ें: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले कवक की पहली सूची जारी की
	स्रोत: द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

कवच (KAVACH)	**संदर्भ:** ओडिशा में हाल ही में हुई ट्रेन त्रासदी ने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच की आवश्यकता को धरातल पर ला दिया है। इस रूट पर कवच उपलब्ध नहीं था। **कवच के बारे में:-** **IMAGE SOURCE:** newssimplified.in • कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे भारतीय रेलवे को शून्य दुर्घटनाएं प्राप्त करने में

	मदद करने के लिए बनाया गया है। • **उद्देश्य:** भारतीय रेलवे में ट्रेन परिचालन में सुरक्षा प्राप्त करना। • **विकास:-** ○ इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ○ भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा विकसित किया गया है। ▪ अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ): यह रेल मंत्रालय के तहत एक अनुसंधान और विकास संगठन है। • **कवच की कार्यप्रणाली:-** ○ यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव तथा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ-साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। **(यूपीएससी सीएसई: आरएफआईडी)** ○ वे ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिये अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके एक-दूसरे से जुड़ते हैं तथा ड्राइवरों को सतर्क भी करते हैं, ये सभी प्रोग्राम के आधार पर होते हैं। • यह एक सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 (SIL-4) प्रमाणित तकनीक है। ○ सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल (SIL): SIL दो स्वैच्छिक मानकों के साथ खतरनाक कार्यों के लिये सुरक्षा प्रदर्शन आवश्यकताओं को मापने हेतु संयंत्र मालिकों/संचालकों द्वारा उपयोग किया जाता है। ○ चार SIL स्तर (1-4) हैं। एक उच्च SIL स्तर का अर्थ है कि प्रक्रियात्मक खतरा अधिक है और उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है। • कवच दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली है। • कवच का प्रारंभिक विकास 2012 में ट्रेन कोलिज़न बचाव प्रणाली (Train Collision Avoidance System-TCAS) नाम से शुरू हुआ और 2022 में इसका विकास पूरा हुआ। • पहला सफल परीक्षण: 2022 में दक्षिण मध्य रेलवे के गुल्लागुड़ा-चिटगिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच। • 2022-23 के बजट में 2000 किलोमीटर में कवच को रोलआउट करने का प्रस्ताव था। **मुख्य विशेषताएं:-** • यदि ड्राइवर ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो ब्रेकिंग सिस्टम स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है। • कवच सिस्टम दो लोकोमोटिव के बीच टकराव को रोकता है। • आपातकालीन स्थितियों के दौरान SoS संदेशों को रिले करता है। • लेवल क्रॉसिंग गेट के पास पहुंचते समय ऑटो सीटी बजाना • नेटवर्क मॉनीटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही की केंद्रीकृत लाइव निगरानी प्रदान करता है। **जरूर पढ़ें:** वंदे भारत 2.0 **स्रोत:** बिज़नेस
एबॉसीन	**संदर्भ:** वैज्ञानिकों ने हाल ही में मशीन लर्निंग की मदद से एबॉसीन नामक एक संभावित नए एंटीबायोटिक की खोज की है। **इसके बारे में:-** • यह एंटीबायोटिक CCR2 नामक प्रोटीन के सामान्य कार्य को बाधित करता है। • इसे मूल रूप से मधुमेह के इलाज के लिए विकसित किया गया था। • यह एसिनेटोबैक्टर बॉमनी (Acinetobacter Baumannii) के खिलाफ प्रभावी है। • **कार्रवाई की प्रणाली:** यह व्यवधान बैक्टीरिया के अंदर कुछ अणुओं की गति को बाधित करता है, जिससे उन्हें बाहरी झिल्ली तक पहुँचने से रोका जा सकता है। • अबौसीन भी एक "प्रजाति-चयनात्मक" एंटीबायोटिक है।

	एसिनेटोबैक्टर बॉमनी • यह एक ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया है। ○ ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया: इसमें एक सुरक्षात्मक बाहरी झिल्ली होती है जो इसे एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध करने की अनुमति देती है। • इसे भारत में अस्पताल से प्राप्त संक्रमण से जोड़ा गया है। • वर्तमान में उपलब्ध सभी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित करने की इसकी असाधारण क्षमता के कारण इसे "रेड अलर्ट" रोगज़नक़ के रूप में स्वीकार किया गया था। **(यूपीएससी सीएसई: रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)** **अवश्य पढ़ें:** विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2022 **स्रोत:** द हिंदू
हिग्स बोसॉन	**संदर्भ:** हाल ही में, यूरोप में CERN के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) पार्टिकल-स्मैशर ने बताया कि उन्होंने एक हिग्स बोसोन का Z बोसॉन कण और एक फोटॉन में क्षय होने का पता लगाया है। **इसके बारे में:-** 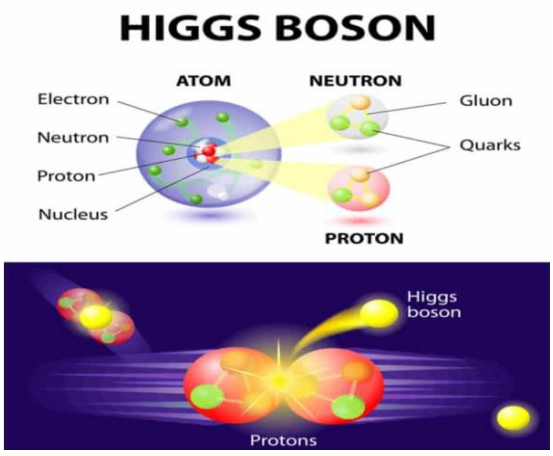 IMAGE SOURCES: scalarlight.com • 'हिंग्स बोसान एक प्रकार का बोसॉन है, जो एक बल-वाहक उपपरमाण्विक कण है। • यह उस बल को वहन करता है जो एक कण ऊर्जा क्षेत्र से गुजरते समय अनुभव करता है, जिसे हिग्स फ़ील्ड कहा जाता है। • **हिग्स फ़ील्ड:** एक फ़ील्ड जो इलेक्ट्रॉनों और क्वार्क जैसे अन्य मूलभूत कणों को द्रव्यमान देता है। • ऐसा माना जाता है कि यह पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। • हिग्स बोसान को अक्सर 'गॉड पार्टिकल" कहा जाता है ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यह "बिग बैंग" का कारण था जिसने कई साल पहले हमारे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। • हिग्स बोसान एक अत्यंत अल्पकालिक कण है। • **विशेषता गुण:** यह तेजी से अन्य कणों में विघटित हो जाता है, जिससे इसका प्रत्यक्ष पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। • LHC के वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसान का उत्पादन करने के लिए उच्च-ऊर्जा कण टकराव का उपयोग किया और इसके अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए इसके क्षय उत्पादों का अवलोकन किया। • हिग्स बोसान का द्रव्यमान 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह एक प्रोटॉन से 130 गुना अधिक बड़ा है। • यह ज़ीरो स्पिन के साथ चार्जलेस भी है। स्पिन: कोणीय गति के बराबर एक क्वांटम यांत्रिक है। हिग्स बोसान एकमात्र प्राथमिक कण है जिसमें कोई स्पिन नहीं है। • इसका जीवनकाल छोटा होता है। ○ यह एक सेकंड के अरबवें (trillionth) हिस्से के खरबवें (billionth) हिस्से से भी कम समय के लिए या,

अधिक सटीक रूप से, 1.6 x 10-22 सेकंड तक टिका रहता है।

समयरेखा:-

- पीटर हिग्स, फ्रांकोइस एंगलर्ट और चार अन्य सिद्धांतकारों ने यह समझाने के लिए कि कुछ कणों का द्रव्यमान क्यों है, 1964 में हिग्स बोसान के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था।
- वैज्ञानिकों ने 2012 में स्विट्जरलैंड में CERN में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में प्रयोगों के माध्यम से इसके अस्तित्व की पुष्टि की।
- इस खोज के कारण 2013 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हिग्स और एंगलर्ट को दिया गया।

महत्व:-

- हिग्स बोसान हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।
- वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हिग्स बोसान का उपयोग डार्क मैटर के बारे में अधिक जानने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाएगा। (यूपीएससी सीएसई: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस))
- इसकी क्षय प्रक्रिया भौतिकी के मानक मॉडल की भविष्यवाणियों का परीक्षण करने में मदद कर सकती है।
- प्राथमिक कणों का मानक मॉडल: यह भौतिकी में एक सैद्धांतिक ढांचा है जो पदार्थ के कणों और उनकी अंतःक्रियाओं की व्याख्या करता है।

लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC)

- LHC एक विशाल प्रयोग है जो अत्यधिक उच्च ऊर्जा पर भौतिकी का अध्ययन करने के लिये कणों के दो बीमों को टकराता है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है।
- यह विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग है।
- संचालित: CERN (परमाणु अनुसंधान के लिये यूरोपीय संगठन)
- CERN: दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु और कण भौतिकी प्रयोगशाला है।
    - इसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के संचालक के रूप में जाना जाता है।
    - यह फ्रांसीसी-स्विस सीमा पर जिनेवा में स्थित है।
    - इसके 22 सदस्य देश हैं।

भारत और CERN:-

- वर्ष 2016 में भारत यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (CERN) का सहयोगी सदस्य बन गया।
- CERN के साथ भारत का जुड़ाव लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के साथ दशकों पुराना है।
- भारत को 2004 में CERN में 'पर्यवेक्षक' के रूप में शामिल किया गया था।
- एसोसिएट सदस्यता से भारत को सालाना 78 करोड़ रुपये का खर्च आता है, हालांकि परिषद के फैसलों पर उसे अभी भी वोटिंग का अधिकार नहीं है। भारतीय वैज्ञानिकों ने लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट (ALICE) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अवश्य पढ़ें: अंतरिक्ष में

स्रोत: द हिंदू

इतिहास, कला एवं संस्कृति

तेलंगाना की ऊनी गोंगडी शॉल	**संदर्भ:** नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के पूर्व छात्रों के एक समूह ने तेलंगाना के ऊनी गोंगडी शॉल को किसानों के लिए हर मौसम के लिए उपयुक्त जूतों में बदल दिया है। **इसके बारे में:-** • गोंगाडी स्वदेशी कुरुमा समुदायों द्वारा बुना गया पारंपरिक ऊनी कंबल है। • इसके निर्माण में स्थानीय रूप से नल्ला गोर्रे के रूप में जानी जाने वाली स्वदेशी दक्कनी भेड़ के ऊन का उपयोग किया जाता है। • **नल्ला गोर्रे:** यह दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की एक नस्ल है। (UPSC MAINS: ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भू-आकृति का निर्माण) • यह शॉल अपनी स्थायित्व और बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। अपनी अनूठी हाथ से की गई बुनाई के कारण यह एक दशक से भी अधिक समय तक चलती है। (यूपीएससी सीएसई: भारत में कपड़ा उद्योग) • गोंगाडी की अनोखी प्रकृति : यह कम नहीं होती है बल्कि समय के साथ और गहरी होती जाती है। • इसे प्राकृतिक या सिंथेटिक रंगों का उपयोग किये बिना जैविक रूप से निर्मित किया जाता है। • भिगोए और पके हुए इमली के बीज के पेस्ट का उपयोग करके इसमें तारों का आकार निर्धारित किया जाता है। **अवश्य पढ़ें:** हैदराबाद की लाख की चूड़ियों को जीआई टैग मिलना **स्रोत:** द हिंदू
आगरा का किला	**सन्दर्भ:** हाल ही में आगरा का किला किसने बनवाया इस पर फिर से बहस शुरू हो गई है। **इसके बारे में:-** • आगरा का किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। • इस किले पर राजपूत, मुगल, जाट और मराठों सहित कई राजवंशों का कब्जा रहा है। • इस किले का निर्माण 1565 में अकबर के शासनकाल में आठ वर्षों तक चला। • हालाँकि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इस बात की जानकारी नहीं है कि आगरा का किला सबसे पहले किसने बनवाया था और अकबर के शासनकाल के दौरान इसमें क्या बदलाव हुए थे। • यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। • इसमें जहांगीर महल और खास महल (शाहजहां द्वारा निर्मित), दीवान-ए-खास और दो बेहद खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। • 1638 तक जब राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई तब तक यह मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। • यह 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया। (UPSC MAINS: यूनेस्को का आदेश और महत्व) **आगरा किले के अंदर महत्वपूर्ण संरचनाएँ:-** • **जहाँगीर का हौज़:** यह एक अखंड टैंक है, और इसे जहाँगीर ने बनवाया था। • **शाहजहानी महल:** शाहजहानी महल संभवतः लाल बलुआ पत्थर के महल को सफेद संगमरमर के महल में बदलने के सम्राट शाहजहाँ के शुरुआती प्रयासों में से एक है। • **बाबर की बावली (बावड़ी):** बाबर ने एक पत्थर का कुआं बनवाया जिसमें आगरा के प्राचीन किले में पानी की जरूरतों का ख्याल रखा गया था • **नगीना मस्जिद:** नगीना मस्जिद एक मस्जिद है, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था।

	• **दीवान-ए-आम (पब्लिक ऑडियंस का हॉल)** – यह हॉल शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। • **ग़ज़नीन द्वार** – ग़ज़नी द्वार वास्तव में ग़ज़नी साम्राज्य के शासकों में से एक गजनी के महमूद की कब्र से संबंधित है। • **बंगाली महल** – यह महल अकबर द्वारा बनवाया गया था और बाद में इसे शाहजहाँ द्वारा संशोधित किया गया था। • **अकबर का महल** – अकबर के प्रसिद्ध महल के खंडहर अभी भी किले में बने हुए हैं। **अवश्य पढ़ें:** धोलावीरा: भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल **स्रोत:** इंडिया टुडे
पीटरमैरिट्ज़बर्ग रेलवे स्टेशन की घटना	**संदर्भ:** हाल ही में, INS त्रिशूल पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उस घटना की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पर पहुंचा, जब महात्मा गांधी को एक ट्रेन से उतार दिया गया था। **परिचय:** • 7 जून, 1893 की रात को, मोहनदास करमचंद गांधी, जो उस समय दक्षिण अफ्रीका के एक युवा वकील थे, को टिकट होने के बावजूद पीटरमैरिट्ज़बर्ग स्टेशन पर ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया था। • ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आदेश के अनुसार अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यह सीट 'केवल गोरों' के लिए है। • इस घटना ने उन्हें शांतिपूर्ण प्रतिरोध के अपने सत्याग्रह सिद्धांतों को विकसित करने और अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण नियमों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका और भारत में लोगों को संगठित करने के लिए प्रेरित किया। • सत्याग्रह: यह शब्द 'सत्य' (सत्य) और 'आग्रह' (आग्रह या सत्य-बल) से बना है। • इसके अभ्यासकर्ताओं को सत्याग्रही कहा जाता है। **आईएनएस त्रिशूल के बारे में:-** • यह भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट 2003 में भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में शामिल हुआ। • यह भारत-रूस के संयुक्त उत्पादन के तहत रूस में निर्मित किया गया। • ये मिसाइल फ्रिगेट रूस के संशोधित क्रिवाक III श्रेणी के फ्रिगेट हैं। • इसकी विस्थापन क्षमता 4,000 टन और गति 30 समुद्री मील है और यह विभिन्न प्रकार के नौसैनिक मिशनों को पूरा करने में सक्षम है, मुख्य रूप से, दुश्मन की पनडुब्बियों और बड़े सतह जहाजों को खोजना और नष्ट करना। • स्टील्थ प्रौद्योगिकियों के उपयोग और एक विशेष पतवार डिजाइन के कारण, परिणामी फ्रिगेट में कम रडार क्रॉस सेक्शन (reduced radar cross section -RCS) के साथ-साथ विद्युत चुम्बकीय, ध्वनिक (acoustic) और इंफ्रारेड सिग्नेचर शामिल हैं। **अवश्य पढ़ें:** भारत और महात्मा गांधी **स्रोत**: हिंदुस्तान टाइम्स
गिलगित पांडुलिपियाँ	**संदर्भ:** हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें गिलगित पांडुलिपियों का प्रदर्शन किया गया। **गिलगित पांडुलिपियों के बारे में:-**

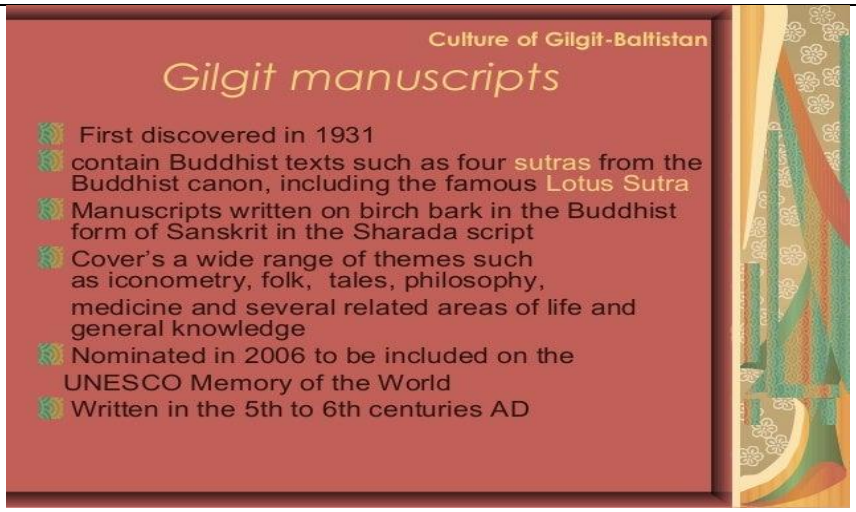

IMAGE SOURCE: slideshare.net

- गिलगित पांडुलिपियाँ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाऊपुर गाँव (गिलगित क्षेत्र) में खोजी गईं।
- पुरातत्ववेत्ता सर ऑरेल स्टीन ने इसकी खोज वर्ष 1931 में की थी।
- यह 5वीं-6वीं शताब्दी ई.पू. के बीच लिखा गया था।
- यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना जीवित पांडुलिपि संग्रह है।
- यह कश्मीर क्षेत्र में पाए जाने वाले बर्च पेड़ों की छाल (bark of birch trees) की भीतरी परत के टुकड़ों पर लिखे बर्च छाल फोलियो दस्तावेज़ों पर लिखा गया था।
- इसमें विहित और गैर-विहित दोनों जैन और बौद्ध कार्य शामिल हैं जो बहुत से धार्मिक-दार्शनिक साहित्य के विकास पर प्रकाश डालते हैं। (यूपीएससी सीएसई: सित्तनवासल जैन विरासत स्थल)

भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार

- भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की वर्तमान इमारत का निर्माण 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद 1926 में किया गया था।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** इसकी स्थापना 1891 में कोलकाता (कलकत्ता) में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी।
- **मंत्रालय:** संस्कृति मंत्रालय
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- यह सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम, 1993 और सार्वजनिक रिकॉर्ड नियम, 1997 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।
- इसके भंडार अभिलेखों का एक विशाल संग्रह हैं, जिसमें फ़ाइलें, खंड, मानचित्र, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित बिल, राजपत्रों और गजेटियर्स का एक महत्वपूर्ण संग्रह, जनगणना रिकॉर्ड, विधानसभा और संसद की बहस, प्रतिबंधित साहित्य, यात्रा विवरण आदि शामिल हैं।
- प्राच्य अभिलेखों का एक बड़ा हिस्सा संस्कृत, फ़ारसी, अरबी आदि में है।

अवश्य पढ़ें: पाल्म लीफ पांडुलिपि संग्रहालय (Palm-Leaf Manuscript Museum)
स्रोत: पीआईबी

मालचा महल

संदर्भ: दिल्ली के उपराज्यपाल ने हाल ही में मालचा महल के आसपास के वन क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए निर्देश जारी किए।
मालचा महल के बारे में:-

- इसका निर्माण 1325 में तत्कालीन सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने करवाया था।
- इसका उपयोग लंबे समय तक शिकारगाह के रूप में किया जाता था।
- यह बाद में अवध के नवाब के वंशजों का निवास स्थान बन गया।
- **स्थान:** दिल्ली
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** इसे अवध की बेगम विलायत महल के नाम पर 'विलायत महल' के नाम से जाना जाने लगा,

	जिन्होंने दावा किया था कि वह अवध के शाही परिवार की सदस्य थीं। o उन्हें यह महल 1985 में सरकार द्वारा दिया गया था। o जब उनकी मृत्यु हुई, तो यह उनकी बेटी सकीना महल और बेटे प्रिंस अली रज़ा (साइरस) के स्वामित्व में आ गया। • यह स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित नहीं है और इसलिए, इसके संरक्षण के लिए इतने वर्षों में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। (यूपीएससी सीएसई: एएसआई) **फ़िरोज़ शाह तुगलक** • फ़िरोज़ शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा शासक था। • तुगलक वंश: 1320 से 1412 ई. तक दिल्ली पर शासन किया। • वह अपने चचेरे भाई मुहम्मद-बिन-तुगलक के निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। • समयावधि : 1351 ई. से 1388 ई. तक। **अवश्य पढ़ें:** ASI हम्पी में प्रसिद्ध पत्थर रथ के चारों ओर बैरिकेडिंग की योजना बना रहा है। **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
केदारनाथ मंदिर	**संदर्भ:** हाल ही में, उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ मंदिर में सोने के लेनदेन में धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया। **पृष्ठभूमि:** **केदारनाथ मंदिर के बारे में:-** • यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। • **स्थान:** यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। • मंदाकिनी नदी: यह अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है। o यह चोराबारी ग्लेशियर (Chorabari Glacier) से निकलती है। o यह रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग क्षेत्रों के बीच से होकर बहती है। • **महत्व:** केदारनाथ छोटा चार धाम तीर्थयात्रा सर्किट के चार स्थलों में से एक है। o छोटा चार धाम तीर्थयात्रा: यह उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में पहाड़ों से चार पवित्र मंदिरों तक की यात्रा को संदर्भित करता है। o चार मंदिर हैं यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम। • यह भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। • ज्योतिर्लिंग: मंदिर जहां भगवान शिव की पूजा ज्योतिर्लिंगम के रूप में की जाती है। • निर्माण: ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। (यूपीएससी सीएसई: भारत में मंदिर वास्तुकला) • बाद में इसका पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। • इसमें उत्कृष्ट वास्तुकला है और यह बेहद बड़े लेकिन समान आकार के भूरे पत्थर के स्लैब से बना है। • पत्थर की पट्टियों को लोहे के क्लैंप का उपयोग करके एक दूसरे से जोड़ा जाता है। • मंदिर के निर्माण में किसी मशाले (mortar) का इस्तेमाल नहीं किया गया है। • केदारनाथ मंदिर के अंदर एक शंक्वाकार चट्टान की संरचना है जिसे शिव के सदाशिव रूप के रूप में पूजा जाता है। • मंदिर के अंदर पूजा के लिए एक "गरबा गृह" और तीर्थयात्रियों के लिए एक मंडप रखा गया है। **अवश्य पढ़ें:** श्रीशैलम मंदिर **स्रोत:** टाइम्स ऑफ इंडिया
रानी दुर्गावती	**संदर्भ:** रानी दुर्गावती गौरव यात्रा' हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुई। **पृष्ठभूमि:-** • मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने छह दिवसीय रानी दुर्गावती गौरव यात्रा शुरू

	की। **रानी दुर्गावती के बारे में:-** ● रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में मध्य प्रदेश की सीमा के पास वर्तमान उत्तर प्रदेश में चंदेल राजवंश में हुआ था। ● उनके पिता राठ के राजा सालबाहन थे जो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों के लिए जाने जाते थे। ● उन्होंने गढ़ा-कटंगा राज्य के दलपत शाह से शादी की। o हालाँकि, कुछ वर्षों के बाद वह विधवा हो गईं और राज्य पर शासन करने का कार्यभार संभाला। **मुगलों से युद्ध:-** ● 16वीं शताब्दी के मध्य में, अकबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य के विस्तार का नेतृत्व किया। ● मुगल जनरल आसफ खान ने गढ़ा-कटंगा पर आक्रमण कर दिया। ● इस लंबी लड़ाई के दौरान, रानी दुर्गावती को तीरों से चोट लगी और ऐसा माना जाता है कि आत्मसमर्पण करने के बजाय, उन्होंने खुद को अपने खंजर से मार लिया था। **रानी दुर्गावती का नेतृत्व** ● रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक राज्य के मामलों का प्रबंधन किया, व्यापार संबंधों को बनाए रखा और सार्वजनिक कार्य किए। ● अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फज़ल, जिन्होंने अकबरनामा में इन वर्षों का विवरण दिया है, ने दुर्गावती को "सौंदर्य, अनुग्रह और मर्दाना साहस और बहादुरी" के संयोजन के रूप में वर्णित किया है। **रानी दुर्गावती की विरासत** ● राजनीतिक प्रतीकवाद: रानी दुर्गावती को एक देशभक्त शासक और संस्कृति की रक्षक के रूप में गौरव और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ● मदन महल रानी दुर्गावती तथा उनके पुत्र वीरनारायण से संबंधित था। ● उनके सम्मान में, 1983 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। ● 24 जून 1988 को भारत सरकार ने उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। ● दुर्गावती एक्सप्रेस (11449/11450) जबलपुर जंक्शन और जम्मूतवी के बीच चलती है और इसका नाम रानी के नाम पर रखा गया है। ● अपनी तरह का तीसरा इनशोर पेट्रोल वेसल (आईपीवी), आईसीजीएस रानी दुर्गावती, 14 जुलाई, 2018 को भारतीय तट रक्षक द्वारा कमीशन किया गया था। **स्रोत: द हिंदू**
खर्ची पूजा	**संदर्भ:** हाल ही में चर्चित खर्ची पूजा त्रिपुरा राज्य में मनाया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण त्योहार है। **इसके बारे में:-** ● नामकरण: 'खर्ची' शब्द दो त्रिपुरी शब्दों से बना है- 'खर' या खरता जिसका अर्थ है पाप और 'ची' या सी जिसका अर्थ है सफाई। ● क्षेत्र: यह त्रिपुरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ● समय अवधि: यह जुलाई-अगस्त के महीनों के दौरान अमावस्या के आठवें दिन किया जाता है। **खर्ची पूजा का महत्व:-** ● ऐसा माना जाता है कि देवी माँ या त्रिपुरा सुंदरी, भूमि की अधिष्ठात्री देवी है, जो त्रिपुरा के लोगों की रक्षा करती है, जून माह में अंबुबाची के समय मासिक धर्म से गुज़रती हैं। ● अंबुबाची: जून में मनाया जाता है। ● प्रचलित मान्यता है कि देवी के मासिक धर्म के दौरान पृथ्वी अशुद्ध हो जाती है। o इसलिये मासिक धर्म समाप्त होने के बाद पृथ्वी को स्वच्छ करने के लिये अनुष्ठान द्वारा लोगों के पापों को

धोने के लिये खर्ची पूजा की जाती है।

खर्ची पूजा के दौरान अनुष्ठान:-

- त्योहार के दौरान, त्रिपुरा के लोग अपने 14 देवताओं के साथ-साथ पृथ्वी की भी पूजा करते हैं। **(यूपीएससी सीएसई: बथुकम्मा उत्सव)**
- चौदह देवताओं की पूजा चंताई (शाही पुजारी) द्वारा की जाती है।
- यह सात दिनों तक चलता है और यह पुराने अगरतला में चौदह देवताओं के मंदिर में होता है जिसे 'चतुर्दश देवता (Chaturdasha Devata)' मंदिर परिसर के रूप में जाना जाता है।
- खर्ची पूजा देवताओं का शरीर पूर्ण नहीं होता है।
- उनके केवल सिर ही हैं जिनकी पूजा की जाती है।
- पूजा के दिन 14 देवताओं को "चंताई" (शाही पुजारी) के सदस्यों द्वारा "सैदरा" नदी पर ले जाया जाता है। देवताओं को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है और वापस मंदिर में लाया जाता है।
- यह त्यौहार त्रिपुरा के आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों लोगों द्वारा मनाया जाता है।

अवश्य पढ़ें: गोवा का साओ जोआओ उत्सव (Goa's Sao Joao festival)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

विविध

रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस)	**संदर्भ:** रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) हालिया ओडिशा रेल दुर्घटना की जांच कर रहा है। **रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) के बारे में:-** • रेलवे सुरक्षा आयोग रेल यात्रा और ट्रेनों की सुरक्षा से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। • **मंत्रालय:** नागरिक उड्डयन मंत्रालय • **मुख्यालय:** लखनऊ, उत्तर प्रदेश • परिचालन पर रेलवे अधिनियम (1989) में निर्धारित कुछ वैधानिक कार्यों का आरोप लगाया गया है। • इसके कार्य निरीक्षणात्मक, अन्वेषणात्मक और सलाहकार प्रकृति के होते हैं। **(यूपीएससी सीएसई: मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन (एमटीआरसी))** • गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं की जांच करना सीआरएस की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। **(यूपीएससी मेन्स: भारतीय रेलवे दुर्घटनाएँ)** • यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) के प्रशासनिक नियंत्रण में है। • इसके पीछे का कारण या सिद्धांत, सीधे शब्दों में कहें तो सीआरएस को देश के रेलवे प्रतिष्ठान के प्रभाव से अलग रखना और हितों के टकराव को रोकना है। **अवश्य पढ़ें:** श्रमिक कल्याण पोर्टल **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
अग्नि प्राइम	**संदर्भ:** भारत ने हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। **अग्नि प्राइम के बारे में:-** **IMAGE SOURCE:** autojournalism.com • अग्नि प्राइम 'अग्नि-1' मिसाइल का उन्नत संस्करण है। (यूपीएससी सीएसई: नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि पी') • यह एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। • रेंज: 1000 किमी से 1500 किमी • यह दो चरणों वाली मिसाइल है। • यह अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों का नवीनतम और छठा संस्करण है। • यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के अंतर्गत है। • अग्नि प्राइम के पास कई स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश योग्य वाहन हैं। • यह अलग-अलग स्थानों पर कई हथियार पहुंचाने में सक्षम है।

	• यह 1.5 टन तक के हथियार ले जा सकता है। • इसमें दोहरी निरर्थक नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली है। • अग्नि-पी मिसाइल भारत की विश्वसनीय निवारक क्षमताओं को और मजबूत करेगी। **एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी)** • इसकी कल्पना डॉ. ए.पी.जे. ने की थी। अब्दुल कलाम ने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया। • इस कार्यक्रम के तहत विकसित 5 मिसाइलें हैं:- 1. पृथ्वी: कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। 2. अग्नि: विभिन्न रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें। 3. त्रिशूल: कम दूरी की निम्न स्तरीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। 4. नाग: तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल। 5. आकाश: मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। **अन्य अग्नि श्रेणी की मिसाइलें** • अग्नि I: 700-800 किमी की रेंज। • अग्नि II: 2000 किमी से अधिक की रेंज। • अग्नि III: 2,500 किमी से अधिक की रेंज • अग्नि IV: रेंज 3,500 किमी से अधिक है और रोड-मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकती है। • अग्नि-V: अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी, 5,000 किमी से अधिक की मारक क्षमता वाली एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM)। **अवश्य पढ़ें:** बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) इंटरसेप्टर **स्रोत**: NEWSONAIR
महुआ के लड्डू	**संदर्भ:** ओडिशा की आदिवासी महिलाओं द्वारा तैयार किए गए महुआ के लड्डू ने हाल के दिनों में आय (revenue) में बड़ी सफलता हासिल की है। **महुआ लड्डू के बारे में:-** • ओडिशा के कंधमाल जिले की आदिवासी महिलाएं विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करने के लिए महुआ के फूलों का उपयोग करती हैं। महुआ के फूल मुख्य रूप से स्थानीय शराब बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो पूरे भारत में लोकप्रिय हैं। • राज्य के वन धन विकास केंद्रों की लगभग 120 आदिवासी महिला सदस्य आय कमाने के लिए सूखे महुआ के फूलों का उपयोग करके लड्डू, केक, जैम, टॉफी, अचार, स्क्वैश, पकौड़े और बिस्कुट तैयार करती हैं, जिन्हें वे स्थानीय बाजार में आपूर्ति करती हैं। • अन्य उत्पादों की तुलना में महुआ के लड्डू की मांग अधिक है। • काजू, रासी, मूंगफली, गुड़ और महुआ के फूल जैसी सामग्री का उपयोग करके लड्डू तैयार किया जाता है। **वन धन विकास केंद्र:** • इन्हें प्रधानमंत्री वनधन योजना (पीएमवीडीवाई) के तहत स्थापित किया गया है। • उनका लक्ष्य आदिवासी संग्रहकर्ताओं और कारीगरों के लघु वन उत्पादों (एमएफपी)-केंद्रित आजीविका विकास को बढ़ावा देना है। • लघु वन उपज आर्थिक वस्तुएं हैं जो जंगल में प्राकृतिक रूप से उगती हैं और लकड़ी और ईंधन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए बेची जाती हैं। उदाहरणों में बांस, जंगली शहद, गोंद, लाख, मोम, रेजिन आदि शामिल हैं। • ये केंद्र स्थानीय रूप से उपलब्ध MFP की खरीद सह मूल्यवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करते है। **प्रधानमंत्री वनधन योजना (PMVDY):-**

	• इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। • यह जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की एक पहल है। • उद्देश्य: जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में सुधार करना। • यह जनजातीय स्वयं सहायता समूहों (SHG) के समूह बनाने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों में मजबूत करने के लिए बाजार से जुड़ा जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। **अवश्य पढ़ें:** महुआ का पेड़/मधुका लोंगिफोलिया **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
फ्रेंच ओपन	**संदर्भ:** हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2023 में, नोवाक जोकोविच ने 23 ग्रैंड स्लैम खिताब तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया। **फ्रेंच ओपन के बारे में:-** 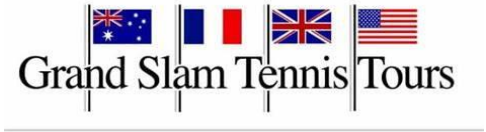 • फ्रेंच ओपन एक प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट है। • यह टेनिस के चार ग्रैंड स्लैम में से एक है। • इसे रोलैंड-गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। o टूर्नामेंट और स्थल का नाम फ्रांसीसी एविएटर रोलैंड गैरोस के नाम पर रखा गया है। o रोलैंड गैरोस: एक फ्रांसीसी विमानन अग्रणी और लड़ाकू पायलट थे। • निर्धारित समय: यह दो सप्ताह तक चलता है और प्रत्येक वर्ष मई के अंत में शुरू होता है। • स्थान: पेरिस, फ्रांस में स्टेड रोलैंड गैरोस • फ्रेंच ओपन दुनिया की प्रमुख क्ले कोर्ट चैंपियनशिप है। (यूपीएससी मेन्स: खेल और नैतिकता) • वर्ष 1924 - 1925 से पहले फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम नहीं माना जाता था। • फ्रेंच ओपन 2023 विजेता:- o पुरुष एकल: नोवाक जोकोविच (सर्बिया) o महिला: इगा स्विएटेक (पोलैंड) **ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट** • ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में निम्नलिखित शामिल हैं:- o ऑस्ट्रेलियन ओपन: जनवरी के मध्य में, o फ्रेंच ओपन या रोलैंड गैरोस: मई के अंत के आसपास, o विंबलडन: जून के अंत में, और o यूएस ओपन टेनिस: अगस्त के अंत में। • चार वार्षिक टेनिस टूर्नामेंटों को सामूहिक रूप से ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। • संचालित: यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) द्वारा संचालित होता है। • ऐतिहासिक समयरेखा:- o विंबलडन टेनिस: यह सबसे पुराना है, इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। o यूएस ओपन: 1881 में शुरू हुआ। o फ्रेंच ओपन: 1891 में शुरू हुआ। o ऑस्ट्रेलियन ओपन: 1905 में शुरू हुआ। **अवश्य पढ़ें:** भारत और फ्रांस संबंध

	स्रोत: AIR
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)	**संदर्भ:** हाल ही में, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने आपूर्ति में बदलाव के बाद इथियोपिया को खाद्य सहायता निलंबित कर दी। **विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के बारे में:-** • यह जीवन बचाने और जीवन बदलने वाला, आपात स्थिति में भोजन सहायता प्रदान करने वाला और पोषण में सुधार तथा लचीलापन बनाने के लिए समुदायों के साथ काम करने वाला अग्रणी मानवीय संगठन है। • इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। (UPSC CSE: WFP) • संस्थापक: खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) • मुख्यालय: रोम, इटली • फंडिंग: इसके पास फंड का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है; यह पूरी तरह से स्वैच्छिक चंदे द्वारा वित्त पोषित है। o इसके प्रमुख दाता सरकारें हैं। • यह WFP कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित होता है, जिसमें 36 सदस्य देश शामिल हैं और यह WFP की गतिविधियों के लिए अंतर-सरकारी समर्थन, निर्देशन और पर्यवेक्षण प्रदान करता है। • प्रमुख (Head): एक कार्यकारी निदेशक, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किया जाता है। • यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (UNSDG) का भी सदस्य है। o UNSDG: सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है। • WFP 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों में संघर्ष से विस्थापित और आपदाओं से निराश्रित लोगों तक लाइफ-सेविंग भोजन पहुंचाने के लिए काम करता है। • वर्ष 2020 में, भूख से निपटने के प्रयासों और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान के लिए इसे शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। • यह इनके साथ मिलकर काम करता है:- o खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ): संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो हंगर को खत्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। o कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी): एक संयुक्त राष्ट्र-विशेष एजेंसी जो गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है। **उद्देश्य:-** • डब्ल्यूएफपी आपातकालीन सहायता के साथ-साथ पुनर्वास और विकास सहायता पर भी ध्यान केंद्रित करता है। • इसका दो-तिहाई कार्य संघर्ष प्रभावित देशों में होता है, जहां लोगों के अल्पपोषित होने की संभावना अन्य जगहों की तुलना में तीन गुना अधिक है। • भोजन तक पहुंच की रक्षा करके भूख को समाप्त करना। • पोषण में सुधार और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना। • एसडीजी कार्यान्वयन का समर्थन करना और इसके परिणामों के लिए साझेदारी करना। **अवश्य पढ़ें:** यूक्रेन युद्ध और वैश्विक खाद्य संकट **स्रोत:** AIR
अभ्यास एकुवेरिन	**संदर्भ:** संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरिन का 12वां संस्करण हाल ही में उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। **इसके बारे में:-** • यह भारत और मालदीव के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। • मालदीव भाषा में एकुवेरिन का अर्थ 'मित्र' होता है। (यूपीएससी मेन्स: मालदीव में भारत के हित) • पृष्ठभूमि: भारत और मालदीव 2009 से एकुवेरिन अभ्यास आयोजित कर रहे हैं। • यह संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत अर्ध-शहरी वातावरण में उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियान

	चलाने तथा संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाने के लिए दोनों सेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता बढ़ाने पर केंद्रित है। • 11वां संस्करण: दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था। • 12वां संस्करण: जून 2023 में भारत के उत्तराखंड में आयोजित किया गया। **अवश्य पढ़ें:** भारत-मालदीव संबंध **स्रोत:** पीआईबी
स्वालबार्ड मिशन	**संदर्भ:** नॉर्वेजियन राजदूत ने इसरो अध्यक्ष से मुलाकात की। बैठक अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और नॉर्वे के बीच निरंतर साझेदारी बनाए रखने और बढ़ती गतिविधियों को बढ़ावा देने के महत्व पर एक आपसी समझौते के साथ संपन्न हुई। **स्वालबार्ड मिशन के बारे में:-** • यह मुलाक़ात चुनौतीपूर्ण स्वालबार्ड मिशन को याद करने का अवसर प्रदान करती है, जो 26 साल पहले न्यू-एलेसुंड, स्वालबार्ड में हुआ था। • 1997 में, सावलबार्ड मिशन के तहत, एंट्रिक्स ने रोहिणी RH-300 Mk.II साउंडिंग रॉकेट की बिक्री के लिए नॉर्वेजियन स्पेस सेंटर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। **(यूपीएससी सीएसई: NISAR)** • एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ACL): इसरो द्वारा विकसित अंतरिक्ष उत्पाद, तकनीकी परामर्श सेवा और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के प्रचार और वाणिज्यिक दोहन के लिए इसरो की एक विपणन शाखा है। **(यूपीएससी सीएसई: इन-स्पेस)।** • RH-300 Mk-II को नॉर्वेजियन स्पेस सेंटर द्वारा इस्बजॉर्न-1 के रूप में एक नया नाम दिया गया था, जिसका शाब्दिक अनुवाद 'ध्रुवीय भालू-I' है। • चुनौती: रोहिणी रॉकेट तब तक भारत में केवल उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में ही उड़ान भरते थे। जबकि स्वालबार्ड द्वीपसमूह का तापमान बेहद कम था। • आर्कटिक मौसम की स्थिति के लिए अर्हता प्राप्त करने के बाद इसरो ने RH-300 Mk-II को नॉर्वे भेज दिया। • हालाँकि, रॉकेट, दुर्भाग्य से, अनुमानित ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया, केवल 71 किमी तक ही ऊपर उठा। • फिर भी, नॉर्वेजियन वैज्ञानिक प्रक्षेपण से खुश दिखे क्योंकि उड़ान के दौरान एकत्र किए गए डेटा से कुछ नए निष्कर्ष निकले। • इस प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष अनुसंधान में दोनों देशों के बीच सहयोग के एक नए युग की शुरुआत की। **RH-300** • यह एक सिंगल-स्टेज साउंडिंग रॉकेट है। • यह फ्रेंच बेलियर रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी से व्युत्पन्न हुआ है। • प्रक्षेपण ऊंचाई: 100 किमी. • एक वैरिएंट, RH-300 Mk-II, की अधिकतम लॉन्च ऊंचाई 116 किलोमीटर है। • पेलोड: 80 किलोग्राम तक (20 किलोग्राम वैज्ञानिक पेलोड)। • एक ही उड़ान में कई पेलोड का परीक्षण किया जा सकता है। **अवश्य पढ़ें:** अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान (NGLV) **स्रोत:** द हिंदू
वैश्विक दासता सूचकांक 2023	**संदर्भ:** वैश्विक दासता सूचकांक 2023 हाल ही में प्रकाशित किया गया था। **वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के बारे में:-** • यह 160 देशों में आधुनिक गुलामी/दासता की स्थितियों का आकलन है। • द्वारा प्रकाशित: वॉक फ्री फाउंडेशन • यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) द्वारा जारी डेटा का उपयोग करता है।

	o ILO: यह सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और सार्वभौमिक और स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। o IOM: यह प्रवासन के क्षेत्र में एक अंतरसरकारी संगठन है। • यह सूचकांक 3 आयामों में रैंकिंग प्रदान करता है: समस्या का आकार (व्यापकता), सरकारी प्रतिक्रिया और भेद्यता (राजनीतिक अस्थिरता, असमानता)। **रिपोर्ट की मुख्य बातें:-** • वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार, अनुमानित 50 मिलियन लोग वर्ष 2021 में किसी भी दिन आधुनिक गुलामी/दासता के शिकार थे। o वर्ष 2016 के बाद इस संख्या में 10 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। o आधुनिक दासता: इसमें शोषण के विभिन्न रूप शामिल हैं, जिनमें जबरन श्रम, जबरन विवाह, ऋण बंधन, मानव तस्करी, गुलामी जैसी प्रथाएं और बच्चों की बिक्री और शोषण शामिल हैं। o इसका मतलब है कि विश्व में प्रत्येक 160 में से एक व्यक्ति आधुनिक दासता का शिकार है। • उच्चतम प्रसार वाले देश: उत्तर कोरिया (104.6), इरिट्रिया (90.3), और मॉरिटानिया (32.0)। o इनमें आधुनिक गुलामी अक्सर राज्य-प्रायोजित होती है। • सबसे कम प्रसार वाले देश: स्विट्जरलैंड (0.5), नॉर्वे (0.5), और जर्मनी (0.6)। • एशिया और प्रशांत क्षेत्र: आधुनिक गुलामी में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। (29.3 मिलियन) • भारत: इसका प्रचलन आठ है। (प्रति हजार व्यक्तियों पर आधुनिक गुलामी में रहने वाली जनसंख्या का अनुमानित अनुपात)। • भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका शीर्ष G20 देशों में से हैं जहां मजबूर मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है। • आधुनिक गुलामी में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या की मेजबानी करने वाले देश:- o भारत o चीन o उत्तर कोरिया **अवश्य पढ़ें:** वर्ल्ड ऑफ़ वर्क रिपोर्ट **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
अंजदीप और संशोधक (Anjadip and Sanshodhak)	**संदर्भ:** हाल ही में दो युद्धपोत अंजदीप और संशोधक लॉन्च किए गए। **अंजदीप और संशोधक के बारे में:-** **अंजदीप:** • यह भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। • निर्माण : कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई)। • अंजादीप शैलो वॉटर क्राफ्ट (एसडब्ल्यूसी) परियोजना के आठ जहाजों में से तीसरा है। o शैलो वॉटर क्राफ्ट (एसडब्ल्यूसी) परियोजना: वर्ष 2019 में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता और रक्षा मंत्रालय के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। o कर्नाटक के अंजादीप द्वीप को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए जहाज का नाम अंजादीप रखा गया है। • 'अर्नाला' श्रेणी के जहाज नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक कार्वेट के मौजूदा 'अभय' वर्ग की जगह लेंगे। • इन्हें तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियान चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है **विशेषताएँ:-** • यह जल-जेट प्रणोदन द्वारा संचालित है। • अधिकतम गति: 25 समुद्री मील (46 किमी/घंटा)।

	• इसमें 14 समुद्री मील (26 किमी/घंटा) पर 1,800 समुद्री मील (3,300 किमी) की सहनशक्ति है। • यह एक एंटी-सबमरीन कॉम्बैट सूट, संभावित रूप से डीआरडीओ द्वारा विकसित IAC MOD'C', एक हल माउंटेड सोनार और एक कम-आवृत्ति वैरिएबल डेप्थ सोनार से सुसज्जित है। • इसमें अग्नि नियंत्रण प्रणाली (एफसीएस), एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणाली, परमाणु ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और युद्ध क्षति नियंत्रण प्रणाली भी शामिल है। • जहाज 80 प्रतिशत स्वदेशीकरण वाले होंगे। **संशोधक** • यह भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वेसल लार्ज (एसवीएल) है। (यूपीएससी सीएसई: इक्षाक सर्वेक्षण पोत) • जहाज का नाम 'संशोधक' रखा गया है, जिसका अर्थ है 'शोधकर्ता'। o यह एक सर्वेक्षण पोत के रूप में जहाज की प्राथमिक भूमिका को दर्शाता है। • एसवीएल जहाज नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरणों के साथ मौजूदा संधायक क्लास सर्वेक्षण जहाजों की जगह लेंगे। • यह समुद्र संबंधी डेटा एकत्र करने में मदद करेगा। **विशेषताएँ:-** • उनके पास चार सर्वे मोटर बोट और एक अभिन्न हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता है। • जहाजों की प्राथमिक भूमिका बंदरगाहों और नौवहन चैनलों के पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करनी होगी। • जहाजों को रक्षा के साथ-साथ नागरिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्र विज्ञान और भूभौतिकीय डेटा एकत्र करने के लिए भी तैनात किया जाएगा। **अवश्य पढ़ें:** MV Ganga Vilas **स्रोत:** द हिंदू
जनजातीय खेल महोत्सव	**संदर्भ:** हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव की पहल की सराहना की। **जनजातीय खेल महोत्सव के बारे में:-** • जनजातीय खेल महोत्सव का उद्घाटन 2023 में किया गया था। • जनजातीय खेल महोत्सव ओडिशा सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। • इस कार्यक्रम ने जनजातीय समुदायों की प्रतिभा और प्रतिस्पर्धी भावना को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। • KIIT विश्वविद्यालय, ओडिशा में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। • **उद्देश्य:** खेलों का उत्सव मनाना और आदिवासी खेलों तथा एकता को बढ़ावा देना। (यूपीएससी सीएसई: सतत विकास में जनजातीय संस्कृति का महत्व) **महत्व:-** o इसने विविध पृष्ठभूमि के एथलीटों को अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। o इसने भाग लेने वाले राज्यों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा दिया। o इसने पूरे भारत के स्वदेशी एथलीटों का उत्सव मनाया। • फोकस क्षेत्र: खेल, संस्कृति और एकता। • प्रतिभागी: विभिन्न आदिवासी संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 26 राज्यों के लगभग 5,000 स्वदेशी एथलीटों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। **अवश्य पढ़ें:** जनजातीय ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करना **स्रोत:** पीआईबी
गांधी शांति पुरस्कार 2021	**संदर्भ:** हालिया रिपोर्टों के अनुसार, गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस, गोरखपुर को प्रदान किया गया। **गांधी शांति पुरस्कार 2021 के बारे में:-** • **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी।

	o 1995: तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जूलियस के न्येरेरे को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। o डॉ. जूलियस के. न्येरेरे: अफ्रीकी एकता के आंदोलनों के पीछे भी प्रमुख शक्ति थे। • **अवधि:** यह एक वार्षिक पुरस्कार है। (यूपीएससी सीएसई: नोबेल शांति पुरस्कार 2021) • **महत्व:** यह महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए आदर्शों के प्रति एक श्रद्धांजलि है। (यूपीएससी सीएसई: महात्मा गांधी) o महात्मा गांधी: एक वकील, राष्ट्रवादी और उपनिवेशवाद विरोधी कार्यकर्ता। o उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक जन आंदोलन का नेतृत्व किया। o गांधीजी द्वारा प्रारंभिक आंदोलन: चंपारण सत्याग्रह (1917), खेड़ा सत्याग्रह (1918), 1920: असहयोग आंदोलन (1920), सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930), भारत छोड़ो आंदोलन (1942)। o कार्य: हरिजन (गुजराती), इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया (अंग्रेजी) सहित समाचार पत्र। o आत्मकथा: सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। • पुरस्कार के लिए पात्रता: यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, वंश, भाषा, जाति आदि सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। • मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय • इस पुरस्कार में एक करोड़ रुपये की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। • **जूरी:** इसकी अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री करते हैं, और इसमें दो पदेन सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात् भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता। **हाल के पुरस्कार विजेता:-** • वर्ष 2020: बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। o बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान: बांग्लादेश में राष्ट्रपिता। • वर्ष 2021: गीता प्रेस। o गीता प्रेस: इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, और यह दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। **अवश्य पढ़ें:** गांधी मंडेला पुरस्कार **स्रोत:** AIR
भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI)	**संदर्भ:** नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) ने हाल ही में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। **नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) के बारे में:-** • NIXI कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) है। **(यूपीएससी सीएसई: एनआईएक्सआई)** o एनपीओ: एक संगठन जो एक विशेष सामाजिक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है, और अर्जित या दान किए गए सभी धन का उपयोग इसके उद्देश्यों को पूरा करने और परिचालन लागत को पूरा करने में किया जाता है। • स्थापना: 2003 • मुख्यालय: नई दिल्ली • मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय • NIXI की स्थापना भारत में इंटरनेट की पहुंच और इसे अपनाने के लिए की गई थी। • NIXI की स्थापना इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र को जनता द्वारा प्रबंधित और उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न बुनियादी ढांचे के पहलुओं को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। • NIXI की स्थापना इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को आपस में जोड़ने के लिए की गई थी। o पियरिंग (Peering): इंटरनेट के बजाय सीधे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच डेटा का आदान-प्रदान। **NIXI के उद्देश्य:-** • इंटरनेट को बढ़ावा देना। (यूपीएससी सीएसई: भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति) • जरूरत पड़ने पर, भारत के चुनिंदा स्थानों/भागों/क्षेत्रों में इंटरनेट एक्सचेंज/पीयरिंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए। o इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट (IXP): एक नेटवर्क पॉइंट जिस पर इंटरनेट सेवा प्रदाता और सामग्री वितरण नेटवर्क अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफ़िक का आदान-प्रदान करते हैं। • भारत के भीतर इंटरनेट ट्रैफ़िक के प्रभावी और कुशल रूटिंग, पियरिंग, पारगमन और विनिमय को सक्षम करने के

	लिए। o नेटवर्क रूटिंग: एक या अधिक नेटवर्क पर पथ चुनने की प्रक्रिया है। o पियरिंग: इंटरनेट के बजाय सीधे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच डेटा का आदान-प्रदान। o डेटा ट्रांज़िट: डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। o इंटरनेट ट्रैफ़िक: संपूर्ण इंटरनेट के भीतर, या इसके घटक नेटवर्क के कुछ नेटवर्क लिंक में डेटा का प्रवाह। • इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करना। **अवश्य पढ़ें:** इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ) **स्रोत:** पीआईबी
आईएनएस कृपाण	**संदर्भ:** हाल ही में भारत ने वियतनाम को मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में देने की घोषणा की। **घोषणा के बारे में:** • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गैंग के साथ बातचीत के बाद वियतनाम को आईएनएस कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है। • यह बैठक विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रयासों पर प्रगति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। • वियतनामी रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ मुख्यालय का भी दौरा किया और रक्षा अनुसंधान तथा संयुक्त उत्पादन में सहयोग के माध्यम से रक्षा औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। • भारत ने वियतनामी सशस्त्र बलों में क्षमता निर्माण के लिए वायु सेना अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में एक भाषा और आईटी लैब स्थापित करने की भी घोषणा की है। **आईएनएस कृपाण के बारे में:** • आईएनएस कृपाण एक स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट है। o मिसाइल कार्वेट: तटीय या तटीय अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया एक छोटा युद्धपोत। o यह आमतौर पर जहाज-रोधी मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और अन्य आक्रामक तथा रक्षात्मक हथियार प्रणालियों से सुसज्जित है। (यूपीएससी सीएसई: इक्षाक सर्वेक्षण पोत) • यह खुकरी क्लास मिसाइल कार्वेट है। o खुकरी श्रेणी की मिसाइल: भारत में असेंबल किए गए डीजल इंजन से सुसज्जित। • इसे 1991 में नौसेना में शामिल किया गया था। **विशेष लक्षण:-** • इसका विस्थापन करीब 1,400 टन है। • **लंबाई:** 91 मीटर • इसमें 11 मीटर की बीम है। • **गति:** यह 25 समुद्री मील से अधिक की गति देने में सक्षम है। • जहाज में मीडियम रेंज गन, 30 मिमी की क्लोज रेंज गन, चैफ लांचर और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें लगी हुई हैं। • **निभाई गई भूमिकाएँ:** तटीय और अपतटीय गश्त, तटीय सुरक्षा, सतही युद्ध, समुद्री डकैती विरोधी, और मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) संचालन। **अवश्य पढ़ें:** एमवी गंगा विलास **स्रोत:** द हिंदू
पद्म पुरस्कार	**संदर्भ:** हाल ही में गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन 15 सितंबर 2023 तक खुले रहेंगे। **पद्म पुरस्कारों के बारे में:-**

IMAGE SOURCES: Oneindia

- पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।
- **स्थापना:** 1954. (यूपीएससी सीएसई: पद्म पुरस्कार)
- **उद्देश्य:** गतिविधियों या विषयों के उन सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को पहचानना जहां सार्वजनिक सेवा का एक तत्व शामिल है।
- प्रस्तुतकर्ता: भारत के राष्ट्रपति
- समयावधि: हर साल मार्च/अप्रैल
- इसकी घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।
  o इसके लिए वर्ष 1978 और 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान एक संक्षिप्त व्यवधान था।
- **पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं:-**
  o पद्म विभूषण: असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए
  o पद्म भूषण: उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए
  o पद्मश्री: विशिष्ट सेवा के लिए

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- 1954: भारत सरकार ने दो नागरिक पुरस्कार-भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की।
  o पद्म विभूषण के तीन वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग।
  o 1955: इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कर दिया गया।

पात्रता:-

- जाति, व्यवसाय, पद या लैंगिक आधार पर भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र होते हैं।
- डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मियों सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं होते हैं।
- यह पुरस्कार विशिष्ट कार्यों को मान्यता देना चाहता है और गतिविधियों/विषयों के सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए दिया जाता है:-
  - **कला:** इसमें संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, सिनेमा, थिएटर आदि शामिल हैं।
  - **सामाजिक कार्य:** इसमें सामाजिक सेवा, धर्मार्थ सेवा, सामुदायिक परियोजनाओं में योगदान आदि शामिल हैं।
  - **सार्वजनिक मामले:** इसमें कानून, सार्वजनिक जीवन, राजनीति आदि शामिल हैं।
  - **विज्ञान और इंजीनियरिंग:** इसमें अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, परमाणु विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और उसके संबद्ध विषयों में अनुसंधान और विकास आदि शामिल हैं।
  - **व्यापार और उद्योग:** इसमें बैंकिंग, आर्थिक गतिविधियाँ, प्रबंधन, पर्यटन को बढ़ावा देना, व्यवसाय आदि शामिल हैं।
  - **चिकित्सा:** चिकित्सा शोध, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, एलोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा आदि में विशिष्टता/विशेषज्ञता शामिल है।
  - **साहित्य और शिक्षा:** इसमें पत्रकारिता, शिक्षण, पुस्तक रचना, साहित्य, कविता, शिक्षा को बढ़ावा

देना, साक्षरता को बढ़ावा देना, शिक्षा सुधार आदि शामिल हैं।

- **सिविल सेवा:** इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रशासन आदि में विशिष्टता/उत्कृष्टता शामिल है।
- **खेल:** इसमें लोकप्रिय खेल, एथलेटिक्स, साहसिक कार्य, पर्वतारोहण, खेलों को बढ़ावा देना, योग आदि शामिल हैं।
- **अन्य:** उपरोक्त क्षेत्र शामिल नहीं हैं और इसमें भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार, मानवाधिकारों की सुरक्षा, वन्य जीवन संरक्षण/संरक्षण आदि शामिल हो सकते हैं।

सजावट:-

- पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण पत्र) और एक पदक प्रदान किया जाता है।
- प्राप्तकर्ताओं को पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे किसी भी औपचारिक/राज्य समारोह आदि के दौरान पहन सकते हैं।

चयन प्रक्रिया:-

- नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली होती है।
- यहां तक कि स्व-नामांकन भी किया जा सकता है।
- यह पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं।
  - पद्म पुरस्कार समिति: इसका गठन हर साल प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है।
  - इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं।
  - अन्य सदस्य: गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और सदस्यों के रूप में चार से छह प्रतिष्ठित व्यक्ति।
- **अनुमोदन:** समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए प्रधान मंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं।

पद्म पुरस्कारों की विशेष विशेषताएं:-

- एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या (मरणोपरांत पुरस्कारों और एनआरआई/विदेशियों/ओसीआई को छोड़कर) 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यह पुरस्कार किसी उपाधि के बराबर नहीं है और इसका उपयोग पुरस्कार विजेता के नाम के प्रत्यय (suffix) या उपसर्ग (prefix) के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- यह पुरस्कार आम तौर पर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है।
  o हालाँकि, अत्यधिक योग्य मामलों में, सरकार मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार कर सकती है।

जरूर पढ़ें: पद्म पुरस्कार विजेता शांति देवी

स्रोत: AIR

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)

संदर्भ: केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड- सी. बी. एफ. सी. ने स्पष्ट किया कि फिल्म बहत्तर हुरें को 2019 में 'ए' प्रमाणन दिया गया था।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के बारे में:-

IMAGE SOURCE: SlideShare

- **स्थापना:** 1951
- यह सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत एक वैधानिक निकाय है। (यूपीएससी सीएसई: सिनेमैटोग्राफ

अधिनियम में संशोधन)

- **मंत्रालय:** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- **मुख्यालय:** मुंबई, महाराष्ट्र
- सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही फिल्मों को भारत में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।

सीबीएफसी के उद्देश्य:-

- सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 और सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983 के प्रावधानों के अनुसार अच्छा और स्वस्थ मनोरंजन सुनिश्चित करना।
- भारत में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करने के लिए एक प्रमाण पत्र प्रदान करना।
- सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार जनता के मनोरंजन, शिक्षा और अच्छे और स्वस्थ मनोरंजन को बढ़ावा देना।

संरचना:-

- **सीबीएफसी बोर्ड:** इसका नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और 12-45 गैर-आधिकारिक सदस्य करते हैं।
- सदस्य सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, कानून, कला या फिल्म पृष्ठभूमि के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है।

कार्य:-

- यह ऐसी सामग्री के लिए फिल्मों की जांच करता है जो कुछ विशेष दर्शकों, विशेषकर बच्चों और युवाओं के लिए हानिकारक या अनुपयुक्त हो सकती है।
- यह सुनिश्चित करता है कि फिल्में सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का सम्मान करते हुए नैतिक मानकों का पालन करती हों।

  सामग्री का मूल्यांकन करने और फिल्म को वर्गीकृत करने के बाद, सीबीएफसी एक प्रमाणपत्र देता है जो फिल्म की सार्वजनिक प्रदर्शनी की अनुमति देता है।

अपील:-

- फिल्म निर्माता सीबीएफसी के फैसलों के खिलाफ फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (एफसीएटी) में अपील कर सकते हैं।
  - o **एफसीएटी:** यह अपीलों की समीक्षा और समाधान करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय है।

फ़िल्मों को चार श्रेणियों के अंतर्गत प्रमाणित किया जाता है:-

- "U": अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी।
- "A": वयस्क दर्शकों तक सीमित।
- "U/A": बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता के मार्गदर्शन के अधीन अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी।
- "S": डॉक्टरों या वैज्ञानिकों जैसे विशेष दर्शकों तक सीमित।
  - o बोर्ड प्रमाणित करने से इंकार भी कर सकता है।

अवश्य पढ़ें: रिफार्म (Reform)

स्रोत: AIR

IAS BABA
ONLINE
Baba's ILP Students 3 RANKS in TOP 30
KRITIKA GOYAL
Rank 14
G V S PAVANDATTA
Rank 22
GUNJITA AGRAWAL
Rank 26
Most Trusted
Integrated Learning Program (ILP) - 2024
The Most Comprehensive Self-Study Program
VAN (Comprehensive Notes for entire UPSC Syllabus)
1
2
Mains Tests-59 and Discussion Videos
Daily MICRO Planning
3
4
Dedicated Portal and App
5
Prelims Tests-67
6
Effective NewsPaper Reading Sessions
7
Answer writing forum & Model Answers
8
Infographics on important topics
ADMISSION OPEN
www.iasbaba.com
support@iasbaba.com
91691 91888

MAINS

राजव्यवस्था और शासन

भारत में नशीली दवाओं का दुरुपयोग

संदर्भ: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) चंडीगढ़ जोन ने हाल ही में एक कथित ड्रग तस्कर को हिरासत में लिया है, जो कथित तौर पर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सक्रिय है।

मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में:

- नशीली दवाओं की तस्करी एक वैश्विक अवैध व्यापार है जिसमें उन पदार्थों की कृषि, निर्माण, वितरण और बिक्री शामिल है जो नशीली दवाओं के निषेध कानूनों के अधीन हैं।
- ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) वैश्विक अवैध दवा बाजारों की गतिशीलता की अधिक व्यापक समझ हासिल करने के लिए लगातार निरीक्षण और शोध कर रहा है।

भारत और नशीली दवाओं का दुरुपयोग:

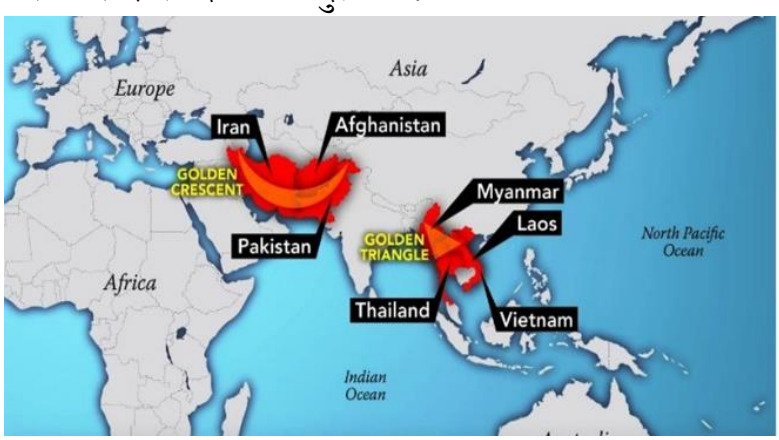

- यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जिसमें सदियों पुरानी भांग से लेकर ट्रामाडोल जैसी नई प्रिस्क्रिप्शन दवाओं और मेथमफेटामाइन जैसी बनावटी दवाओं तक शामिल है।
- नशीली दवाओं के व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग आतंकवाद, मानव तस्करी, अवैध व्यवसायों आदि के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
- भारत दुनिया के दो प्रमुख अवैध अफ़ीम उत्पादन क्षेत्रों के मध्य में स्थित है, पश्चिम में गोल्डन क्रिसेंट और पूर्व में गोल्डन ट्राएंगल जो इसे अवैध दवा व्यापार का एक व्यवहार्य केंद्र बनाता है।
  - **गोल्डन ट्राएंगल:** इसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के क्षेत्र शामिल हैं और यह दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य अफीम उत्पादक क्षेत्र है और यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के लिए सबसे पुराने नशीले पदार्थों की आपूर्ति मार्गों में से एक है।
  - **गोल्डन क्रिसेंट:** इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं और यह अफीम उत्पादन और वितरण के लिए एक प्रमुख वैश्विक स्थान है।
- **चीन फैक्टर:** इन हेरोइन और मेथामफेटामाइन उत्पादक क्षेत्रों की सीमाएँ छिद्रपूर्ण हैं और कथित तौर पर विद्रोही समूहों के नियंत्रण में हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से चीनियों द्वारा समर्थित हैं।
  - यहां अवैध हथियार बनाए जाते हैं और भारत में सक्रिय भूमिगत समूहों को आपूर्ति की जाती है।

भारत में नशीली दवाओं की तस्करी के पीछे कारण: भारत में नशीली दवाओं की तस्करी के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से कुछ हैं:

- **भौगोलिक स्थिति:** भारत का स्थान "गोल्डन क्रिसेंट" और "गोल्डन ट्राइएंगल" क्षेत्रों के बीच है, जो प्रमुख दवा उत्पादक क्षेत्र हैं, जो इसे नशीली दवाओं की तस्करी के प्रति संवेदनशील बनाता है।
  - हेरोइन, अफ़ीम और हशीश जैसी नशीली दवाओं का उत्पादन गोल्डन क्रिसेंट में किया जाता है, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं, और उत्तर-पश्चिमी सीमा के माध्यम से भारत में तस्करी की जाती है।

- **छिद्रपूर्ण सीमाएँ (Porous borders):** भारत कई देशों के साथ सीमाएँ साझा करता है जो नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी के लिए जाने जाते हैं, और इन सीमाओं की अक्सर अच्छी सुरक्षा नहीं होती है और तस्कर आसानी से प्रवेश कर जाते हैं।
    - उदाहरण के लिए, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर-पूर्व राज्य नशीली दवाओं की तस्करी के लिए हॉटस्पॉट हैं।
- B भारत की आबादी बड़ी है, और मनोरंजन और औषधीय दोनों उद्देश्यों के लिए दवाओं की अधिक मांग है।
  o उदाहरण के लिए, मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरीय शहरों में मारिजुआना और कोकीन जैसी दवाओं की अत्यधिक मांग है।
- **जागरूकता की कमी:** नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी है, और बहुत से लोग नहीं जानते कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग की पहचान कैसे करें या सहायता कैसे प्राप्त करें।
  o उदाहरण के लिए, जो युवा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में शिक्षित नहीं हैं, वे विशेष रूप से नशीली दवाओं के तस्करों के शिकार बनने के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- **भ्रष्टाचार:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सरकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार नशीली दवाओं के तस्करों को निर्भीक होकर काम करने की अनुमति देता है।

भारत में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने में चुनौतियाँ:

- **डार्क नेट:** अपनी गुमनामी और कम जोखिम के कारण डार्क नेट बाजारों का पता लगाना मुश्किल होता है।
  o अध्ययनों से पता चलता है कि 62% डार्क नेट का उपयोग अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया जाता है।
  o डार्क नेट का उपयोग करके तस्करों को पकड़ने में सफलता दर दुनिया भर में बहुत कम रही है।
- **क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन:** कूरियर सेवाओं के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी भुगतान और डोरस्टेप डिलीवरी ने डार्क नेट लेनदेन को आकर्षक बना दिया है।
- **तस्कर रचनात्मक और तकनीक प्रेमी बनना:** तस्करों ने पंजाब में ड्रोन के माध्यम से नशीली दवाओं और बंदूकों की आपूर्ति जैसी नई युग की तकनीकों को अपना लिया है, जिसने सुरक्षा बलों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
- **अधिक सुरक्षित और गुमनाम तरीकों का उपयोग करना:** कोविड-19 महामारी के दौरान वाहन/जहाज/एयरलाइन मूवमेंट पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद नशीली दवाओं के तस्करों ने कूरियर/पार्सल/पोस्ट पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया है।
- **ड्रग्स लॉर्ड्स और NRI के बीच सांठगांठ:** हाल की जांच में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग और कई यूरोपीय देशों में स्थित NRI के साथ-साथ भारत में स्थानीय ड्रग लॉर्ड्स और गैंगस्टरों के साथ ड्रग कार्टेल के संबंध का पता चला है, जिनके पाकिस्तान में खालिस्तान आतंकवादियों और आईएसआई के साथ संबंध हैं।
- **स्थानीय गिरोहों के माध्यम से तस्करी:** एक नया चलन सामने आया है जिसमें संगठित गिरोह, जो मुख्य रूप से अपने स्थानीय क्षेत्रों में जबरन रिकवरी गतिविधियों को अंजाम देते थे, का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उनके पास तैयार सामान है।

भारत में नशीली दवाओं की तस्करी को विनियमित करने के लिए की गई पहल:

- **नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति (एनडीपीएस):** इसे 1985 में भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और नशीली दवाओं तथा साइकोट्रोपिक पदार्थों के उपयोग को विनियमित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
- **राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय पोर्टल:** ड्रग कानून प्रवर्तन में हितधारकों की बहुलता के कारण वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय आवश्यक हो गया है।
- **नशा करने वालों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए):** MoSJE नशा करने वालों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) के रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR):** MoSJE ने 2018-2025 के लिए NAPDDR लॉन्च किया।
  o इस योजना का लक्ष्य बहु-आयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल परिणामों को कम करना है।
- **नशा मुक्त भारत अभियान/ड्रग्स-मुक्त भारत अभियान:** इसे 15 अगस्त 2020 (स्वतंत्रता दिवस) को 32 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के 272 जिलों के लिए हरी झंडी दिखाई गई थी, जिनकी पहचान देश में दवाओं के उपयोग के मामले में सबसे कमजोर जिलों के रूप में की गई है।

o यह देश भर में 500 से अधिक स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी के साथ चालू है, जिन्हें NAPDDR योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

22वां विधि आयोग और समान नागरिक संहिता

संदर्भ: विधि आयोग ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विचार पर जनता से विचार मांगने का निर्णय लिया है।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में:

- यह सभी नागरिकों के लिए, धर्म की परवाह किए बिना, विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है।
- **अनुच्छेद 44:** संविधान का यह अनुच्छेद यूसीसी का संदर्भ देता है और कहता है, "राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।"
  o यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित अध्याय में है और इसलिए इसे प्रकृति में सलाहकार माना जाता है।
- **अनुच्छेद 37:** बताता है कि समान नागरिक संहिता (अन्य निदेशक सिद्धांतों के साथ) की दृष्टि भारतीय संविधान में एक लक्ष्य के रूप में निहित है जिसके लिए राष्ट्र को प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह मौलिक अधिकार या संवैधानिक गारंटी नहीं है।
  o कोई यूसीसी की मांग के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अदालतें इस मामले पर अपनी राय नहीं दे सकतीं।

यूसीसी का महत्व एवं आवश्यकता:

- **समान सिद्धांत:** सामान्य संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि जैसे पहलुओं के संबंध में समान सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम बनाती है। ताकि स्थापित सिद्धांत, सुरक्षा उपाय और प्रक्रियाएं निर्धारित की जा सकें और नागरिकों को विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में टकराव और विरोधाभासों के कारण संघर्ष न करना पड़े।
- **धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा:** धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानूनों का एक सेट सच्ची धर्मनिरपेक्षता की आधारशिला है।
  o यह धार्मिक आधार पर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करने में मदद करता है।
- **कमजोर और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा:** यह समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करता है।
  o सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक परंपराओं के नाम पर व्यक्तिगत कानूनों के माध्यम से महिलाओं को वंचित किया गया है।
  o इसलिए, यूसीसी महिलाओं को सम्मानजनक जीवन और उनके जीवन के साथ-साथ शरीर पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सभी समुदायों को एक साथ ला सकता है।
- **कलह में कमी:** जब पूरी आबादी समान कानूनों का पालन करना शुरू कर देगी, तो संभावना है कि इससे जीवन में अधिक शांति आएगी और दंगों में कमी आएगी ।
  o इसलिए, देश में शांतिपूर्ण जीवन के लिए धार्मिक सद्भाव बनाया जाएगा।
- **धर्म-आधारित भेदभाव को रोकना:** व्यक्तिगत कानून धर्म के आधार पर लोगों के बीच अंतर करते हैं। वैवाहिक मामलों के संबंध में समान प्रावधानों वाला एक एकीकृत कानून उन लोगों को न्याय प्रदान करता है जो भेदभाव महसूस करते हैं।
- **अन्यायपूर्ण रीति-रिवाजों और परंपराओं को समाप्त करना:** एक तर्कसंगत सामान्य और एकीकृत व्यक्तिगत कानून समुदायों में प्रचलित कई बुरे, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन रीति-रिवाजों और परंपराओं को खत्म करने में मदद करता है।
  o उदाहरण के लिए, हाथ से मैला ढोने की प्रथा के विरुद्ध कानून। हो सकता है कि यह अतीत में एक रिवाज रहा हो लेकिन भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र में इस रिवाज को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
- **राष्ट्रीय एकीकरण:** समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य में मदद करती है।
- **श्रेष्ठ अभ्यास:** 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता को वैध बनाने का फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर गोवा को समान नागरिक संहिता के साथ एक "चमकदार उदाहरण" के रूप में वर्णित किया।
- **वोट बैंक की राजनीति को हटाना:** यूसीसी को चुनने से राजनीतिक व्यवस्था का धार्मिक गठजोड़ दूर हो जाएगा जिसमें मतदाताओं को धर्म, जाति आदि के आधार पर विभाजित किया जाता है।
- **प्रशासन को आसान बनाना:** यूसीसी भारत के विशाल जनसंख्या आधार का प्रशासन करना आसान बनाता है।

- **यूसीसी का वैश्विक अभ्यास:** लगभग सभी मुस्लिम राष्ट्र जैसे मोरक्को, पाकिस्तान आदि यूसीसी का पालन कर रहे हैं।

यूसीसी के विरुद्ध तर्क:

- **विविधता और बहुसंस्कृतिवाद में बाधा:** भारतीय समाज की विविधतापूर्ण और बहुसांस्कृतिक होने के रूप में एक विशिष्ट पहचान है, और एकीकृत कानून इस राष्ट्र की इन अनूठी विशेषताओं को समाप्त कर सकता है।
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** धार्मिक निकाय इस आधार पर समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं कि यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
- **सांप्रदायिक अशांति उत्पन्न होना:** यह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा और इसके लागू होने पर देश में बहुत अशांति फैल सकती है।
    - ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि विवाह और विरासत से संबंधित कानून सदियों से धार्मिक निषेधाज्ञा का हिस्सा थे।

22वें विधि आयोग का गठन: आयोग के अध्यक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हैं।

कार्य:

- आयोग, अन्य बातों के अलावा, "उन कानूनों की पहचान करता है जिनकी अब आवश्यकता या प्रासंगिक नहीं है और जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है; राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करना और सुधार तथा सुधार के तरीके सुझाना शामिल है।
- ऐसे विधानों का सुझाव देना जो निदेशक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों"; और "सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, अस्पष्टताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके"।
- आयोग कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गौर कर रहा है जैसे-
  o समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कार्यान्वयन।
  o एक साथ चुनाव कराना।
- 22वें आयोग ने दावा किया है कि यूसीसी पर पिछले पैनल द्वारा समान विचार मांगे जाने के बाद कई साल बीत चुके हैं, और विभिन्न राय हासिल करने के लिए एक नए प्रयास की आवश्यकता है।
- आलोचकों के अनुसार, समान नागरिक संहिता के विचार पर जनता से विचार मांगने का विधि आयोग का निर्णय एक राजनीतिक पहल प्रतीत होता है जिसका उद्देश्य संभावित विभाजनकारी मुद्दे को ध्यान में लाना है।

आगे की राह

- यूसीसी के लक्ष्य को आदर्श रूप से टुकड़ों में पूरा किया जाना चाहिए, जैसे कि शादी की उम्र पर हालिया संशोधन। सरकार को समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने और लोगों, विशेषकर महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के पहलुओं से निपटने के लिए संविधान के उद्देश्यों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग और औषधि सुरक्षा

पाठ्यक्रम

मेन्स – GS-2 (गवर्नेंस)

संदर्भ: भारत में निर्मित दवाओं से गंभीर नुकसान होने और दुनिया भर से दर्जनों मरीजों की मौत की खबरें लगातार आती रहती हैं।

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग के बारे में:

- भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता (provider) है।
- यह विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50% से अधिक, अमेरिका में जेनेरिक मांग का 40% और यूके में सभी दवाओं का 25% आपूर्ति करता है।
- भारतीय फार्मास्युटिकल बाजार का अनुमान 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और फार्मा कंपनियां 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करती हैं।
  o हालाँकि, यह 1.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक फार्मास्युटिकल बाजार का एक छोटा सा हिस्सा है।

- वैश्विक स्तर पर, भारत फार्मास्युटिकल उत्पादन के मामले में मात्रा के हिसाब से तीसरे स्थान पर और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है।
- वैश्विक जेनेरिक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 30% से अधिक है लेकिन नई आणविक इकाई क्षेत्र में 1% से कम हिस्सेदारी है।
- **नई आणविक इकाई:** एक नवीन यौगिक जिसे पहले मनुष्यों में उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है।
  o आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, अगले दशक में घरेलू बाजार के तीन गुना बढ़ने की उम्मीद है।

भारत में फार्मा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे:

निश्चेतक औषधियाँ:

- नवीनतम रिपोर्ट श्रीलंका में दो मरीजों की मौत की है, जिन्हें भारत में बनी एनेस्थेटिक दवाएं दी गई थीं।

आई ड्राप (Eye drops):

- अभी पिछले महीने ही भारत में निर्मित आई ड्रॉप्स के कारण श्रीलंका में लगभग 30 मरीजों की आंखों में संक्रमण और 10 मरीजों में अंधापन हो गया था।
- भारत में बनी एनेस्थेटिक दवाओं के कारण मौतें हाल के दिनों में पहली बार हुई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ महीने पहले आई ड्रॉप्स के कारण संक्रमण, अंधापन और यहां तक कि मौतें होने की सूचना मिली थी, अटलांटा स्थित रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने उनमें अत्यधिक दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया पाया था।

कफ सिरप:

- भारत में उत्पादित दवाओं के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्टों की श्रृंखला पिछले साल शुरू हुई जब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने गाम्बिया में कम से कम 70 बच्चों की मौत को गंभीर किडनी की चोट से कफ सिरप से जोड़ा।
- सिरप में दोषी घटक डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल घातक रसायन थे जो प्रोपलीन ग्लाइकोल के सस्ते विकल्प के रूप में उपयोग किए जाते थे जो कि किसी भी दवा में यह कभी नहीं पाया जाना चाहिए था।
- गाम्बिया में हुई मौतों के तुरंत बाद, भारत में बने और दो घातक रसायनों वाले कफ सिरप ने दिसंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मृत्यु हो गई।
- भारत में निर्मित कफ सिरप फिर से खबरों में था जब WHO ने मार्शल द्वीप और माइक्रोनेशिया में पाई जाने वाली दूषित दवाओं को चिह्नित किया; संदूषण की पहचान ऑस्ट्रेलियाई नियामक द्वारा की गई थी।

चुनौतियाँ:

दवाओं की सुरक्षा:

- कुछ पारंपरिक निरीक्षणों को छोड़कर, भारतीय दवा नियामक अब तक यह सुनिश्चित करने के उपाय करने में विफल रहा है कि निर्यात और घरेलू उपयोग के लिए भारत में उत्पादित दवाएं सुरक्षित हैं।

गुणवत्ता परीक्षण में असफल होना:

- 2014-2016 में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग पांच प्रतिशत भारतीय दवाएं, जिनमें से कई बड़ी फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित हैं, गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहीं।
- एक अध्ययन से पता चलता है कि यह आंकड़ा बहुत अधिक हो सकता है।
- देश का फार्मा उद्योग बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा व्यक्त की गई गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को नकारता रहा है।

उत्पादन की लागत:

- भारत में उत्पादन लागत विकसित देशों की तुलना में 50 प्रतिशत कम है, लेकिन यह अभी भी चीन की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक है।
- इसका कारण कच्चे माल का 25-30 प्रतिशत महंगा होना, बिजली का 20 प्रतिशत अधिक महंगा होना और अन्य लागत जैसे वित्तपोषण, रसद, परिवहन आदि का 30 प्रतिशत अधिक महंगा होना है।

भारत में औषधियों का विनियमन

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940:

- यह अधिनियम भारत में दवाओं के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है।
- अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में बेची जाने वाली दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन सुरक्षित, प्रभावी और राज्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं।

- नकली और मिलावटी दवाओं के निर्माण और व्यापार के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में संशोधन किया गया था।

नई औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक, 2022:

- बदलती आवश्यकताओं को समायोजित करने और नई तकनीक को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मौजूदा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 को बदलने के लिए जुलाई 2022 में एक मसौदा विधेयक जारी किया।
- यह अधिनियम देश भर में दवा के आयात, उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करता है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन:

- यह भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) का उच्च विभाग है।
- सीडीएससीओ भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक नियामक संस्था है।
- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

भारत के औषधि महानियंत्रक:

- भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विभाग के प्रमुख हैं।
- यह भारत में रक्त और रक्त उत्पाद, IV तरल पदार्थ, टीके और सीरा (sera) जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।
- DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक भी तय करता है।

आगे की राह :

- **नियामक ढांचे को मजबूत करना:** सरकार को नियामक ढांचे को मजबूत करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लागू करना चाहिए कि भारत में उत्पादित मेडिसिन और दवाएं आवश्यक सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करती हों।
- **निरीक्षण और ऑडिट बढ़ाना:** विनिर्माण प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण से संबंधित किसी भी संभावित मुद्दे की पहचान करने और उसका समाधान करने के लिए दवा उद्योग के सभी स्तरों पर नियमित निरीक्षण और ऑडिट आयोजित किए जाने चाहिए।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना:** सरकार को नियामक प्रक्रिया को जनता और हितधारकों के लिए अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाकर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहिए।
  o यह सूचना के प्रसार में सुधार और सार्वजनिक परामर्श आयोजित करके किया जा सकता है।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना:** सरकार को नियामक एजेंसियों और उद्योग के पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान है।
- **अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग:** भारत को दवा विनियमन में श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि भारतीय दवा कंपनियां वैश्विक सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन कर रही हैं।

स्रोत: द हिंदू

अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत-अमेरिका संबंध

पाठ्यक्रम

- **मुख्य परीक्षा – GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)**

संदर्भ: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप का अनावरण किया है जो नियामक बाधाओं को दूर करने और सुचारू व्यापार तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में "गहरे सहयोग" के लिए निर्यात नियंत्रण को संरेखित करने पर केंद्रित है।

भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में:

द्विपक्षीय जुड़ाव:

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का आनंद लेते हैं, जो मानव प्रयास के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करती है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कई मुद्दों पर हितों के अभिसरण और जीवंत लोगों से लोगों के संपर्कों से प्रेरित है।
- नेतृत्व-स्तर पर नियमित आदान-प्रदान द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार का एक अभिन्न अंग रहा है।
- COVID-19 महामारी के बावजूद, भारत-यू.एस. रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, आर्थिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और लोगों से लोगों के संबंधों सहित व्यापक क्षेत्रों में विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों के तहत सहयोग में गहन भागीदारी देखी गई।

रक्षा एवं सुरक्षा:

- भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग "भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए नई रूपरेखा" पर आधारित है, जिसे 2015 में 10 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था।
- 2016 में, रक्षा संबंध को प्रमुख रक्षा साझेदारी (एमडीपी) के रूप में नामित किया गया था।
- द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और रक्षा आदान-प्रदान सैन्य-से-सैन्य सहयोग को गहरा करने के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

क्वाड:

- चार क्वाड साझेदारों (भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया) ने पहली बार 2004 में एक "कोर ग्रुप" का गठन किया, ताकि 2004 की सुनामी की संयुक्त प्रतिक्रिया के दौरान तेजी से सहायता जुटाई जा सके। 2017 के बाद से, क्वाड की गतिविधियां बढ़ी और तेज हुई हैं।

आतंकवाद विरोधी सहयोग:

- सूचना के आदान-प्रदान, परिचालन सहयोग और आतंकवाद विरोधी प्रौद्योगिकी और उपकरणों को साझा करने के साथ आतंकवाद-निरोध में सहयोग में काफी प्रगति देखी गई है।
- भारत-यू.एस. आतंकवाद-निरोध पर संयुक्त कार्य समूह विस्तारित CT सहयोग की देखरेख करता है।

व्यापार और आर्थिक संबंध:

- तेजी से बढ़ता व्यापार और वाणिज्यिक संबंध भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बहुआयामी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और हमारे माल और सेवाओं के निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य है।
- 2019 में वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 146 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत को अब तक का सबसे अधिक 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ।
- अमेरिका ने 2020-21 के दौरान 13.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रवाह के साथ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में मॉरीशस को पीछे छोड़ दिया।
- भारतीय एफडीआई के लिए अमेरिका शीर्ष 5 निवेश स्थानों में से एक है।

शिक्षा साझेदारी:

- यह भारत-अमेरिका संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और दोनों देश उच्च शिक्षा सहयोग के मजबूत संबंध और इतिहास साझा करते हैं।
- 2 फरवरी 1950 को भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा आदान-प्रदान पर एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया (USEFI) की स्थापना की गई थी।

भारतीय प्रवासी:

- अमेरिका में लगभग 4.2 मिलियन भारतीय अमेरिकी/भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारतीय अमेरिकी [3.18 मिलियन] अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा एशियाई जातीय समूह हैं।

भारत-अमेरिका संबंधों के बीच चुनौतियाँ:

- **व्यापार:** हाल ही में भारत और अमेरिका टैरिफ और संरक्षणवादी नीतियों को लेकर एक-दूसरे से भिड़ गए।
  o अमेरिका ने लगातार भारत पर उच्च टैरिफ का आरोप लगाया है और भारत ने अमेरिका पर अमेरिकी बाजारों पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय उत्पादों पर उच्च टैरिफ का आरोप लगाया है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार:** अमेरिका ने आईपीआर नीतियों के लिए लगातार भारत की आलोचना की है। इसने भारत पर जेनेरिक दवाओं की तुलना में प्रमुख कंपनियों विशेषकर फार्मास्युटिकल कंपनियों के बौद्धिक गुणों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है।
- **पाकिस्तान को लगातार समर्थन:** हालाँकि अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थन कम कर दिया है, फिर भी उसने पाकिस्तान को मौद्रिक सहायता प्रदान की है।
  o फरवरी 2016 में, ओबामा प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया कि वह पाकिस्तान को किसी भी परमाणु हथियार सक्षम प्लेटफॉर्म के हस्तांतरण के संबंध में अमेरिकी सांसदों की कड़ी आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान को आठ परमाणु-सक्षम F-16 लड़ाकू विमान और आठ सहित मिश्रित सैन्य सामान प्रदान करना चाहता है।
- **रूस के साथ संबंध:** रूस ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का समर्थन किया है। इससे भारत को अपनी रक्षा क्षमताएं विकसित करने में मदद मिली।
  o 2018 में, भारत ने अमेरिका के CAATSA अधिनियम की अनदेखी करते हुए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणाली, चार S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए रूस के साथ ऐतिहासिक समझौता किया।
- **ईरान के साथ संबंध:** अमेरिका ने ईरान पर उसके परमाणु विकास के कारण प्रतिबंध लगा रखा है। ईरान से तेल खरीदने में भारत की सामरिक रुचि है।
  o भारत के ईरान से तेल खरीदने के फैसले पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को प्रतिबंध लगाने की धमकी दी।
  o लेकिन हाल ही में इसने भारत को उन प्रतिबंधों से छूट दे दी जिससे भारत को ईरान से तेल खरीदने की अनुमति मिल गई।

आगे की राह

यह अत्यधिक संभावना प्रतीत होती है कि रणनीतिक, राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक दृष्टि से, भारत और अमेरिका के बीच संबंध वर्तमान नेतृत्व के तहत अपने प्रगति पथ को जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों का भारत पर प्रभाव लाभकारी और सकारात्मक रहने की संभावना है। भूराजनीतिक चालें भारत-अमेरिका संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं; हालाँकि, यह बहुआयामी और एक "अनिवार्य साझेदारी" बनी रहेगी।

स्रोत: द हिंदू

भारत-मिस्र संबंध

पाठ्यक्रम

- **मुख्य परीक्षा – GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)**

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री (पीएम) ने भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए 1997 के बाद पहली बार मिस्र का दौरा किया है।

भारत-मिस्र संबंधों के बारे में:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- भारत-मिस्र संबंधों का पता 2750 ईसा पूर्व से लगाया जा सकता है, जब फिरौन सहुर ने "पंट की भूमि (Land of Punt)" पर जहाज भेजे थे, जिसे प्रायद्वीपीय भारत माना जाता था।
- दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में मिस्र की ममियों को भारतीय नील-रंगे मलमल में लपेटने के साथ, आदान-प्रदान जारी रहा।

मैत्री संधि और द्विपक्षीय संबंध:

- 1950 के दशक में दोनों देश और भी करीब आ गए और 1955 में एक ऐतिहासिक मैत्री संधि संपन्न हुई।
- पिछले कुछ वर्षों के दौरान, दोनों देशों के बीच पारंपरिक रूप से मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय बैठकों और संपर्कों के नियमित आदान-प्रदान से गति मिली है।

आर्थिक संबंध:

- मार्च 1978 से, भारत-मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज के तहत प्रभावी रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार 4.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य तक पहुंच गया।
- महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, व्यापार की मात्रा में 2019-20 में मामूली गिरावट आई और यह 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई और 2020-21 में यह और भी कम होकर 4.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।
- विशेष रूप से, भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- भारत को मिस्र के प्रमुख निर्यातों में शामिल हैं: कच्चा कपास, कच्चे और निर्मित उर्वरक, तेल और तेल उत्पाद, जैविक और गैर-कार्बनिक रसायन, चमड़ा और लौह उत्पाद।
- भारत से मिस्र में प्रमुख आयात हैं: सूती धागा, तिल, कॉफी, जड़ी-बूटियाँ, तम्बाकू और दाल।
  o खनिज ईंधन; वाहन के पुर्जे; जहाज, नाव और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर; हड्डी रहित गोजातीय जमे हुए मांस के टुकड़े; और इलेक्ट्रिकल मशीनरी और पार्ट्स भी भारत से निर्यात किए जाते हैं।

रक्षा सहयोग:

- दोनों वायु सेनाओं ने 1960 के दशक में लड़ाकू विमानों के विकास पर सहयोग किया और भारतीय पायलटों ने 1960 के दशक से 1980 के दशक के मध्य तक अपने मिस्र के समकक्षों को प्रशिक्षित किया।
- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और मिस्र की वायु सेना दोनों फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू जेट उड़ाती हैं।
- 2022 में दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें अभ्यास में भी भाग लेने और प्रशिक्षण में सहयोग करने का निर्णय लिया गया है।
- भारतीय सेना और मिस्र सेना के बीच पहला संयुक्त विशेष बल अभ्यास, "एक्सरसाइज साइक्लोन-I" जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में पूरा हुआ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

- 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी' सहयोग सीएसआईआर (भारत) और एनआरसी (मिस्र) के बीच द्विवार्षिक कार्यकारी कार्यक्रमों और वैज्ञानिक सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
- दूसरा ISRO-NARSS JWG 2017 में काहिरा में आयोजित किया गया था।
- कृषि-जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी पर भारत-मिस्र कार्यशालाएँ क्रमशः 2018 में शिलांग में और 2019 में मुंबई में आयोजित की गईं।
- अल अज़हर विश्वविद्यालय, CEIT में एक आईटी केंद्र भी फरवरी 2019 से चालू है।

सांस्कृतिक संबंध:

- मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर (MACIC) की स्थापना 1992 में काहिरा में की गई थी।
- इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) के कार्यान्वयन के माध्यम से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
- केंद्र, हिंदी, उर्दू और योग कक्षाओं और फिल्मों की स्क्रीनिंग के माध्यम से भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के अलावा, सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करता है।
- 'इंडिया बाय द नाइल' उत्सव:
  o यह मिस्र में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है।
  o यह शास्त्रीय, समकालीन, प्रदर्शन और दृश्य कला, भोजन और लोकप्रिय संस्कृति के माध्यम से भारत के सार को एक ऐसी भाषा में प्रस्तुत करता है जो विविध सांस्कृतिक और कलात्मक पहलुओं को जोड़ती है।

o यह महोत्सव दिल्ली स्थित M/S टीमवर्क आर्ट्स द्वारा निर्मित है और आईसीसीआर और मिस्र के संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्थित है।

भारत-मिस्र संबंधों की चुनौतियाँ:

- **राजनीतिक मतभेद:** प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। उदाहरण के लिए, मिस्र ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) सुधारों पर भारत की स्थिति को साझा नहीं किया है।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** उत्तरी अफ्रीका में मिस्र की भौगोलिक स्थिति इसे लीबिया और सूडान सहित कई अस्थिर क्षेत्रों और संघर्ष क्षेत्रों के निकट रखती है।

  o यह अस्थिरता क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक निवेश जैसे पारस्परिक हित के क्षेत्रों में अनिश्चितता पैदा करके अप्रत्यक्ष रूप से भारत-मिस्र संबंधों को प्रभावित कर सकती है।
- **क्षेत्रीय राजनीति को आगे बढ़ाना:** भारत और मिस्र दोनों के बीच जटिल क्षेत्रीय संबंध हैं।

  o इन रिश्तों को संतुलित करना, विशेष रूप से जब वे भारत के लिए कश्मीर या मिस्र के लिए इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष जैसे मुद्दों से संबंधित हों, तो चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** मिस्र सहित अफ्रीका में चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति एक और महत्वपूर्ण चुनौती है।
  - चीन की बेल्ट एंड रोड पहल अफ्रीका में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है और इससे क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ गया है।
  - मिस्र और व्यापक अफ्रीकी क्षेत्र में भारत की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की कोशिश करते हुए चीन के साथ संबंधों को संतुलित करना भारत के लिए एक मुश्किल कूटनीतिक चुनौती हो सकती है।

आगे की राह

ऐतिहासिक संबंधों से प्रेरित और वर्तमान भू-राजनीतिक उथल-पुथल से प्रभावित होकर, यह स्पष्ट है कि भारत और मिस्र अब एक करीबी संबंध पर एकजुट हो रहे हैं, जो भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं और स्वायत्त विदेश नीतियों दोनों पर नजर रखता है।

स्रोत: द हिंदू

अर्थव्यवस्था

भारत में वित्तीय समावेशन

संदर्भ: जून 2023 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया, जिसका नाम अंतर्दृष्टि है।

अंतर्दृष्टि के बारे में:

- इस नवोन्मेषी टूल का उद्देश्य प्रासंगिक मापदंडों को कैप्चर करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
- डैशबोर्ड, जो वर्तमान में आरबीआई में आंतरिक उपयोग के लिए है, बहु-हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करेगा।

वित्तीय समावेशन के बारे में:

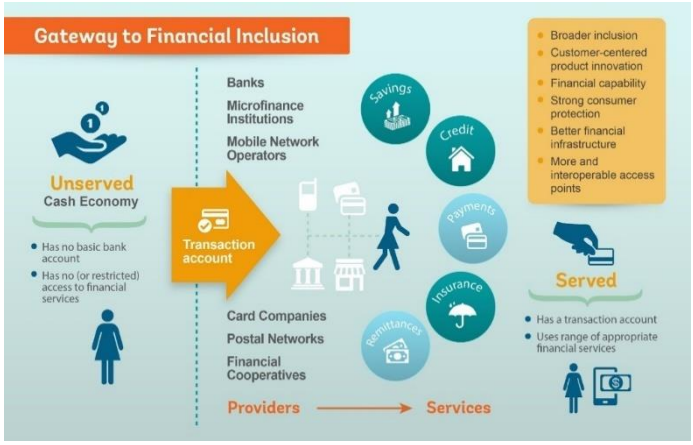

- विश्व बैंक के अनुसार, वित्तीय समावेशन का मतलब है कि व्यक्तियों और व्यवसायों के पास किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच है जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं।
  o वित्तीय सेवाओं की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता वित्तीय समावेशन के 3 स्तंभ हैं।
  o यह किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग और वित्तीय समाधान और सेवाएँ प्रदान करने की एक विधि है।
- वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार भारत में आधिकारिक तौर पर 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पेश की गई थी।

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

- भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए एक बुनियादी नो-फ्रिल्स बैंकिंग खाता
- बचत उत्पाद (निवेश और पेंशन सहित)
- सरल क्रेडिट उत्पाद और नो-फ्रिल्स खातों से जुड़े ओवरड्राफ्ट
- प्रेषण, या धन हस्तांतरण की सुविधा
- सूक्ष्म बीमा (जीवन) और गैर-सूक्ष्म बीमा (जीवन और गैर-जीवन)
- माइक्रो पेंशन और
- वित्तीय साक्षरता

वित्तीय समावेशन का महत्व:

- वित्तीय समावेशन आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता को मजबूत करता है और गरीबों के बीच बचत की अवधारणा का निर्माण करता है।
- वित्तीय समावेशन समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह वंचित आबादी के समग्र आर्थिक विकास में मदद करता है।
- भारत में गरीबों और वंचित लोगों के उत्थान के लिए उन्हें संशोधित वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करके प्रभावी वित्तीय समावेशन की

आवश्यकता है।

भारत में वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ:

- **सामाजिक-आर्थिक कारक:** वित्तीय बहिष्करण कम आय वाले परिवारों की सामाजिक स्थितियों से संबंधित है, जो उपलब्ध वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं।
  o कम आय, कम बचत और आम तौर पर जागरूकता का निम्न स्तर जैसी विभिन्न बाधाएँ वित्तीय समावेशन में बाधा डालती हैं।
- **भौगोलिक कारक:** रंगराजन समिति की समीक्षा से पता चलता है कि देश के पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में घरों में वित्तीय बहिष्कार आंशिक रूप से खराब बुनियादी ढांचे के कारण सबसे अधिक है।
  o इसके साथ-साथ कुछ क्षेत्रों में दूरदर्शिता और कम आबादी के कारण पहुंच संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
- **उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सीमित उपलब्धता:** वित्तीय समावेशन का मुख्य चालक स्थिर और विश्वसनीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रसार है।
  o दरवाजे पर लेनदेन की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी की कमी वित्तीय समावेशन में बाधा है।
- **दायित्व की धारणा:** वित्तीय संस्थान अनियमित आय वाले छोटे मूल्य और लाभहीन ग्राहकों को सेवा देने में अनिच्छुक हैं।
  o बैंक समावेशन को व्यावसायिक अवसर के बजाय एक दायित्व के रूप में देखते हैं।
  o यह बैंकों को कम आय वाले व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने से हतोत्साहित करता है।
- **दस्तावेज़ों की कमी:** उन्हें औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक पहुँचने से रोकने वाला एक अन्य कारक विभिन्न दस्तावेज़ प्रमाण की आवश्यकता होती है।
  o आमतौर पर गरीबों के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण आदि जैसे दस्तावेजों का अभाव होता है।
- **वित्तीय निरक्षरता:** बुनियादी शिक्षा का अभाव लोगों को वित्तीय समावेशन से संबंधित सरल जानकारी का भी पालन करने से रोकता है।
  o परिणामस्वरूप, ग्रामीण आबादी उच्च दरों पर वित्त प्राप्त करने के लिए ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर रहती है, जिससे गरीबी और ऋण चुकौती का दुष्चक्र पैदा होता है।
- **पहुंच:** वर्तमान में, भारत के 6 लाख गांवों में से केवल 5% में ही बैंक शाखाएं हैं। निम्न स्तर की बैंकिंग सेवाओं वाले राज्यों में 296 अल्प बैंकिंग सुविधा वाले जिले हैं।
  o इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की पहुँच ख़राब है जिसके कारण वित्तीय बहिष्कार होता है।

वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम:

भारत सरकार की पहल:

- पीएम मुद्रा योजना - यह गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों हेतु छोटे ऋण के लिए है
- पीएम जनधन योजना
- बीमा योजना - पीएम सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना
- पेंशन योजना - अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना, प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम-एसवाईएम)
- डिजिटल भुगतान को गहरा करने पर नंदन नीलेकणि पैनल
- किसान क्रेडिट कार्ड

आरबीआई की पहल:

- वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) 2019-24
- भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ)
- एटीएम अवसंरचना
- परियोजना वित्तीय साक्षरता

आगे की राह

बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता और मजबूत बैंक शाखा नेटवर्क विकासात्मक गतिविधियों के प्रमुख सूत्रधार हैं। एक मजबूत और मजबूत वित्तीय प्रणाली किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि, विकास और प्रगति का स्तंभ है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश न्यायसंगत और स्थाई तरीके से विकसित हो तो वित्तीय बहिष्कार की समस्या से निपटना होगा।

Source: Business Standard

भूगोल

आर्कटिक महासागर का 2030 तक बर्फ मुक्त होना

संदर्भ: नेचर कम्युनिकेशंस के नए अध्ययन के अनुसार, आर्कटिक महासागर 2030 के दशक तक गर्मियों में बर्फ मुक्त हो सकता है, भले ही हम अब और तब के बीच उत्सर्जन को कम करने का अच्छा काम करें।

आर्कटिक क्षेत्र के बारे में:

Image source: AMAP

- इसे आमतौर पर 66° 34' उत्तर अक्षांश के उत्तर में आर्कटिक सर्कल के ऊपर के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए समझा जाता है, जिसमें केंद्र में उत्तरी ध्रुव के साथ आर्कटिक महासागर शामिल है।
- आर्कटिक परिषद: आठ आर्कटिक राज्य-कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका आर्कटिक परिषद बनाते हैं।

आर्कटिक क्षेत्र का महत्व:

जलवायु प्रभाव:

- आर्कटिक समुद्री बर्फ वैश्विक जलवायु पैटर्न को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने और ध्रुवीय क्षेत्रों को ठंडा रखने में मदद मिलती है।
- समुद्री बर्फ एक अवरोध के रूप में कार्य करती है, ऊपर की ठंडी हवा को नीचे के गर्म पानी से अलग करके हवा को ठंडा रखती है।

जैव विविधता और स्वदेशी समुदाय:

- समुद्री बर्फ में परिवर्तन से जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है, विशेषकर ध्रुवीय भालू और वालरस जैसे स्तनधारियों पर।
- शिकार, प्रजनन और प्रवास के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर स्वदेशी आर्कटिक आबादी प्रभावित होती है।

आर्थिक अवसर और प्रतिस्पर्धा:

- बर्फ का आवरण कम होने से शिपिंग लेन खुलती है और आर्कटिक में प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच आसान हो जाती है।
- इससे क्षेत्र में प्रभाव और संसाधन दोहन के लिए देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है।

संसाधन और निवासी:

- आर्कटिक लगभग चार मिलियन निवासियों का घर है, जिनमें से लगभग दसवां हिस्सा स्वदेशी लोगों के रूप में माना जाता है।

o आर्कटिक महासागर और इसके आस-पास का भूभाग वैश्विक वैज्ञानिक साथियों के साथ-साथ नीति निर्माताओं के लिए अत्यधिक रुचि और अनुसंधान का एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है।
o आर्कटिक पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के वायुमंडलीय, समुद्री विज्ञान और जैव-रासायनिक चक्रों को प्रभावित करता है।

खनिज स्रोत:

- आर्कटिक क्षेत्र में कोयला, जिप्सम और हीरे के समृद्ध भंडार हैं और जस्ता, सीसा, प्लसर सोना और क्वार्ट्ज के भी पर्याप्त भंडार हैं।
  o अकेले ग्रीनलैंड के पास दुनिया के दुर्लभ पृथ्वी भंडार का लगभग एक चौथाई हिस्सा है।

हाइड्रोकार्बन:

- आर्कटिक में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का भंडार भी मौजूद है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है।
  o इसलिए आर्कटिक संभावित रूप से भारत की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

परिणाम :

- **ध्रुवीय जेट स्ट्रीम का कमजोर होना:** समुद्री बर्फ के कम होने से ध्रुवीय जेट स्ट्रीम कमजोर हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप यूरोप में तापमान और लू बढ़ जाती है।
  o उत्तर पश्चिम भारत में बेमौसम बारिश को भी इस कमज़ोरी से जोड़ा गया है।
- **बर्फ का पिघलना:** ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का पिघलना समुद्र के स्तर को बढ़ाने में योगदान देता है, यह पूरी तरह से पिघलने से संभावित रूप से सात मीटर की वृद्धि होती है।
- **समुद्री जल की संरचना में परिवर्तन:** आर्कटिक महासागर और समुद्रों के गर्म होने के साथ-साथ लवणता और अम्लीकरण में परिवर्तन, समुद्री और आश्रित प्रजातियों सहित जैव विविधता को प्रभावित करता है।
- **जीव-जंतुओं को प्रभावित करना:** आर्कटिक प्रवर्धन के कारण बढ़ी हुई वर्षा लाइकेन की उपलब्धता और पहुंच को प्रभावित करती है, जिससे आर्कटिक जीवों में भुखमरी और मृत्यु हो जाती है।
- गैसीय उत्सर्जन: पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से कार्बन और मीथेन निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीनहाउस गैसें हैं।
  o यह लंबे समय से निष्क्रिय बैक्टीरिया और वायरस भी छोड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से बीमारी फैल सकती है।

भारत पर आर्कटिक वार्मिंग का प्रभाव:

बढ़ता समुद्र स्तर:

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट, '2021 में वैश्विक जलवायु की स्थिति' के अनुसार, भारतीय तट पर समुद्र का स्तर वैश्विक औसत दर की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है।
- इस वृद्धि का प्राथमिक कारण ध्रुवीय क्षेत्रों, विशेषकर आर्कटिक में समुद्री बर्फ का पिघलना है।

कनेक्टिविटी:

- आर्कटिक की बर्फ पिघलने और इसकी भौगोलिक स्थिति अमेरिका, यूरोप और उत्तर पूर्व एशिया के बीच सबसे कम समुद्री दूरी सुनिश्चित करती है।
- यह संभवतः वैश्विक समुद्री वाणिज्य को बदल देगा, जो वर्तमान में मलक्का जलडमरूमध्य और स्वेज़ नहर के माध्यम से पारंपरिक पूर्व-पश्चिम मार्ग के माध्यम से संचालित होता है।

मानसून:

- भारत में बदलते आर्कटिक और मानसून के प्रभाव के बीच संबंध देश में होने वाली चरम मौसम की घटनाओं और पानी तथा खाद्य सुरक्षा के लिए वर्षा पर भारी निर्भरता के कारण महत्व में बढ़ रहा है।

भू-राजनीति:

- आर्कटिक की बर्फ पिघलने से भू-राजनीतिक तापमान (geopolitical temperatures) भी बढ़ रहा है।
- 2018 में, आर्कटिक नीति पर चीन के श्वेत पत्र (White Paper) ने खुद को 'निकट-आर्कटिक राज्य' कहा।
- शिपिंग मार्गों के खुलने और संसाधन निष्कर्षण में वृद्धि की संभावनाओं के कारण तीन बड़े देश-अमेरिका, चीन और रूस-तथा नाटो इस क्षेत्र में स्थिति और प्रभाव के लिए प्रयास कर रहे हैं।

आगे की राह :

- 2026 तक तापमान में भारी वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य विलुप्त हो जाएंगे, जिससे 2026 के बाद क्या होगा इसके

बारे में अनुमान लगाना कई मायनों में व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार, जलवायु योजना के माध्यम से व्यापक और प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से सबसे खराब चीजों को होने से रोकने में मदद करना सही काम है।

स्रोत: द हिंदू

भारत में आकस्मिक बाढ़

पाठ्यक्रम

- **मेन्स - GS 1 (भूगोल) और GS 3 (आपदा प्रबंधन)**

संदर्भ: हाल ही में भारत और पाकिस्तान अचानक आई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

आकस्मिक बाढ़ के बारे में:

- अचानक आने वाली बाढ़ भू-आकृतिक निचले इलाकों, नदियों, सूखी झीलों और घाटियों में तेजी से आने वाली बाढ़ है।
- जो तेज़ गति से चलने वाले तूफान, भारी बारिश, हिमनद झील, फटने या कृत्रिम बांधों की विफलता के कारण होती है।

भारत में बाढ़ की स्थिति: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) रिपोर्ट

- भारत में, 40 मिलियन हेक्टेयर (10% प्रतिशत भूमि) के क्षेत्र को बाढ़ का खतरा है।
- हर साल औसतन 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है, 1600 लोगों की जान चली जाती है और 1,800 करोड़ रुपए का खर्च आता है।
- 1970 से 2004 के बीच प्रति वर्ष औसतन 3 बार बाढ़ आ चुकी है। हालाँकि, 2005 और 2019 के बीच, वार्षिक औसत बढ़कर 11 हो गया। 2005 तक औसतन 19 जिले सालाना प्रभावित होते थे। 2005 के बाद, यह संख्या बढ़कर 55 हो गई।

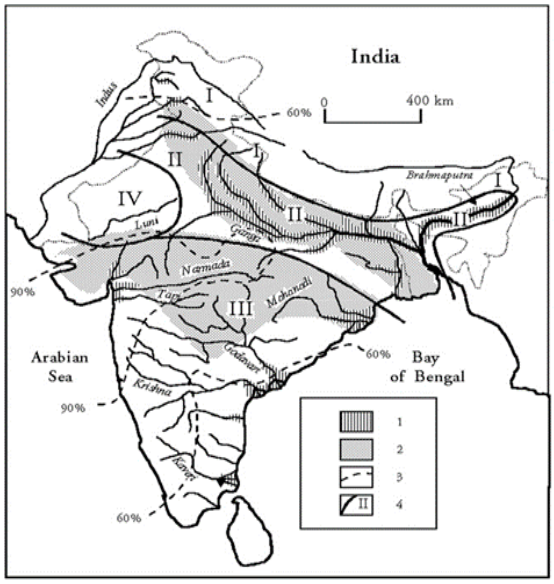

Source: researchgate.net

- 2017 के विश्लेषण से पता चलता है कि 4.48 मिलियन भारतीय नदी बाढ़ के संपर्क में हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।

भारत में बाढ़ के कारण:

फिजियोलॉजिकल कारण:

- भारी वर्षा: भारत में बाढ़ का एक प्रमुख कारण भारी वर्षा है।
  o ऐसा प्रभाव पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट क्षेत्र, असम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में देखा जा सकता है।
- नदी-प्रवाह की घुमावदार प्रवृत्ति: समतल भूभागों में नदियों की एक विशिष्ट सीमा के भीतर बहने या रास्ता बदलने की प्रवृत्ति भी ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदानी इलाकों की निचली पहुंच जैसे घुमावदार क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनती है।
- डेल्टा क्षेत्रों में गाद जमा होना: समुद्री ज्वार द्वारा नदी-मुहानों पर गाद जमा होने से नदियों की निर्वहन क्षमता ख़राब हो जाती है जिससे उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है।
- भूकंप और भूस्खलन: कभी-कभी यह पाया गया है कि भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद नदी अपना रास्ता बदल लेती है जिससे उसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है।

o ऐसे उदाहरण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आदि पर्वतीय क्षेत्र के राज्यों में पाए जा सकते हैं।

- नदियों के मुक्त प्रवाह में बाधा: सड़क, तटबंध, रेलवे लाइन, नहर आदि नदियों के मुक्त प्रवाह में बाधा डालते हैं जिससे क्षेत्र में बाढ़ आती है।
- बादल फटना: बादल फटने से कम समय में भारी मात्रा में वर्षा होती है, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है।
  o आकस्मिक बाढ़ आमतौर पर हिमालय क्षेत्र में होती है।

मानव निर्मित कारण:

- बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निरंतर लोगों का बसना: कई नदियों के बाढ़ क्षेत्र, विशेषकर उत्तरी मैदानी इलाकों जैसे कोसी, घाघरा, गंडक, सरयू आदि में हर साल बाढ़ आती है।
  o फिर भी इन क्षेत्रों में लोग बस गये हैं।
  o इससे विशेषकर असम और बिहार के मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण बार-बार नुकसान होता है।
- प्राकृतिक निकायों पर अतिक्रमण: दलदल और झीलों सहित प्राकृतिक आर्द्रभूमि के विनाश के कारण वे क्षेत्र अवरुद्ध हो गए हैं जो पहले पानी के सिंक के रूप में काम करते थे।
  o चेन्नई में बाढ़ का मुख्य कारण यही है।
- तीव्र और अनियोजित शहरीकरण: योजनाओं को मंजूरी दिए बिना अव्यवस्थित तरीके से घरों के निर्माण के कारण हिमालय क्षेत्र में बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ के दौरान कई इमारतें बह गईं।
- प्रकृति का विनाश: विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों और नदी तटों पर वनों की बढ़ती कटाई के साथ, बाढ़ के विरुद्ध ये विशेष रक्षा कवच हट दी गई है।
  o यही कारण है कि चक्रवात के कारण आई बाढ़ के कारण तटों पर भयंकर विनाश होता है।

आकस्मिक बाढ़ के परिणाम:

- **जान-माल हानि:** हर साल बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और बह जाते हैं।
- **संचारी रोगों का फैलना:** हैजा, टाइफाइड बुखार, हेपेटाइटिस और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी जलजनित बीमारियाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फैलती हैं।
  o बाढ़ से वेक्टर जनित बीमारियाँ भी होती हैं, जो परजीवियों और मच्छर जैसे रोगजनकों के माध्यम से फैलती हैं।
  o परिणामस्वरूप, बाढ़ पीड़ितों का स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है।
- **फसलों का विनाश:** ये आपदा हर साल बाढ़ बड़ी संख्या में फसलों को नष्ट कर देती है।
- **पशुधन की हानि:** मनुष्यों की तरह, पशुधन भी बाढ़ के दौरान विस्थापित हो जाते हैं और अपने आवास के नुकसान के कारण मर जाते हैं।
- संचार संपर्क और परिवहन में व्यवधान: बाढ़ के कारण पुल, रेल, बिजली संयंत्र आदि जैसे परिवहन संपर्कों को नुकसान होता है, जिससे उन क्षेत्रों में संचार बाधित होता है।
- **आर्थिक और सामाजिक व्यवधान:** इससे अर्थव्यवस्था में ठहराव आ जाता है क्योंकि लोग दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इस स्थिति के सँभालने में समय लगता है।

बाढ़ की समस्या के निवारक उपाय:

- बेहतर बाढ़ चेतावनी प्रणालियाँ: प्रभावी बाढ़ चेतावनी प्रणालियाँ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय पर कार्रवाई करने में मदद कर सकती हैं और लोगों की जान बचा सकती हैं।
  o पूर्व-योजना से बाढ़ के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक करने का समय मिल जाता है।
- **बाढ़-रोधी आवास प्रणालियों का निर्माण:** बाढ़ के दौरान कंक्रीटिंग फर्श बहुत उपयोगी हो सकते हैं। घरों को वॉटर प्रूफ़ किया जाना चाहिए और झटके की संभावना को कम करने के लिए बिजली के सॉकेट को दीवारों से ऊंचे स्तर पर लगाया जाना चाहिए।
- **इमारतों का निर्माण बाढ़ स्तर से ऊपर करना:** बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने और बाढ़ के दौरान निकासी के लिए इमारतों का निर्माण जमीन से एक मीटर ऊपर किया जाना चाहिए।
- **आर्द्रभूमि निर्माण और पुनर्वनीकरण को प्रोत्साहित करना:** अधिक से अधिक आर्द्रभूमि बनाने से अत्यधिक नमी को सोखने में मदद

मिल सकती है क्योंकि आर्द्रभूमि स्पंज के रूप में कार्य करती है।

o जंगली क्षेत्र भी भारी जल प्रवाह को धीमा कर सकते हैं, जिससे बाढ़ का प्रभाव कम हो सकता है।

o ऊपरी क्षेत्रों में वनीकरण से बाढ़ से होने वाले नुकसान के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- **बाढ़ अवरोधक स्थापित करना:** ये बाढ़ द्वार हैं जो अवरोध के पीछे के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

  o बाढ़ के पानी को बनाई गई सीमा से बाहर रखने के लिए इन्हें इमारतों के आसपास भी रखा जा सकता है।

- **GIS का विकास:** आपदा प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित राष्ट्रीय डेटाबेस है।

  o GIS आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मापदंडों के संदर्भ में जानकारी तक पहुंचने के लिए आपातकालीन उत्तरदाताओं के लिए एक प्रभावी उपकरण है।

आगे की राह :

- जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के साथ, भारत में बाढ़ की भयावहता और तीव्रता भी बढ़ने वाली है। इस प्रकार, एनडीएमए दिशानिर्देशों के साथ-साथ भारत में बाढ़ प्रबंधन में सेंडाई ढांचे के आपदा जोखिम लचीलापन दृष्टिकोण को अपनाना समय की मांग है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

पर्यावरण

दुनिया भर में झीलों का सिकुड़ना

संदर्भ: एक नए अध्ययन के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी झीलों और जलाशयों में से 50 प्रतिशत से अधिक पिछले तीन दशकों में जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण मुख्य रूप से सिकुड़ गए हैं।

अध्ययन के मुख्य आकर्षण:

- इन जल निकायों से, 1992 और 2020 के बीच लगभग 600 क्यूबिक किमी पानी खत्म हो गया था, जो 2015 के पूरे वर्ष के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग किए जाने वाले कुल पानी के बराबर राशि है।
- शोधकर्ताओं ने पाया कि 1,052 प्राकृतिक झीलों की जांच की गई थी, 457 को पिछले तीन दशकों में महत्वपूर्ण पानी का नुकसान हुआ था।
- उन्होंने प्राकृतिक झीलों में पानी की मात्रा में शुद्ध गिरावट का 57 प्रतिशत मानव गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया, जैसे कि पानी की अस्थिर खपत, और बाद में दो के साथ तापमान और संभावित वाष्पीकरण (पीईटी) बढ़ते हुए दो-दो जलवायु परिवर्तन की भूमिका का संकेत देते हैं।
- पिछले अध्ययनों के विपरीत, आर्द्र उष्णकटिबंधीय और उच्च ऊंचाई में स्थित प्राकृतिक झीलें पानी की कमी का अनुभव कर रही हैं।
- दुनिया भर में सभी जलाशयों में से दो-तिहाई ने पानी के महत्वपूर्ण भंडारण में गिरावट का अनुभव किया है।
- हालाँकि, हाल ही में भरे गए 183 जलाशयों के कारण, जलाशयों में जल स्तर में शुद्ध वैश्विक वृद्धि देखी गई।
- जल स्तर में गिरावट के पीछे मुख्य कारण अवसादन है - रेत और पत्थरों जैसे कणों की प्रक्रिया पानी के निकाय के तल पर बसती है।

अध्ययन के निष्कर्ष:

- अध्ययन ने दुनिया भर में सबसे खराब प्रभावित सबसे बड़ी झीलों को भी बताया और वे आकार में क्यों सिकुड़ रहे हैं।
- उदाहरण के लिए, मध्य एशिया में अरल सागर, अर्जेंटीना में मार चिकिटा झील (Lake Mar Chiquita), मध्य पूर्व में मृत सागर, और कैलिफोर्निया में सैलटन सागर मुख्य रूप से पानी की खपत के कारण सूख गया है।
- जबकि, बढ़ते तापमान और (संभावित वाष्पीकरण) PET ने अफगानिस्तान में लेक गौड-ए-ज़ारेह, मिस्र में तोशका झीलों, और तुर्कमेनिस्तान में कारा-बोगाज़-गोल, मोंगोलिया में झील ख्यारगास और चीन में झील ज़ोनग के रूप में चिन्हित किया गया था।।
- विशेष रूप से, झीलें पिछले 20 वर्षों में आर्कटिक के झील-समृद्ध क्षेत्रों के 82 प्रतिशत में पूरी तरह से सिकुड़ गई हैं या गायब हो गई हैं।
- भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में स्थित जलाशयों में से आधे से अधिक पानी के भंडारण में काफी गिरावट देखी गई है, यह मुख्य रूप से अवसादन के कारण हुआ।
- इसके अलावा, देश में सबसे खराब प्रभावित प्राकृतिक झीलों में लद्दाख की त्सो मोरारी है।

झीलों के सिकुड़ने के कारण:

- **मानव गतिविधियाँ:** प्राकृतिक झीलों में पानी की मात्रा में 57 प्रतिशत शुद्ध गिरावट मानव गतिविधियों के लिए, जैसे कि पानी की अस्थिर खपत।
- **जलवायु परिवर्तन:** आर्कटिक झीलें "वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों के कारण पानी की वर्षा, अपवाह, तापमान, और संभावित वाष्पीकरण (पीईटी) में परिवर्तन के संयोजन के कारण सिकुड़ गई हैं, जो संभवतः प्राकृतिक परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन के समवर्ती परिणाम हैं।
- **अवसादन:** पानी के स्तर में गिरावट के पीछे का मुख्य कारण अवसादन है - रेत और पत्थरों जैसे कणों की प्रक्रिया पानी के एक निकाय के तल पर बसती है।

सिकुड़ती झीलों के परिणाम:

- वर्ष 2023 में वैश्विक आबादी के एक-चौथाई लोग, लगभग दो बिलियन लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि वे बड़े जल निकायों के साथ बेसिन में रहते हैं, जिन्होंने पिछले तीन दशकों में अपने जल स्तर में महत्वपूर्ण गिरावट देखी है।

- इन सूखने वाली झीलों में से कई को पानी और ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में पहचाना गया है।
- इन झीलों के कम आकार के परिणामस्वरूप न केवल मीठे पानी की गिरावट और पर्यावरणीय गिरावट होती है, बल्कि पानी और कार्बन चक्रों को भी बाधित करती है।
- इन जल निकायों में व्यापक पानी की कमी, "विशेष रूप से बढ़ते झील के तापमान के साथ, अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सकता है और वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन को बढ़ा सकता है, यह देखते हुए कि झीलें कार्बन साइकिलिंग के हॉटस्पॉट हैं।"

आगे की राह :

- एकीकृत तरीके से इन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता है। वैश्विक तापमान को नीचे लाने के लिए पानी की खपत और जलवायु शमन पर प्रतिबंध जैसे कदम उन्हें संरक्षित करने के कुछ तरीके हैं।
- यह जलाशयों में अवसादन को कम करने में भी मदद करेगा क्योंकि अवसादन की दर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी होती है - यह तब बढ़ जाती है जब अत्यधिक वर्षा होती है, साथ ही भूमि की गड़बड़ी जैसे कि जंगल की आग, भूस्खलन और वनों की कटाई भी होती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत में ट्रांसजेनिक फसलें

संदर्भ: तीन राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ने हाल ही में एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, जिसे केंद्र की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा एक नए तरह के ट्रांसजेनिक कपास के बीज का परीक्षण करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

ट्रांसजेनिक फसलों के बारे में:

- ट्रांसजेनिक फसलें ऐसे पौधे हैं जिन्हें आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों के माध्यम से संशोधित किया गया है।
- इन फसलों को नई विशेषताएँ या लक्षण देने के लिए उनके डीएनए में विशिष्ट जीन डाले गए हैं जो पारंपरिक ब्रीडिंग मेथड्स (traditional breeding methods) के माध्यम से प्रजातियों में स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते हैं।

आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के बारे में:

- आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) कोई भी जीवित जीव है जिसकी आनुवंशिक सामग्री को कुछ वांछनीय तकनीकों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है।
- आनुवंशिक संशोधन का उपयोग पहले इंसुलिन, टीके, और बहुत कुछ के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया गया है।
- फसलों में, आनुवंशिक संशोधन में फसल की कुछ विशेषताओं को बदलने के लिए नियंत्रित परागण - फसलों को बेहतर बनाने की पारंपरिक विधि - का उपयोग करने के बजाय डीएनए में हेरफेर शामिल होता है।

भारत में स्थिति:

- भारत में, केवल कपास को वर्तमान में व्यावसायिक रूप से जीएम फसल के रूप में खेती की जाती है। ट्रांसजेनिक तकनीक का उपयोग करके बैगन, टमाटर, मक्का और छोले जैसी अन्य फसलों के लिए परीक्षण चल रहे हैं।
- GEAC ने GM सरसों हाइब्रिड DMH-11 की पर्यावरणीय रिलीज को मंजूरी दी, जिससे यह पूर्ण व्यावसायिक खेती के करीब पहुंच गया।
- हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेनिक खाद्य फसलों की अनुमति पर सवाल उठाते हुए एक कानूनी मामला है। वे प्रतिबंधित हर्बिसाइड्स का उपयोग करके किसानों के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए, जीएम सरसों पर ठहरने की तलाश करते हैं।

लाभ:

- **रोग प्रतिरोधी और स्थिरता:** आनुवंशिक संशोधनों के माध्यम से, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों को बीमारियों के लिए प्रतिरोधी बनाया जाता है। यह उनकी स्थिरता और उपज को बढ़ाता है।
- **पर्यावरण संरक्षण:** ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, जीएम जानवरों और फसलों की वृद्धि को अक्सर कम समय, उपकरण और रसायनों की आवश्यकता होती है, और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, मिट्टी के कटाव और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **लंबे समय तक शेल्फ लाइफ:** आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों में एक लंबा शेल्फ जीवन होता है। यह परिवहन और भंडारण की आसानी को बढ़ाता है।
- **सामर्थ्य:** इनपुट के कम बोझ और लंबे समय तक शेल्फ जीवन के कारण अपव्यय कम हो जाता है, उत्पादन की कीमतें कम होती है। जिससे सामर्थ्य बढ़ जाती है।

- **फोर्टिफिकेशन:** संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, कुछ जीएम खाद्य पदार्थों को विटामिन या खनिज सामग्री के मामले में अधिक पौष्टिक बनने के लिए इंजीनियर किया गया है।
  o यह न केवल लोगों को उन पोषक तत्वों को प्राप्त करने में मदद करता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, बल्कि तीसरी दुनिया के देशों में कुपोषण के खिलाफ लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नुकसान:

- यह माना जाता है कि इन आनुवंशिक रूप से इंजीनियर खाद्य पदार्थों की खपत से बीमारियों के विकास का कारण बन सकता है, जो एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरक्षा हो सकता है।
- यह क्रॉस-परागण विधि अन्य जीवों को नुकसान पहुंचा सकती है जो पर्यावरण में पनपते हैं।
- यह तकनीक कार्सिनोजेनिक हो सकती है। यह एक किलर टेक्नोलॉजी है जो मिट्टी, रोगाणुओं, परागणकों, लगभग सभी औषधीय जड़ी - बूटियों को मारती है और फसल विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह मनुष्यों में कैंसर भी पैदा कर सकता है।

आगे की राह :

- GM फसलों के लिए अलग -अलग दृष्टिकोण के कारण, परीक्षण पर अनुमोदन का पालन नहीं करने वाले राज्यों के मुद्दे को हल करने के लिए, GEAC डीबीटी द्वारा देश भर के कुछ क्षेत्रों को 'अधिसूचित परीक्षण साइटों के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ऐसी 42 प्रस्तावित साइटें हैं और यदि यह सफल हो जाती है, तो इन स्थानों पर जीएम फसलों का परीक्षण करने की इच्छुक कंपनियों और संस्थानों को परीक्षणों के लिए राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

स्रोत: हिंदू

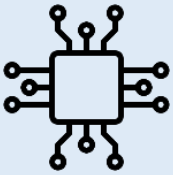

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

निश्चित खुराक संयोजन (FDCS) प्रतिबंध मुद्दा

संदर्भ: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना प्रकाशित की है, जिसमें चिकित्सीय औचित्य की कमी और उनके निषेध के लिए एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश का हवाला देते हुए 14 फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।

निश्चित खुराक संयोजन (एफडीसी) दवाओं के बारे में:

- संयोजन उत्पाद या निश्चित खुराक दवा संयोजन (FDCs) एक ही खुराक रूप में दो या अधिक सक्रिय दवाओं से मिलकर बनता है।
- यूएसए में खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) एक संयोजन उत्पाद को दवा और उपकरण, जैविक उत्पाद और उपकरण, दवा और जैविक उत्पाद, या दवा, उपकरण, और जैविक उत्पाद से बना उत्पाद के रूप में संयोजन उत्पाद को परिभाषित करता है ।
- यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि अधिकांश दवाओं को एकल यौगिकों के रूप में तैयार किया जाना चाहिए।
- उदाहरण: फेनिटोइन + फेनोबार्बिटोन सोडियम, क्लोरफेनिरामाइन + कोडीन फॉस्फेट + मेन्थॉल सिरप, सल्बुटामोल + ब्रोमहेक्सिन, पेरासिटामोल + ब्रोमहेक्सिन + फेनिलफ्रिन + क्लोरफेनिरामाइन + गुआफेफेसिन ईटीसी

प्रतिबंध का औचित्य:

- प्रतिबंध, जो तुरंत लागू होता है, इन दवा संयोजनों और ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का पालन करता है।
- विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की, "इन एफडीसी के लिए कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है और एफडीसी में मानव के लिए जोखिम शामिल हो सकता है"।

एफडीसी दवाओं के लाभ:

- **कार्रवाई का पूरक तंत्र:** एफडीसी फॉर्मुलेशन एक्शन के पूरक तंत्र के साथ दवाओं को जोड़ती है, जो उपचार के चिकित्सीय प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है।

o एक ही खुराक के रूप में कई दवाओं की संयुक्त कार्रवाई एक बीमारी के विभिन्न पहलुओं को लक्षित कर सकती है या अधिक व्यापक उपचार दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है।

- **सहक्रियात्मक प्रभाव:** FDCs सहक्रियात्मक प्रभावों को प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां दवाओं की संयुक्त कार्रवाई अकेले उपयोग की जाने वाली व्यक्तिगत दवाओं की तुलना में अधिक चिकित्सीय प्रभाव पैदा करती है।
  o इसके परिणामस्वरूप रोगियों के लिए बेहतर प्रभावकारिता और बेहतर उपचार परिणाम हो सकते हैं।
- **बेहतर सहिष्णुता:** कुछ मामलों में, FDC में दवाओं के संयोजन से दुष्प्रभाव कम करने या सहनशीलता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
  o दवाओं के बीच बातचीत प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को कम कर सकती है, जिससे उपचार रोगियों के लिए अधिक प्रबंधनीय हो जाता है।
- **लम्बी उत्पाद जीवन-चक्र प्रबंधन:** FDC फॉर्मूलेशन उन दवाओं के संयोजन से एक उत्पाद के जीवन चक्र का विस्तार कर सकते हैं जो पहले से ही व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित हो चुके हैं।
  o यह फार्मास्युटिकल कंपनियों को पूरी तरह से नई दवाओं के लिए स्वीकृति विकसित करने और प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बिना नए उपचार विकल्पों को नया करने और पेश करने की अनुमति देता है।
- **लागत बचत:** एफडीसीएस दोनों रोगियों और हेल्थकेयर सिस्टम के लिए लागत बचत का कारण बन सकता है। एक एकल सूत्रीकरण में कई दवाओं को मिलाकर, उपचार की समग्र लागत कम हो सकती है।
  o यह दवा को अधिक सस्ती और सुलभ बना सकता है, विशेष रूप से संसाधन-कृत्रिम सेटिंग्स में।
- **कम से कम पिल-बर्डन:** एफडीसी का उपयोग करने से मरीज को लेने की आवश्यकता होती है।
  o यह उपचार को सरल बना सकता है और दवा कार्यक्रम के लिए रोगी के अनुपालन (adherence) में सुधार कर सकता है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें नियमित रूप से कई दवाएं लेने की आवश्यकता होती है।

एफडीसी के नुकसान:

- किसी दिए गए रोगी के लिए उपयुक्त दवाओं और/या सबसे उपयुक्त संबंधित शक्तियों के साथ उपलब्ध एफडीसी नहीं हो सकता है, जिससे कुछ रोगियों को बहुत अधिक अवयव मिल सकता है और अन्य बहुत कम हो सकते हैं।
  o इस प्रकार, FDCS "चिकित्सकों की खुराक रेजिमेंस को अनुकूलित करने की क्षमता को सीमित करता है।"
- यदि एक एफडीसी का उपयोग करने से प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिक्रिया के कारण जिम्मेदार सक्रिय अवयव की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
- वैज्ञानिकों को बहु-ड्रग योगों के विकास चरणों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि सक्रिय अवयवों और विलेयता तथा विघटन को प्रभावित करने वाले excipients के बीच संगतता मुद्दे।

स्रोत: हिंदू

विविध

हिरोशिमा एआई प्रक्रिया

संदर्भ: हिरोशिमा, जापान में 19-21 मई, 2023 तक आयोजित वार्षिक ग्रुप ऑफ सेवन (जी-7) शिखर सम्मेलन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को विनियमित करने के साधन के रूप में हिरोशिमा AI प्रक्रिया (HAP) की शुरुआत की।

हिरोशिमा एआई प्रक्रिया के बारे में:

- इसका उद्देश्य भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों को अपनाना है।
- G7 नेताओं ने एक मंत्रिस्तरीय मंच बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसे "हिरोशिमा एआई प्रक्रिया" के रूप में जाना जाता है, जो कि

बौद्धिक संपदा अधिकारों और विघटन जैसे ChatGPT जैसे जनरेटिव एआई उपकरणों के बारे में मुद्दों पर चर्चा करेगा।
o यह इस वर्ष के अंत तक गठित होने वाला है।

हिरोशिमा एआई प्रक्रिया का महत्व:

- यह देशों को कुछ प्रमुख नियामक मुद्दों पर एक सामान्य समझ विकसित करने में मदद कर सकता है, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी असहमति से पूर्ण कलह का परिणाम नहीं है।
- यह प्रक्रिया विभिन्न उद्देश्यों के लिए एआई के उपयोग में 'निष्पक्ष उपयोग' सिद्धांत की भूमिका और दायरे में अधिक स्पष्टता ला सकती है।
- यह कॉपीराइट सामग्री के अन्य एआई-संबंधित उपयोगों से प्रति मशीन लर्निंग के लिए उपयोग को अलग कर सकता है। यह बदले में वैश्विक प्रवचन (global discourse) को प्रभावित कर सकता है और इस मुद्दे पर प्रैक्टिस कर सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बारे में:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव खुफिया प्रक्रियाओं का अनुकरण है। एआई के विशिष्ट अनुप्रयोगों में विशेषज्ञ प्रणाली, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और भाषण मान्यता तथा मशीन विज़न शामिल हैं।
- उदाहरण: रोबोटिक्स और स्वचालन, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), पैटर्न मान्यता मशीन सीखने का एक सबसेट है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के एप्लिकेशन:

- **हेल्थकेयर सेक्टर:** मशीन लर्निंग का उपयोग तेजी से, सस्ता और अधिक सटीक निदान के लिए किया जा रहा है और इस प्रकार रोगी परिणामों में सुधार और लागत को कम करना है।
  o उदाहरण, IBM वॉटसन और चैटबॉट ऐसे कुछ उपकरण हैं।
- **व्यावसायिक क्षेत्र:** अत्यधिक दोहराए जाने वाले कार्यों की देखभाल करने के लिए रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन को लागू किया जाता है जो मनुष्यों की तुलना में तेजी से और सहजता से प्रदर्शन करता है।
  - मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए एनालिटिक्स और सीआरएम प्लेटफार्मों में एकीकृत किया जा रहा है।
- **शिक्षा क्षेत्र:** एआई कुछ शैक्षिक प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकता है जैसे कि ग्रेडिंग, रीवार्डिंग मार्क्स (rewarding marks) आदि इसलिए शिक्षकों को अधिक समय दे सकता है।
  o आगे, यह छात्रों का आकलन कर सकता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो सकता है, जिससे उन्हें अपनी गति से काम करने में मदद मिल सकती है। एआई बदल सकता है कि छात्र कहां और कैसे सीखते हैं, यह शायद कुछ शिक्षकों को रेप्लेस्मेंट भी कर सकता है।
- **वित्तीय क्षेत्र:** यह व्यक्तिगत वित्त अनुप्रयोगों पर लागू किया जा सकता है और व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर सकता है और वित्तीय सलाह प्रदान कर सकता है।
  o आज सॉफ्टवेयर वॉल स्ट्रीट पर मनुष्यों की तुलना में अधिक ट्रेड करता है।
- **कानूनी क्षेत्र:** स्वचालन के कारण पहले से ही लंबित मामलों का तेजी से समाधान हो सकता है, जो मामलों का विश्लेषण करते समय टाइम को कम करके समय और अधिक कुशल प्रक्रियाओं का बेहतर उपयोग कर सकता है।
- **विनिर्माण क्षेत्र:** अब लंबे समय से विनिर्माण के लिए रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, हालांकि, अधिक उन्नत घातीय प्रौद्योगिकियां उभरी हैं जैसे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3 डी प्रिंटिंग) जो एआई की मदद से पूरे विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला सकती है।
- **इंटेलिजेंट रोबोट:** रोबोट एक मानव द्वारा दिए गए कार्यों का प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि सेंसर के कारण वास्तविक दुनिया से भौतिक डेटा जैसे प्रकाश, गर्मी, तापमान, आंदोलन, ध्वनि, धमाके और दबाव आदि का पता लगा सकते है।
  o इसके अलावा, उनके पास कुशल प्रोसेसर, कई सेंसर और विशाल मेमोरी, खुफिया प्रदर्शित करने के लिए हैं।
- **स्पीच पहचनना:** ऐसे बुद्धिमान प्रणालियां हैं जो वाक्यों और उनके अर्थों के संदर्भ में भाषा को सुनने और ग्रास्पिंग (grasping) करने में सक्षम हैं, जबकि मानव इससे बात करता है।
- **साइबर सुरक्षा:** भारत में ई-गवर्नेंस पर 20 वें सम्मेलन में यह चर्चा की गई थी कि एआई साइबर सुरक्षा को अधिक टीथ प्रदान कर सकता है और इसका पता लगाया जाना चाहिए।

एआई का नैतिक उपयोग:

- एआई उपकरण व्यवसायों के लिए नई कार्यक्षमता की एक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं, जबकि एआई का उपयोग भी नैतिक प्रश्न उठाता है क्योंकि, बेहतर या बदतर के लिए, एआई प्रणाली ने जो कुछ भी सीखा है उसे सुदृढ़ करता है।
- यह समस्याग्रस्त हो सकता है क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जो सबसे उन्नत एआई उपकरणों में से कई को रेखांकित करता है, केवल उस डेटा के रूप में स्मार्ट हैं जो वे प्रशिक्षण में दिए गए हैं।
  o क्योंकि यह एक मानव का चयन करता है कि एआई कार्यक्रम को प्रशिक्षित करने के लिए डेटा का उपयोग क्या किया जाता है, मशीन लर्निंग बायस की क्षमता निहित है और इसे बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए।
- एआई की नैतिक चुनौतियों में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं: अनुचित रूप से प्रशिक्षित एल्गोरिदम और मानव पूर्वाग्रह के कारण पूर्वाग्रह; गहरे नकली और फ़िशिंग के कारण दुरुपयोग; एआई लिबेल और कॉपीराइट मुद्दों सहित कानूनी चिंताएं; नौकरियों का उन्मूलन; और डेटा गोपनीयता चिंताएं, विशेष रूप से बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और कानूनी क्षेत्रों में।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में चुनौतियां:

- डेटा पारिस्थितिक तंत्र को सक्षम करने की कमी।
- एआई अनुसंधान की कम तीव्रता।
- एआई विशेषज्ञता, जनशक्ति और स्किलिंग के अवसरों की अपर्याप्त उपलब्धता।
- व्यावसायिक प्रक्रियाओं में एआई को अपनाने के लिए उच्च संसाधन लागत और कम जागरूकता।
- अस्पष्ट गोपनीयता, सुरक्षा और नैतिक नियम।
- एआई के शोध और अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए अनाकर्षक बौद्धिक संपदा शासन।
- एआई पेशेवरों में से केवल 4% उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित; लो H इंडेक्स (उद्धरण) और डेटा सेट।
- भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में सरकारी प्रयास:
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नेशनल प्रोग्राम:** यह अंतरिम बजट 2019 में घोषित किया गया था। कार्यक्रम को नेशनल सेंटर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना द्वारा एक हब के साथ -साथ उत्कृष्टता के 6 केंद्रों के साथ उत्प्रेरित किया जाएगा।
- NITI AAYOG और TATA इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) ने तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI-LED समाधानों- स्वास्थ्य सेवा, कृषि और स्मार्ट मोबिलिटी में AI-LED समाधानों को संचालित करने के लिए उन्नत अनुसंधान करने के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ICTAI) की स्थापना के लिए सहयोग शुरू किया।
- **इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम (एनएम-आईसीपी) पर राष्ट्रीय मिशन:** यह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेतृत्व में साइबर-भौतिक प्रणालियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम है। बजट 2019 ने मिशन के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए।
- **AIRAWAT (AI रिसर्च, एनालिटिक्स एंड नॉलेज अस्मिलेशन प्लेटफॉर्म):** $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में, भारत सरकार के थिंक-टैंक NITI AAYOG ने हाल ही में भारत के पहले AI- विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को 'Airawat' (AI रिसर्च, एनालिटिक्स और नॉलेज अस्मिलेशन प्लेटफॉर्म) नामक एक दृष्टिकोण पेपर जारी किया।
  o इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के शोध और विकास का मार्गदर्शन करना है।

आगे की राह :

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। भारत में लगभग 200 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट-अप आज विभिन्न उद्योगों के लिए एआई-आधारित समाधानों का नवाचार और निर्माण कर रहे हैं। यह बड़े डेटा विश्लेषण में मदद करके डिजिटल इंडिया मिशन को पूरक कर सकता है जो एआई का उपयोग किए बिना संभव नहीं है।

एआई शासन के लिए एक "संपूर्ण समाज" दृष्टिकोण हमें व्यापक-आधारित नैतिक सिद्धांत, संस्कृतियां और आचार संहिता को विकसित करने में सक्षम करेगा, ताकि डिजाइन, विकास और तैनाती के चरणों के दौरान आवश्यक नुकसान-शिथिल उपायों (harm-mitigating measures), समीक्षा और ऑडिट को सुनिश्चित किया जा सके, और एआई के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, समावेश और सामाजिक ट्रस्ट को फलने -फूलने के लिए और असाधारण सफलताओं के बारे में लाने के लिए यह वादा करता है।

स्रोत: हिंदू

बालासोर ट्रेन दुर्घटना और भारतीय रेलवे सुरक्षा का मुद्दा

संदर्भ: ओडिशा के बालासोर में हालिया रेल दुर्घटना, जिसमें तीन ट्रेनों की टक्कर शामिल है, यह भारत की रेल सेवाओं का सामना करने वाली चुनौतियों का एक दुखद अनुस्मारक (reminder) है।

- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार, रेलवे दुर्घटनाओं में 2010 और 2021 के बीच हर साल औसतन 23,000 लोगों की मौत हुई है।

भारत की रेल सेवाओं के बारे में:

- भारतीय रेलवे कोविड -19 महामारी से एक वर्ष पहले 23 मिलियन की तुलना में अब हर दिन लगभग 15 मिलियन यात्रियों को वहन करता है।
- भारत के पास अपने रेल बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, और वर्ष 2023-24 में, पूंजीगत व्यय के लिए 2.4-लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- वर्ष 2021 में, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वंदे भारत लेबल वाली 75 नई अर्ध-उच्च गति वाली ट्रेनों को 75 सप्ताह में कई बार चलाया जाएगा, और कई पहले ही शुरू हो चुके हैं।
- यात्री सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है, लेकिन सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है।
- हालांकि इस तरह की घातक ट्रेन दुर्घटनाएं आमतौर पर बहुत बार नहीं होती हैं, ये कभी-कभी दोहरा उठती हैं।

ट्रेन दुर्घटनाएं: एक अवलोकन

- **पटरी से उतरना:** यह भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। सुरक्षा प्रोटोकॉल में लैप्स, ट्रैक रखरखाव, और ट्रैक दोषों की पहचान करने और सुधारने में विफलता के परिणामस्वरूप ट्रेने पटरी से उतरती हैं।
  - उदाहरण के लिए, 2017 में पुरी-हरिद्वार यूटल एक्सप्रेस का पटरी से उतरना, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए, को ट्रैक रखरखाव में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।
- **टकराव:** ट्रेन टकराव सिग्नलिंग सिस्टम, मानव त्रुटियों और ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने में विफलता के कारण हुआ है।
  - ऐसी एक घटना 2014 में उत्तर प्रदेश में गोरखधम एक्सप्रेस और एक रुकी हुई माल ट्रेन के बीच टकराव हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप उच्च संख्या में हताहत और चोटें आई।
- **लेवल क्रॉसिंग दुर्घटनाएं:** लेवल क्रॉसिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लैप्स ने ट्रेनों और सड़क वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं को जन्म दिया है। मानवयुक्त स्तर के क्रॉसिंग को खत्म करने में विफलता, अपर्याप्त चेतावनी प्रणाली, और सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने में लापरवाही ने इस तरह की दुर्घटनाओं में योगदान दिया है।
  - उदाहरण के लिए, 2011 में, उत्तर प्रदेश के कांशीरामनगर जिले में ट्रेन-बस की टक्कर में 38 लोग मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए।
- **सिग्नल विफलताएं:** ट्रेन दुर्घटनाओं के लिए खराबी या अनुचित सिग्नलिंग सिस्टम जिम्मेदार हैं। सिग्नलिंग संचालन में अपर्याप्त रखरखाव, दोषपूर्ण उपकरण और मानवीय त्रुटियों के परिणामस्वरूप टकराव और अन्य दुर्घटनाएँ हुई हैं।
  - पश्चिम बंगाल (1999) में दो गाड़ियों की टक्कर एक सिग्नलिंग त्रुटि के कारण हुई।
- **भीड़भाड़ और तेज रफ़्तार:** उनकी क्षमता से परे और तेज गति से परे गाड़ियों की भीड़ भी दुर्घटनाओं को जन्म देती है। उचित भीड़ प्रबंधन की कमी और गति सीमाओं को लागू करने में विफलता महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताएं हैं।
- वर्ष 2018 अमृतसर ट्रेन दुर्घटना, जहां एक ट्रेन ने रेलवे की पटरियों के पास एक दशहरा घटना को देखते हुए भीड़ को कुचल दिया, जिससे कई घायल हुए, इसमें भीड़भाड़ से जुड़े जोखिमों पर प्रकाश डाला गया।

चुनौतियां और कमियां:

- **क्षमता की कमी:** यात्रियों और माल ढुलाई की उच्च मात्रा में दैनिक परिवहन किया जाता है, जिससे भीड़भाड़ और देरी होती है, जिससे संचालन की दक्षता प्रभावित होती है।
- **सुरक्षा चिंताएं:** भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। नेटवर्क ने ट्रेन के व्युत्पन्नों सहित दुर्घटनाओं और घटनाओं की महत्वपूर्ण संख्या का अनुभव किया है, जिसके परिणामस्वरूप घातक चोटें आई हैं। यात्री और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन:** ट्रैक, स्टेशनों और सिग्नलिंग सिस्टम सहित भारतीय रेलवे के मौजूदा बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण और उन्नयन की आवश्यकता होती है।

o एजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सुचारू संचालन और परिवहन सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता को बाधित करता है।

- **फंडिंग की कमी:** भारतीय रेलवे फंडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स में वित्तीय चुनौतियों का सामना करती है। ऐसी परियोजनाओं की लागत पर्याप्त है, और पर्याप्त धनराशि हासिल करना आवश्यक है।
  o रेलवे अधिक सरकारी धन और आंतरिक संसाधनों पर निर्भर करता हैं, जो निवेश के दायरे को सीमित कर सकता हैं।
- **परिवहन के अन्य तरीकों से प्रतिस्पर्धा:** भारतीय रेलवे परिवहन के वैकल्पिक तरीकों से प्रतिस्पर्धा, जैसे रोडवेज और वायुमार्ग से प्रतिस्पर्धा है।
  o माल और यात्री परिवहन क्षेत्रों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए चुनौतियों का सामना करती है।
- **कुशल मानव संसाधन:** भारतीय रेलवे को कुशल मानव संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से सुरक्षा, रखरखाव और संचालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में।
  o योग्य कर्मियों के साथ रिक्तियों को भरना और उचित प्रशिक्षण प्रदान करना कुशल और सुरक्षित रेलवे संचालन के लिए महत्वपूर्ण है।

2021 CAG रिपोर्ट: CAG ने मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एक और रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- यह देखा गया, "रेलवे ट्रैक का उचित रखरखाव दुर्घटनाओं के बिना ट्रेन संचालन के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।"
- इसके मुख्य कारण थे:
  o कमजोर योजना,
  o निष्क्रिय ट्रैक मशीनें,
  o कार्य बल में रिक्तियां और
  o स्थायी तरीके से कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी।

सरकार द्वारा की गई पहल

- **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई):** सरकार ने रेलवे से संबंधित घटकों में एफडीआई की अनुमति दी है, जिससे क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है।
  o अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक, रेलवे से संबंधित घटकों में एफडीआई प्रवाह यूएस $ 1,107.60 मिलियन था।
- **राष्ट्रीय रेल योजना:** सरकार एक व्यापक "राष्ट्रीय रेल योजना" पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य रेल नेटवर्क को परिवहन के अन्य तरीकों के साथ एकीकृत करना और देश में एक बहु-मोडल परिवहन प्रणाली विकसित करना है।
- **नया ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण प्रणाली:** अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (RDSO), भारतीय रेलवे के अनुसंधान शाखा ने विक्रेता पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए "नया ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण प्रणाली" नामक एक डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली शुरू की है।
- **समर्पित माल कॉरिडोर (DFCs):** माल यातायात के अनुपात को बढ़ाने और माल परिवहन की दक्षता में सुधार करने के लिए समर्पित माल ढुलाई गलियारों का निर्माण चल रहा है।
  o पश्चिमी बंगाल में डंकुनी से पंजाब में लुधियाना के लिए पश्चिम बंगाल में डंकुनी से पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे (WDFC) मुंबई से उत्तर प्रदेश और पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे (EDFC) इस पहल का हिस्सा हैं।
- **रेल किसान:** "रेल किसान" पहल का उद्देश्य किसानों के लिए समर्पित ट्रेनें प्रदान करके कृषि वस्तुओं के परिवहन को बढ़ावा देना है।
  o इस कार्यक्रम के तहत, देश भर के किसानों को लाभान्वित करते हुए 49,000 टन से अधिक माल आठ मार्गों पर ले जाया गया है।
- **स्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के पुनर्विकास के लिए कार्यक्रम:** सरकार ने एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत भारत भर में 400 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।
  o इसका उद्देश्य सुरक्षा, आराम, यात्री सुविधाओं, मूल्य वर्धित सेवाओं और दक्षता के उच्च मानकों के साथ आत्मनिर्भर स्टेशन बनाना है।
- **खनन जिलों और उत्तर पूर्व को जोड़ना:** समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार किया जा रहा है।
  o क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए व्यापक गेज लाइनों को बढ़ाया जा रहा है, और परिवहन को बढ़ाने हेतु खनन जिलों के लिए रेलवे कनेक्टिविटी मैप की जा रही है।
- **आत्मनिर्भरता के लिए क्वेस्ट:** "आत्म निर्भर भारत" पहल के हिस्से के रूप में, रेलवे विभिन्न परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं।
  o इनमें "कवच (Kavach)" नामक स्वदेशी विरोधी टक्कर प्रणाली का विकास शामिल है, जो अत्यधिक ऊर्जा-कुशल "वंदे भारत"

उच्च गति वाली ट्रेनों की शुरूआत है, और शून्य दुर्घटनाओं को प्राप्त करने का लक्ष्य है।

आगे की राह :

- पिछले एक दशक में प्रति मिलियन-ट्रेन किलोमीटर की दुर्घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन पटरियों का खराब रखरखाव और रोलिंग स्टॉक तथा ओवरस्ट्रैक्टेड स्टाफ समस्याएं हैं कि रेलवे अब ग्लिट्ज़ी फेसड (glitzy facades) के साथ छलावरण (camouflage) नहीं कर सकते हैं। बालासोर में दुर्घटना को भारत के रेलवे विकास योजनाओं को सही ट्रैक पर प्रेरित करना चाहिए।
- एंटी कॉलिजन सिस्टम (anti-collision systems) सहित सुरक्षा उपायों का विस्तार हो रहा है, लेकिन यह पर्याप्त गति से नहीं। अधिक महत्वपूर्ण परिचालन और नियोजन स्तरों पर रेलवे द्वारा सुधारात्मक उपाय होने चाहिए। इसे अपनी प्राथमिकताओं को आधुनिक बनाने और तर्कसंगत बनाने के लिए और अधिक संसाधन खोजना होगा।

PRACTICE QUESTIONS

Q1. अनुच्छेद 299 के तहत अनुबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ऐसे अनुबंधों के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
2. अनुच्छेद 299 उस तरीके को चित्रित करता है जिसमें ये अनुबंध संपन्न होते है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक कार्यकारी निकाय है।
2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) बिजली के सीमा के बाहर व्यापार की देखभाल करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. शिवसमुद्रम झरना कृष्णा नदी के तट पर है।
2. लक्ष्मणतीर्थ और कब्बानी कावेरी के दाहिने तट की सहायक नदियाँ हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q4. विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका मुख्यालय रोम में है।
2. इसकी स्थापना खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा ही की गई थी।
3. वर्ष 2020 में इसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 3
(D) 1,2, और 3

Q5. प्रोटेरोज़ोइक ईऑन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस समय के आसपास जटिल रूप कवक का निर्माण हुआ।
2. यह विवर्तनिक रूप से सक्रिय काल था।
3. इस अवधि के दौरान बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 2 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 3
(D) 1,2, और 3

Q6. ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसके उत्पादों में जल, जल वाष्प शामिल हैं।
2. इसमें शून्य कार्बन फुटप्रिंट है।
3. इसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए ईंधन कोशिकाओं में किया जा सकता है
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 3
(D) 1,2, और 3

Q7. प्रधानमंत्री वनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की एक पहल है।
2. इसमें केवल प्रमुख वन उत्पाद शामिल हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क या टोल एकत्र करने का काम सौंपा गया है।

2. NHAI एक कार्यकारी संस्था है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q9. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी केवल एक पीठ है जो दिल्ली में बैठती है।
2. यह केवल सेबी की अपील ही ले सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q10. समुद्री शैवाल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेटर होते हैं।
2. ये पानी के अंदर केल्प वन बनाते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

11. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को संकलित और जारी करता है।
2. यह हर साल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) संकलित और जारी करता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

12. हिरमंड/हेलमंद नदी के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. यह ईरान की सबसे लंबी नदी है।
2. हामुन झील अफगानिस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
उपरोक्त में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q13. ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ओपेक के सदस्य वैश्विक तेल आपूर्ति का 35 प्रतिशत नियंत्रित करते हैं।
2. ओपेक में 15 सदस्य हैं जिनके पास दुनिया के 82 प्रतिशत प्रमाणित भंडार हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इन टीकों के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है।
2. अबौसिन (Abaucin) एक प्रजाति-चयनात्मक एंटीबायोटिक है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नेक्रोफिलिया लाशों के प्रति एक कामुक आकर्षण है।
2. आईपीसी के तहत नेक्रोफिलिया एक दंडनीय अपराध है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q16. आईएनएस विक्रांत के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. इसे कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है।
2. यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमानवाहक पोत है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q17.विलफुल डिफॉल्टर्स (Wilful defaulters) के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद वे ऋणदाता को अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक गए।
2. ये दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

18. गैलेक्सी JO206 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. यह कुम्भ राशि में स्थित है।
2. यह पृथ्वी से 700 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

19. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. यह मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद कर सकता है।
2. यह महिला एवं बाल अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q20. अंजदीप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. यह शैलो वॉटर क्राफ्ट (एसडब्ल्यूसी) परियोजना के आठ जहाजों में से तीसरा है।
2. यह तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियान नहीं चला सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

21. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. यह शहरी विकास मंत्रालय के अधीन है।
2. इसे 2017 में लॉन्च किया गया था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

22. न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी।
2. डिजिटल बुनियादी ढांचा इसके फोकस क्षेत्रों में से एक है।
3. इसका मुख्यालय बीजिंग में है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

Q23. ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है।
2. यह अवैध दवाओं और अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक वैश्विक लीडर है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) 1, 2 और 3

24. बेतेल्गेउज़ (Betelgeuse) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय खगोल विज्ञान में इसे 'थिरुवतिराई' या 'आर्द्रा' कहा जाता है।
2. यह ओरायन तारामंडल में स्थित है।
3. यह सूर्य से भी छोटा है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

25. ChatGPT के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें:
1. यह अपनी गलतियाँ भी स्वीकार कर सकता है।
2. इसे "मानव प्रतिक्रिया से सुदृढीकरण सीखना (आरएलएचएफ)" का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है।
3. इसकी प्रतिक्रियाएँ पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकती हैं।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।
(A) केवल 3
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

26. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अध्यक्ष और अन्य सदस्य तीन वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं।
2. यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

27. गोल्डीलॉक्स परिदृश्य (Goldilocks scenario) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मूल्य स्थिरता प्राप्त करने की संभावना अधिक है।
2. महँगाई और बेरोज़गारी अधिक है।
उपरोक्त में से कौन सी घटना गोल्डीलॉक्स परिदृश्य के दौरान घटित होती है?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

28. अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी (Anak Krakatau volcano) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह अटलांटिक महासागर में स्थित है।
2. यह प्रसिद्ध क्रैकटाऊ ज्वालामुखी के घराने का है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

29. राम प्रसाद बिस्मिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उन्होंने 'देशवासियों के नाम' शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की।
2. उन पर लाहौर षडयंत्र केस का मुकदमा चलाया गया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

Q30. गिलगित पांडुलिपियों (Gilgit manuscripts) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसमें विहित और गैर-विहित केवल बौद्ध कार्य शामिल हैं।
2. इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

Q31. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी स्थापना 1953 में हुई थी।
2. यह एक संवैधानिक संस्था है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

32. भारतीय खाद्य निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है।
2. खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखना इसके कार्यों में से एक है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

33. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह निःसंतान दम्पत्तियों को माता-पिता बनने में मदद कर सकता है।
2. इससे दोहरे जन्म (multiple births) का खतरा बढ़ सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

34. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. भारत 2020 में IEA का सहयोगी सदस्य बन गया।
2. इसकी स्थापना 1974 में हुई थी।
3. इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें
(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

35. वैश्य भारतीय वैज्ञानिक (VAIBHAV) फ़ेलोशिप कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें।
1. फ़ेलोशिप में फ़ेलोशिप अनुदान (INR 4,00,000 प्रति माह) शामिल होगा।
2. यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन है।
3. यह भारत में भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों का एक सहयोग है।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

36. एन्सेलाडस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. यह बृहस्पति का चंद्रमा है।
2. इसकी खोज जूनो मिशन द्वारा की गई थी।
3. इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के दिग्गजों (गिगेंट्स) में से एक के नाम पर रखा गया था।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

37. नागरिक उड्डयन निदेशालय (DGCA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह विमान दुर्घटनाओं की जांच करता है।
2. इसका मुख्यालय मुंबई में है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

38. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत छह पायदान ऊपर चढ़ गया है।
2. यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q39. आईएनएस कृपाण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह खुकरी श्रेणी की मिसाइल कार्वेट है।
2. यह 25 समुद्री मील से अधिक की गति में सक्षम है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q40. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत ने 1993 के बाद से IMF से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है।
2. इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q41. नोवा काखोव्का बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह काला सागर पर है।
2. यह क्रीमिया प्रायद्वीप और ज़ापोरीज़िया परमाणु संयंत्र को पानी की आपूर्ति करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q42. राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं।
2. इसकी स्थापना 2015 में हुई थी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q43. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह गुजरात के साधु बेट द्वीप (Sadhu Bet island) पर स्थित है।
2. यह माही नदी के तट पर है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(A) केवल 2
(B) 1 और 2 दोनों
(C) न तो 1 न ही 2

44. औरंगजेब की कब्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसमें जटिल और भव्य अलंकरण (lavish embellishments) हैं।
2. औरंगजेब को शेख ज़ैनुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया था।
उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

45. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत IFAD का सदस्य नहीं है।
2. IFAD 1977 में बनाया गया था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q46. एसेक्लोफेनाक (Aceclofenac) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक दर्दनाशक है।
2. अपच और दस्त इसके दुष्प्रभावों में से एक हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q47. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. इसका मुख्यालय मुंबई में है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

48. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन है।
2. इसकी स्थापना 1952 में हुई थी।
3. यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को लागू करता है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

Q49. हिंदूकुश क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया में कहीं और की तुलना में अधिक बर्फ और आइस जमा करता है।
2. इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (Bird Areas-IBA) शामिल हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Q50. एक्स खान क्वेस्ट 2023 (Ex Khaan Quest 2023) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह म्यांमार में आयोजित किया जा रहा है।
2. भारत का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स द्वारा किया जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Key Answers:

1	A	11	A	21	D	31	C	41	B
2	B	12	C	22	A	32	B	42	D
3	A	13	A	23	A	33	C	43	A
4	B	14	D	24	A	34	B	44	A
5	A	15	A	25	D	35	A	45	B
6	D	16	D	26	B	36	C	46	D
7	A	17	A	27	A	37	A	47	A
8	B	18	C	28	B	38	C	48	B
9	D	19	D	29	B	39	D	49	D
Z10	B	20	A	30	D	40	B	50	B